वैश्विक संवाद

9.1

17 भाषाओं में एक वर्ष में 3 अंक

पत्रिका

International Sociological Association

वैश्विक समाजशास्त्र के लिए नई दिशाएं

साड़ी हनाफी

वर्ग एवं असमानता पर शोध

प्रोजेक्ट क्लासेनैनलिस
पाब्लो पेरेज
रोडोल्फो एल्बर्ट
स्वेतलाना यारोशेंको
नगई–लिंग सम
तानिया मरे ली
रूथ पैट्रिक
रिचर्ड योर्क
ब्रेट क्लार्क

वृद्धि पैराडाइम के पश्चात?

जेम्स के गैलब्रेथ
क्लाउस डोरे
एरिक पिनाउल्ट
फेडेरिको डेमेरिया
अन्ना सावे–हरनेक
कोरिन्ना डेंगलर
बारबरा मुरका
गेब्रियल सकेलारिडिस
जार्ज रोजस हर्नांडेज

सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य

एरियल साललेह

दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद

लेना लविनास
गुइलहर्मे लेते गोंक्लेव्स
आइसे बुग्रा
रामिरो सी एच कैगरिसो ब्लैंको
नतालिया टेरेसा बर्टी
जस्टिना कजटा

खुला अनुभाग

> मेरी जहोदा से प्रेरणा लेना
> पुर्तगाल में श्रम सम्बन्ध
> वैश्विक संवाद की बंगाली टीम का परिचय

GD
अंक 9 / क्रमांक 1 / अप्रैल 2019
http://globaldialogue.isa-sociology.org/

> संपादकीय

गत जुलाई, टोरोंटो, कनाडा में आयोजित समाजशास्त्र की XIX आईएसए विश्व कांग्रेस में साड़ी हनाफी को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 2019 का वैश्विक संवाद का यह पहला अंक आईएसए के लिए हनाफी के कार्यकाल के दौरान उनकी सैद्धान्तिक दृष्टि के साथ खुलता है। यहां वे बहुल आधुनिकताओं के युग में बहुलवाद के लिए एक नये पैराडाइम के ईद–गिर्द बातचीत को अग्रेषित करने वाली उत्तर–औपनिवेशी उत्तर–सत्तावादी उपागमों के संयोजन/सम्मिश्रण के लिए तर्क देते हैं।

दुनिया भर में दक्षिणपंथी लोकलुभावनवादी दलों के उभार के साथ, वर्ग पर समाजशास्त्रीय बहस को नई प्रमुखता मिली है। इस अंक का पहला निबंध संग्रह लेटिन अमरीका, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी और दक्षिण पूर्व एशिया में वर्तमान शोध की जांच करने वाले लेखों के साथ दुनियाभर में वर्ग विन्यास और वर्ग संबंधों के प्रश्नों में नवीन रूचि को दर्शाता है। इस शोध के साथ, परिसंवाद निर्धनता और असमानता के उभार के निहितार्थों का अन्वेषण भी करती है।

दशकों से, आर्थिक विकास उत्पन्न करना, अधिकांश आर्थिक गतिविधियों के साथ–साथ नीतिगत पहलों और विद्वतापूर्ण चर्चाओं के केन्द्र में रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, कार्यकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ समाजशास्त्रियों एंव अर्थशास्त्रियों ने भी वृद्धि की सीमाओं पर प्रभावशाली बहस प्रारम्भ की है। वे भविष्य पर और कुछ क्षेत्रों में जीडीपी वृद्धि पर इस एक–तरफा फोकस के पारिस्थितिक एवं सामाजिक रूप से विनाशकारी प्रभावों के साथ स्थायी उच्च वृद्धि दरों के संभावित अंत पर चर्चा करते हैं। अकादमिक और कार्यकर्ता बहस दोनों ही संभावित विकल्पों की और अधिक प्रमुख रूप से "डी ग्रोथ" का विचार, एक अवधारणा जिसे काफी चुनौती दी गई, की जांच करती हैं। द्वितीय निबंध संग्रह के आख्यान वृद्धि के भविष्य और एक संभावित डी ग्रोथ विकल्प के इर्द–गिर्द चर्चाओं को दर्शाते हैं।

समकालीन वैश्विक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, एरियल साललेह अपने सैद्धान्तिक योगदान में तर्क देती हैं कि नया समाजशास्त्रीय विश्लेषण माताओं, कृषकों और संग्रहकर्ताओं को पृथ्वी पर जीवन सक्षम बनाने वाली उनकी भौतिक दक्षता के संदर्भ में एकजुट करता है। पारिस्थितिक नारीवाद के आस–पास की बहसों पर ऐतिहासिक प्रतिबिंब के साथ, वे विवेचना पूर्ण समाजशास्त्र और एक मूर्त भौतिकवाद की धारणा का आह्वान करती हैं।

लेटिन अमरीका की कई वामपंथी सरकारों का अंत दुनिया के अन्य क्षेत्रों में दक्षिणपंथी, कभी–कभी सत्तावादी सरकारों के उभार के साथ मेल खाता है। यहां ब्राजील, कोलम्बिया, तुर्की और पोलैंड के विद्वान दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद के ऐतिहासिक और राजनीतिक विकासक्रम की जांच करते हैं।

इस अंक के खुले अनुभाग में तीन आलेख सम्मिलित हैं : जोहान बाकर, जूलिया हॉफमैन और जार्ज हुबमैन हाल ही में प्रकाशित मेरी जहोदा की डॉक्टरेट थीसिस को प्रस्तुत करते हैं और स्मरण कराते हैं कि समाज वैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से संलग्न नागरिकों के रूप में हम उनके जीवन और कार्य से क्या सीख सकते हैं। एलीसियो इस्टेंक और एंटोनियो कासिमिरो फरेरो हमें सबसे हालिया पोस्ट–ट्रोइका काल के तहत पुर्तगाल के नये राजनैतिक श्रम विन्यास के बारे में अंतदृष्टि प्रदान करते हैं जबकि वैश्विक संवाद की बंगाली टीम स्वयं का और अपने कार्य का परिचय देती है। ■

ब्रिजिट ऑलेनबैकर और **क्लॉस डोरे**,
वैश्विक संवाद के संपादक

- *वैश्विक संवाद* आई.एस.ए वेबसाइट पर 17 भाषाओं में देखा जा सकता है।
- प्रस्तुतियाँ <globaldialogue.isa@gmail.com> पर भेजी जा सकती है।

> संपादक मण्डल

संपादक : ब्रिजिट ऑलेनबॉकर, क्लॉस डोरे

सह-सम्पादक : जोहाना ग्रबनर, क्रिस्टीन शिकर्ट

सहयोगी सम्पादक : अर्पणा सुन्दर

प्रबंधन संपादक : लोला बुसुतिल, अगस्त बागा

सलाहकार : माइकल बुरावे

मीडिया सलाहकार : गुस्तावो तनीगुती

परामर्श संपादक :
साडी हनाफी, ज्योफी प्लीयर्स, फिलोमिन गुतिरेज, एलोइजा मार्टिन, सावाको शिराहेस, इजाबेला बरलिंस्का, तोबा बेन्सकी, चिह–जुए जे चेन, जेन फित्ज, कोइची हासेगावा, हिरोशी इशिदा, ग्रेस खुनो, एलिसन लोकोन्तो, सुसन मेकडेनियल, एलिना ओइनास, लोरा ओसो कैसास, बंडाना पुर्कायस्था, रोहडा रेडॉक, मौनीर सैदानी, आयसे सकतांबर, सेली स्कालोन, नाजानीन शाहरोकनी।

क्षेत्रीय संपादक

अरब दुनिया : साड़ी हनाफी, मौनीर सैदानी।

अर्जेन्टीना : जुआन इग्नासियो पियोवानी, एलेक्जेंड्रा ओतामेंडी, पिलर पी पुइग, मार्टिन उर्टुसन।

बंग्लादेश : हबीबुल हक खोंडकर, हसन महमूद, जुवेल राणा, यूएस रोकेय अख्तर, तूफिका सुल्ताना, असिफ बिन अली, खैरून नाहर, काजी फदिया एशा, हेलल उदीन, मुहिमिन चौधरी, मोहम्मद यूनस अली।

ब्राजील : गुस्तावो तानिगुती एंड्रेजा गली, लुकास अमरल ओलिविरा, बेनो वार्केन, एंजेलो मार्टिन्स जूनियर, दिमित्रे सेर्बोनीनी फर्नाडीस।

फ्राँस/स्पेन : लोला बुसुतिल

भारत : रश्मि जैन, प्रज्ञा शर्मा, निधी बंसल, संदीप मील।

इंडोनेशिया : कमांतो सुनार्तो , हरि नुग्रोहो, लूसिया रतीह, कुसुमादेवी, फिना इट्रियती, इंदेरा रत्ना इरावती पट्टिनसारानी, बेनेडिक्टस हरि जूलियावान, मोहम्मद शोहीबुद्दीन, डोमिंगगस एलसीड ली, एंटोनियस एरियो सेतो हार्डजाना, डायना तेरेसा पाकासी, नुरूल ऐनी, गेगेर रियांतो, आदित्य प्रदान सेतियादी।

ईरान : रेयहाने जावदी, नियाश डॉलाती, सिना बस्तानी, सैयद मोहम्मद मुतालेबी, वाहिद लेन्जानगदे।

जापान : सतोमी यामामोतो, सारा मेहारा, मसातका एगुची, रिहो तनाका, मेरी यायामोतो।

कजाकस्तान : अइगुल जाबिरोवा, बायन स्मागमबेट, आदिल रोदियोनोव, अल्माश त्लेसपयेवा, कुआनिश टेल, अलमागुल मुस्सीना, अकनूर ईमानकुल।

पौलैंड : जेकब बारस्जेवस्की, कतार्जीना देवस्का, एना डुलनी–लेसजस्किंस्का, करजिस्तोफ गुबांस्की, मोनिका हेलक, सारा हरस्जींस्का, जुस्तिना कोसिंस्का, लुक्जा लांगे, इगा लजिंस्का, एडम मुलर, वेरनिका पीक, जोफिया पेन्जा–गेबलर, जोनाथन स्कोविल, मार्जनना स्जेपेपैनक, एग्निजका स्जिपुल्स्का, अन्ना टोमला, मातुसुज वोजदा।

रोमानिया : कोसिमा रूधिनिस, राइसा–गेब्रियला जमीफिरेस्कू, लुसियाना एनास्तोसोई, कोस्टीनल अनुदा, मारिया लोर्डाना अर्सने, डायना एलेक्सेंड्रा डुमित्रेस्कु, राडू डुमिस्ट्रेस्कू, युलिआन गेबर, डैन गिओर्टमैन, एलेक्सांड्रा इरिमि–एना, इयूलिया जुगानारू, इयाना मोलुरेनु, बियांका मिहायला, एंड्रिया ऐलेना मोल्दोवीनु, रासेस–मिहाई मुसत, ओना–एलेना नेग्रिया, मिओआरा पराशिव, एलिना क्रिस्टीना पॉन, कोद्रुत पिनजारू, सुसाना मरिया पोपा, एड्रियाना सोहोदोलानु, एलेना ट्युडर।

रूस : ऐलेना ज्द्रावोम्यस्लोवा, अनास्तासिया दौर, वेलेंटीना इसाऐवा।

ताईवान : जिंग–माओ हो।

तुर्की : गुल कोरबासियोग्लू, इरमक एवरेन।

अपने *कार्ययोजना सम्बन्धी लेख में साड़ी हनाफी, आईएसए के नवीन अध्यक्ष, आने वाले वर्षों के लिए आईएसए के लिए अपनी दृष्टि पर चर्चा करते हैं। वे वैश्विक स्तर पर "संवाद में समाजशास्त्र" को मजबूत करने के लिए बहुलवाद के प्रतिमान का आह्वान करते हैं।*

आर्थिक वृद्धि *पश्चिमी समाजों में समृद्धि के आधार का निर्माण करती है लेकिन माल का हरदम–बढ़ता उत्पादन पृथ्वी के पारिस्थितिक विनाश को बढ़ाता है। यहां दुनिया भर से लेखक–समाज में आर्थिक वृद्धि की भूमिका, उसकी समस्याओं एवं चुनौतियों के साथ इस पैराडाइम के परे वैकल्पिक दृष्टि पर चर्चा करते हैं।*

लेटिन अमरीका की कई वामपंथी सरकारों का अंत दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में अक्सर सत्तावादी और लोकलुभावन प्रवृत्तियों के साथ दक्षिणपंथी सरकारों के उभार के साथ हुआ है। इस खण्ड में ब्राजील, कोलोम्बिया, तुर्की और पोलैंड के विद्वान ***दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद*** *के ऐतिहासिक और राजनीतिक विकास की जांच करते हैं।*

GD

सेज प्रकाशन की उदार ग्रांट से
वैश्विक संवाद का प्रकाशन संभव है।

> इस अंक में

संपादकीय 2

> समाजशास्त्र के बारे में बातचीत

वैश्विक समाजशास्त्र – नई दिशाओं की तरफ
साड़ी हनाफी, लेबनान द्वारा 5

> वर्ग और समानता पर शोध

वर्ग पर वैश्विक संवाद के लिए
प्रोजेक्ट क्लासेनैनलिस, जर्मनी द्वारा 8

लेटिन अमरीका में वर्ग और वर्ग हित
पाब्लो पेरेज, चिली और रोडोल्फो एल्बर्ट, अर्जेन्टीना द्वारा 10

समाजवाद–पश्च रूस में निर्धनता और सामाजिक अपवर्जन
स्वेतलाना यारोशेंको, रूस द्वारा 12

चीन में लम्पनप्रोलिटेरियेट एवं नगरीय दलित
न्गई–लिंग सुम, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 14

वर्ग–विन्यास और कृषि पूंजीवाद
तानिया मरे ली, कनाडा द्वारा 16

यूके में कल्याणकारी सुधार के साथ रहना (और प्रतिरोध करना)
रूथ पेट्रिक, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 18

वर्ग एवं पारिस्थितिकी
रिचर्ड लॉर्क, यूएसए द्वारा 20

> वृद्धि पैराडाइम के बाद?

चोक–चेन प्रभाव: तीव्र वृद्धि के परे पूंजीवाद
जेम्स के. गैलब्रेथ, यूएसए एवं क्लॉस डोरे, जर्मनी द्वारा 23

वृद्धि–पश्चात की स्थिति
एरिक पिनाउल्ट, कनाडा द्वारा 25

डी ग्रोथ : कट्टरपंथी सामाजिक–पारिस्थितिक
रूपांतरण का आह्वान
फेडरिको डेमारिया, स्पेन द्वारा 27

नारीवाद और डी ग्रोथ : गठबंधन या बुनियादी संबंध?
एन्ना सावे–हरनेक एवं कोरिन्ना डेंगलर, जर्मनी और बारबरा मुरका, यूएसए द्वारा 29

डी ग्रोथ रणनीति के लिए चुनौतियां: ग्रीस का मामला
गेब्रियल सकेलारिडिस, ग्रीस द्वारा 31

चिली : नवउदारवार से पोस्ट ग्रोथ समाज तक
जॉर्ज रोजस हर्नांडेज, चिली द्वारा 33

> सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य

एक नये वर्ग विश्लेषण के रूप में पारिस्थितिक–नारीवादी समाजशास्त्र
एरियल सालेह, ऑस्ट्रेलिया द्वारा 35

> दक्षिणपंथी लोकवाद का वैश्विक उभार

ब्राजील 2018: मध्यम वर्ग का दक्षिणपंथ की तरफ झुकाव
लेना लवीनास एंव गुइलहर्मे लेइट गोंकोल्वेस, ब्राजील द्वारा 38

लोकवाद, पहचान और बाजार
आयसे बुग्रा, तुर्की द्वारा 40

लेटिन अमरीका में दक्षिणपंथी लोकवाद:
समाज कल्याण के ऊपर निजी–स्वार्थ
रामिरो कार्लोस हम्बर्टो कैगनिजो ब्लैंको, ब्राजील एवं नतालिया टेरेसा बर्टी, कोलंबिया द्वारा 42

पोलैंड में एक नई प्रति–संस्कृति के रूप में कट्टरपंथी राष्ट्रवाद
जस्टिना कज्टा, पोलैंड द्वारा 44

> खुला अनुभाग

मेरी जहोदा से प्रेरणा लेना
जोहान बाकर, जूलिया हॉफमैन एवं जार्ज हुबमैन, आस्ट्रिया द्वारा 47

पुर्तगाल में श्रम सम्बन्ध और सामाजिक संवाद
एलिसियो एस्टांक एवं एन्टोनियो कासिमिरो फेरेरा, पुर्तगाल द्वारा 49

वैश्विक संवाद की बंगाली टीम का परिचय 51

> “यह बहुत महत्वूपर्ण है कि समाजशास्त्र में कुछ अवधरणाएं मानवाधिकार की भांति सार्वभौमिकता का दावा करती हैं, लेकिन मैं उनकी सार्वभौमिकता को केवल एक अतिव्यापी सांस्कृतिक–पार सर्वसम्मति के माध्यम से संभव होता देखता हूं न कि यूरो–अमेरिकी संदर्भों से आने वाले मूल्यों को सार्वभौमिक बनाने से।”

साड़ी हनाफी

> वैश्विक समाजशास्त्र : नई दिशाओं की ओर

साड़ी हनाफी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत, लेबनान और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ (2018-2022) द्वारा

साड़ी हनाफी, अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ के अध्यक्ष

जुलाई 2018 में टोरंटो में अंतराष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ (आईएसए) की कांग्रेस के दौरान इसके अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने से मैं गौरान्वित हूं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में, मैं इस पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में दिये गये भाषण में रेखांकित प्रोगाम की रूपरेखा प्रस्तुत करना और एक उत्तर–सत्तावादी दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता सिद्धान्त के वर्तमान संकट की तरफ अग्रसर, संवाद में समाजशास्त्र से सम्बन्धित तीन बिन्दु एजेंडे को उजागर करना चाहूंगा।

> संवाद में समाजशास्त्र

बीस निर्वाचित आईएसए अध्यक्षों में से, केवल दो यूरोप और उत्तर अमरीका के बाहर से आये थे और मैं तीसरा हूं। मैं समाजशास्त्र के प्रति विशिष्ट संवेदनाओं के साथ आया हूं जो मेरे निजी और व्यावसायिक जीवन के प्रक्षेपवक्र से प्रभावित हैं – एक ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालयी अध्ययन सीरिया में और फिर फ्रांस में किया हो एवं मिस्र, फिलिस्तीन, फ्रांस और लेबनान में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में काम किया हो। अतः मैं इन विन्यासों में असंख्य बहस से घिरा हुआ हूं।

चूंकि मैं विरोधी युग्म श्रेणियों (जैसे परम्परा/आधुनिकता, पूर्व/पश्चिम, सार्वभौमिकता/संदर्भवाद इत्यादि) से सावधान (बहुत सावधान) हूं, मैं विभिन्न समाजशास्त्रों को हमेशा संवाद में रहने का प्रस्ताव देता हूं। संवाद में समाजशास्त्र असल में राष्ट्रीय संघों की परिषद के चतुर्थ आईएसए संगोष्ठी का शीर्षक था और चिन–चुन यी और मेरे द्वारा सह–संपादित आगामी पुस्तक, जिसका प्रकाशन सेज द्वारा किया जा रहा है, का शीर्षक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र की कुछ अवधारणाएं, मानवाधिकार की तरह, सार्वभौमिकता का दावा करती हैं लेकिन मैं उनकी सार्वभौमिकता को केवल एक अतिव्यापी सांस्कृतिक–पार आने वाले सर्वसम्मति के माध्यम से संभव होता देखता हूं, न कि यूरो–अमरीकी संदर्भ से मूल्यों को सार्वभौम बनाने से। मैं लोकतंत्र की अवधारणा का उदाहरण देता हूं। क्या लोकतंत्र सार्वभौमिक है? हां, वह है लेकिन फ्लोरेंट गेनार्ड (2016) को प्रतिध्वनित करते हुए न तो निर्यात किये जाने वाले मॉडल के रूप में, न ही उत्तमता के साथ एक अवधारणा के रूप में, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक अनुभव के रूप में जिसे विशेष रूप में 1980 के दशक के बाद लेटिन अमरीका, फिर पूर्वी और मध्य यूरोप और अंत में अरब दुनिया के कुछ देशों में अपने विस्तार से मानकता मिली। इस प्रकार जो सार्वभौमिक है, वह लोकतंत्र की इच्छा की कल्पना है जिसके निशान प्रदर्शनकारियों द्वारा स्वतन्त्रता, न्याय और गरिमा के बारे में लगाये जाने वाले नारों में पाये जाते हैं। यह आदर्शात्मक सार्वभौमिकतावाद हल्की है और 2016 में आर्मेंडो सल्वाटोर द्वारा वर्णित "नागरिकता के विभिन्न पैटर्न" के अस्तित्व को प्रतिबन्धित नहीं करती है।

हालांकि, चूंकि हम इस बहस को केवल औपनिवेशिक स्थिति और पश्चिमी ज्ञान उत्पादन आधिपत्य से मुक्ति के रूप में नहीं फ्रेम करना चाहते हैं, उत्तर–औपनिवेशिक दृष्टिकोण ज्ञान उत्पादन की समस्याओं का लेखा–जोखा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे, मैं जिसे "पश्च–सत्तावादी दृष्टिकोण" कहता हूं से पूरक किया जाना

>>

चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें न सिर्फ उपनिवेशवाद के प्रभाव का अपितु स्थानीय सत्तावाद के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए।

> पश्च–सत्तावादी दृष्टिकोण की ओर

हमें औपनिवेशिक काल के आघात के घावों को स्वीकार करना ही होगा। वे अभी भी उपस्थित हैं; वे कुछ को अपंग करते हैं और अन्य को उन मार्गों का स्मरण कराते हैं जिन पर हम दुबारा चलने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर–औपनिवेशिक अध्ययन, जो बाह्यकारकों पर अत्यधिक जोर देते हैं और स्थानीय की उपेक्षा करते हैं, का उपयोग और दुरूपयोग दोनों किया जा सकता है। पश्च–सत्तावादी अध्ययनों का उत्तर औपनिवेशिक अध्ययनों के साथ शाब्दिक नातेदारी का अर्थ है कि संगत द्वारा पूर्ववर्ती परवर्ती श्रेणी को रेखांकित करने वाली कई मान्यताओं को आकर्षित कर सकता है, खासकर शक्ति संरचनाओं के संदर्भ में। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने सत्तावाद से समझौता कर लिया, न यह कि हम इस युग के "पश्च" में हैं।

हमारी समझ में सत्तावाद राज्यों द्वारा सामाजिक जीवन में अधिकारी तंत्र एवं पुलिस की बाध्यता को तैनात कर अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं है। इस अधिक वर्णनात्मक प्रतिपादन में, सभी राज्य कुछ हद तक अधिनायकवादी हैं। यह वह राज्य नहीं है जहां संप्रभु कार्ल शमित की अपवाद की स्थिति को काम में लेते हैं। हम जानते हैं कि सभी राज्यों में अपवाद एवं सत्तावादी व्यवहार के "क्षण" या प्रवृत्तियां होती हैं। अपितु सत्तावाद राज्य के निर्णयों में लोकप्रिय जवाबदेही या भागीदारी के व्यवस्थित बेदखली और जैसा ग्राहम हैरीसन ने 2018 में कहा, अफसरशाही में कार्यकारी शक्ति का पर्याप्त केन्द्रीकरण है।

सत्तावाद के विभिन्न स्तर हैं : एक शासन से सम्बन्धित है; दूसरा राजनीतिक – आर्थिक प्रणाली से; और तीसरा व्यक्ति के स्तर पर है।

> क्रूरतापूर्ण सत्तावाद

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिविलाइजिंग प्रोसेस में नॉर्बर्ट एलियास का प्रमुख विचार था कि समाज वैयक्तिक हिंसा के प्रतिगमन (व्यवहारों का शमन) के माध्यम से विकसित होते हैं। यद्यपि, हम इन दिनों, जिसे जोसेफा लारेच ने 2017 में "दमित की वापसी" कहा था या जिसे जार्ज मोसेस ने 1991 में इस सभ्यतागत आंदोलन के क्षरण को उजागर करने के लिये "क्रूरता" कहा, के गवाह हैं। यदि पुलिस और सेना तंत्र के माध्यम से समाज के क्रूरकरण में राज्य के कर्ता प्रमुख खिलाड़ी हैं, हम गैर–राज्य कर्ताओं की बढ़ती शक्ति के भी गवाह हैं। सिरिया और लेबनान में रह चुकने के कारण, मेरे लिए आईएसआईएस और दूसरे सम्प्रदायवादी और अंतरालीय कर्ता जो सामुदायिक एकजुटता को फैलाकर राज्य को दरकिनार करते हैं, इसका एक उदाहरण हैं। लेकिन किसी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों एंव वित्तीय बाजारों जैसे वैश्विक गैर–राज्य कर्ता, जिन्हें 1990 में जेम्स रोसेनौ ने "सम्प्रभुता–मुक्त कर्ता" कहा, के बारे में भी सोचना चाहिए। हालांकि, गैर–राज्य कर्ता विरले ही राज्य कर्ताओं की सहमति और सहूलियत के बिना काम करते हैं। सीरियाई कुलीन वर्ग या अत्यधिक साम्प्रदायिक इराकी शासन द्वारा राजनीतिक स्पेस को पूर्णतया बंद किये बिना आईएसआईएस संभव नहीं था। राज्य और गैर–राज्य कर्ता न सिर्फ समाज का क्रूरकरण करते हैं, वे दुनिया के क्रूरकरण, जिसके आज हम गवाह और हितधारक हैं, को भी बढ़ावा देते हैं। इससे भी बदतर, जैसा सिरिया, लीबिया और यमन में हुआ, युद्ध "राजनीतिक के क्रूरकरण" को पैदा करता है जिसका अर्थ है हिंसा के बिना राजनीति कठिन हो जाती है।

लारोचे के अनुसार, क्रूरता की यह प्रक्रिया सामाजिक बंधनों और एकजुटता के विनाश के साथ प्रारम्भ हो कर राष्ट्रीय समुदाय से निर्धन लोगों और विदेशी समूहों के अन्यकरण और अपवर्जन की तरफ बढ़ती है और इस तरह वह उनके विरूद्ध एवं दैनिक बर्बरता, जो अंततः समाज में सामान्यीकृत हो जाती है, को सबल करती है।

> नवउदार सत्तावाद

आर्थिक और राजनैतिक की अर्न्तक्रिया एक अजीबोगरीब राजनीतिक–आर्थिक विन्यास के उद्भव की तरफ ले जाती है जिसे मैं नवउदार सत्तावाद की संज्ञा देता हूं। हालांकि, यह नया विन्यास महज एक सम्मिश्रण का परिणाम नहीं है बल्कि एक ऐसी मुखरता का परिणाम है जो कई मायनों में नवउदारवाद और सत्तावादी शासन दोनों को बदल देती है।

हम जानते हैं कि नवउदारवाद ने व्यापक सामाजिक और आर्थिक अन्याय और दरिद्रता को उपजा है। हालांकि, उन समाजों में जहां पूंजीपति वर्ग प्रभावी न होकर कमजोर है, पूंजीवादी परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए राज्य की केन्द्रीकृत और बाध्यकारी शक्ति की व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण तैनाती काफी नई है। यदि पारंपरिक पूंजीवादी समाज ने अक्सर एक लोकतांत्रिक राजनीतिक शासन के माध्यम से प्रभुत्व की व्यवस्था को उत्पन्न किया है, कई परिधीय समाजों और उन पश्चिमी देशों में जहां पूंजीपति वर्ग कमजोर और काफी विवादास्पद है, यह मामला नहीं है। राज्य को रेखांकित करने वाली सामाजिक ताकतों के सम्बन्ध न सिर्फ वर्ग, जैसा निकोस पोलांट्जस ने तर्क दिया, द्वारा आकारित होते हैं बल्कि इनमें नस्लीय ओर लिंगीय पदानुक्रम भी सम्मिलित है। ये पदानुक्रम उन प्रक्रियाओं द्वारा आकारित होते हैं जिन्हें अनीबल क्विजानों ने सत्ता की औपनिवेशिकता कहा है, जो समय और स्थान पर भिन्न तरीकों से मुखर होते हैं।

> सत्तावादी नागरिक

राज्य कर्त्ताओं और गैर–राज्य कर्त्ताओं द्वारा तैनात राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, सत्तावाद सत्तावादी नागरिकों के साथ सहसंबंध में मौजूद है। सत्तावादी नेता कल्पना का गला घोंटते हैं : वे ग्रे तंत्रमानव की तलाश करते हैं जो स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले स्वायत्त विषयों की बजाय उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक सत्तावादी नागरिक बनने की प्रक्रिया न सिर्फ उपर से धकेली जाती है बल्कि वह व्यावहारिक तर्क के सम्बन्ध में निर्मित होती है।

मेव कुक के अनुसार, सत्तावादी व्यावहारिक तर्क के दो अन्तः संबंधित घटक हैं। पहला, ज्ञान की आधिकारिक अवधारणाएं है। ये विशेषाधिकार प्राप्त समूह के लोगों तक ज्ञान की पहुंच की सीमित करती हैं और इतिहास संदर्भ के प्रभावों से दूर उन दृष्टिकोणों का दावा करती हैं जो सत्य और सच्चरित्रता के दावों को बिना शर्त वैधता की गारंटी देते हैं। दूसरा, न्यायसंगति की सत्तावादी अवधारणाएं हैं जो प्राक्कथनों और मानदंड़ो की वैधता को मानव की तार्किकता, जिसके लिए उन्हें वैध घोषित किया जाता है, से विभाजित करती है।

कुछ लोग, विशेष रूप से धार्मिक या वे जो सत्तावादी

>>

व्यावहारिक तर्क के इन दो घटकों में से एक को साझा करते हैं, के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में बहस करना कठिन है। चूंकि नागरिक की धारणा में प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक स्वायत्तता निहित है, मेव कुक तर्क देती हैं कि नागरिकों की नैतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। यह स्वायत्तता उस अंतर्ज्ञान पर टिकी हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर मनुष्यों की स्वतन्त्रता में उन कारणों, जिन्हें वे स्वयं का कहते हैं, के आधार पर अच्छे की अपनी धारणा को बनाने और आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता का समावेश है। अरब दुनिया में क्रांति और प्रतिक्रान्ति की प्रक्रियाओं में और लोकतांत्रिक ताकतों की पहचान करने वाली बहसों में, कुलीन वर्ग के व्यावहारिक तर्क पर कम ही ध्यान दिया जाता हे। अधिकांश बल धर्मनिरपेक्षता के प्रतिमान पर होता है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को सत्तावादी व्यावहारिक तर्क के प्रति व्यवस्थित रूप से निरापदीय माना गया जबकि पारिभाषिक तौर पर राजनीतिक इस्लामिक आंदोलन इस तरह के तर्क के साथ संचालित होते हैं। बेशक, यह सरल व्याख्या है और इसकी जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्तावादी नागरिक इन दोनों कुलीन संरचनाओं में पाये जा सकते हैं। इस कारण मैं यह तर्क देती हूं कि धर्मनिरपेक्षता सिद्धान्त वास्तविक संकट में है, और वह धर्म के साथ नागरिकों के सम्बन्धों के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है।

> धर्मनिरपेक्षता सिद्धान्त में संकट

जहां धर्मनिरपेक्षता अभी भी लोकतंत्र और आधुनिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग है, इस प्रक्रिया को इसकी कुछ अतिरेकता ओर विकृतियों से मुक्त करने के लिए पश्च–धर्मनिरपेक्ष आधार पर समस्याग्रस्त होने की आवश्यकता है। धर्म के समाजशास्त्र पर आईएसए शोध समिति (आरसी 22) के अध्यक्ष, जिम स्पिकार्ड के साथ हाल ही में हुई बातचीत में, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐतिहासिक तौर पर समाजशास्त्र ने धर्मनिरपेक्षता सिद्धान्त को अपनाया है जिसे डेविड मार्टिन, मेनुअल वास्क्यूज एवं वे स्वयं जैसे समाजशास्त्रियों ने उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के प्रारम्भिक दशकों के फ्रांस में प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा प्रतिक्रियावादी धर्म के खिलाफ बौद्धिक युद्ध में ट्रेस किया है। पीटर बर्जर के लिए, यह सिद्धान्त, जिसने आधुनिकता को धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी माना, को आनुभाविक रूप से झुठला दिया गया है और इसे बहुवाद के सूक्ष्म भेदी सिद्धान्त से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। वह उद्विकासवाद जो धर्म को "अतीत" एवं समाजशास्त्र को "भविष्य" के रूप में चिन्हित करता है, उसने हमारी सोच में धर्मनिरपेक्षता थीसिस को अंतःस्थापित किया है। परिणामस्वरूप, 1980 और 1990 के दशकों में धर्म के सार्वजनिक पुनरूत्थान को शीघ्रता से "कट्टरपंथी" और "आधुनिकता के खिलाफ प्रतिक्रिया" के रूप में चिन्हित किया। उलरिके पोप–बेयर के अनुसार यह उभरती बहस तीन आदर्श लाक्षणिक मेटा–नैरेटिव से फ्रेम हुई है। पहला वैज्ञानिक विश्वदृष्टि के प्रसार के कारण धार्मिक सम्बद्धताओं, प्रथाओं और विश्वासों के पतन का वृत्तान्त है। दूसरा रूपांतरण का वृत्तान्त है जिसमें "अदृश्य धर्म", "निहित धर्म", बिना सम्बद्धता के विश्वास", "प्रतिनिधिक धर्म", "धर्म का न्यायिकरण" और हालिया वर्षों में प्रमुखता से बढ़ती "आध्यात्मिकता", के बारे में तर्क सम्मिलित हैं जो वैयक्तिकरण और विषयीकरण से सम्बन्धित अधिक सामान्य सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में धर्म के सामाजिक स्वरूप के कायान्तरण का सुझाव देते है। तीसरा उभार का वृत्तान्त है जो धार्मिक जीवंतता को धार्मिक बहुलता और प्रतिस्पर्धी धार्मिक संगठनों के साथ जोड़ता है; इस्लाम के मामले में, यह उभार कट्टरवाद से और आतंकवाद से भी सम्बद्ध है।

हमें विभिन्न बौद्धिक परम्पराओं, लोकप्रिय धर्मी और संस्थागत वाहकों, जिन्होंने समकालीन समाज में धर्म और धार्मिकता के विभिन्न स्वरूपों को उत्पन्न किया है, का विश्लेषण करने हेतु कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष के रूप में लेबल करने वाले कई रूढोक्तियों के परे जाने की आवश्यकता है। समाजशास्त्रीय बहस में, लोकतंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म के स्थान पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। जैसा जॉन राल्स करते हैं, वैसे नागरिकों से अपने धार्मिक विश्वास से स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिबद्धता को उचित सिद्ध करने की नैतिक जिम्मेदारी रखने को नहीं कहा जा सकता है। हेबरमास के बहुलवाद में भी, रॉल्स सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म के स्थान को स्वीकार करते हैं और बहस करते हैं कि धार्मिक समुदायों को अन्य धर्मों एवं विश्वदृष्टि के दावों की तरफ, धर्मनिरपेक्ष ज्ञान विशेष रूप से वैज्ञानिक दक्षता की ओर एवं राजनीतिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष कारणों की प्राथमिकता की ओर ज्ञानात्मक स्थिति को विकसित करेन के लिए व्याख्यात्मक आत्म–चिंतन से संलग्न होना होगा। परन्तु क्या "धार्मिक" कारणों से "धर्मनिरपेक्ष" को अलग कर पाना वास्तव में सम्भव है? डैरेन वाल्ह (2013) जैसे विद्वानों का कहना है कि "धर्मशास्त्र, राजनीति और एक धार्मिक समुदाय की पहचान एक दूसरे के साथ गुथी है, चूंकि धार्मिक नेता एवं नागरिक नवीन राजनीतिक संदर्भों में अपने धर्मशास्त्रों को लागू करते हैं और पुनः निरूपित करते हैं।

यद्यपि कानून, धर्म, राजनीति और समाज के संगम के कई समस्यात्मक परिणाम हुए है जैसे संप्रदायवाद। मध्य–पूर्व जैसे संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में, संप्रदायवाद एक प्रमुख संघर्ष गतिकी है लेकिन यह जिसे आजमी विशारा ने 2017 में "कल्पित संप्रदाय" कहा, के द्वारा स्थानीय पहचान को आकार देने का एक तंत्र भी है। इसी तर्क से, इजराइल ने हाल ही में एक कानून पारित किया जो यह घोषणा करता है कि यहूदियों को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय करने का एक अनूठा अधिकार है जबकि वह इजराइल और फिलीस्तीनी क्षेत्रों में अपनी रंगभेद की राजनीति को बनाये रखता है।

> निष्कर्ष

"अनुदार लोकतंत्रों" में और कुछ अच्छी तरह से स्थापित लोकतंत्रों द्वारा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर हमलों में वृद्धि के साथ, आईएसए को आज दुनिया भर के इतने सारे लोगों की आशंकाओं और भावनाओं को पकड़ना चाहिए। हन्नाह अरेंड्ट ने अधिनायकवाद की उत्पत्ति बाह्य कारकों (साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों का संकट) और आंतरिक कारकों (यहूदी–विरोधीवाद और नस्लवाद) के संयोजन में स्थित की है।

इसी रूप में मेरा मानना है आईएसए को उपनिवेशवाद और सत्तावाद के विश्लेषण को मिलाने की जरूरत है। इसे बहुल आधुनिकता के युग में धर्म और बहुलवाद के लिए नवीन प्रतिमान के ईद–गिर्द वार्ता का नेतृत्व करना चाहिए। ऐसा सूक्ष्म और स्थूल आयामों के मिश्रण, जो आज की वैश्विक स्थिति की विशेषता को दर्शाते हैं, को समझने के लिए एक अधिक उपयुक्त फ्रेमवर्क का निर्माण करने के द्वारा ही और अलातस और सिन्हा की २०१७ की पुस्तक के शीर्षक "सोशियोलोजिकल थ्योरी बियोंड द कैनन" के समान निर्मित करके संभव है। ■

सभी पत्राचार साड़ी हनाफी को <sh41@aub.edu.lb> पर प्रेषित करें।

> वर्ग पर वैश्विक संवाद के लिए

प्रोजेक्ट क्लासेनैनलिस जेना (पीकेजे), जेना विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा

> हमें वर्ग सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों है : साथियों की तलाश में पीकेजे

वर्तमान में हम दुनिया भर में तीव्र होती सामाजिक विषमताओं और बढ़ते सामाजिक प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी संकट की तरफ अधोमुख है। यह पूंजीवादी केन्द्रों पर भी लागू होता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2017 में 17 फीसदी जर्मन आबादी निर्धनता या सामाजिक बहिष्कार से संकट में थी; अन्य अध्ययन भी बढ़ते हुए सामाजिक ध्रुवीकरण के दर्शाते हैं। इस बीच, दुनिया के बड़े हिस्से राजनीतिक दक्षिणपंथ की तरफ झुकाव को अनुभव कर रहे हैं। इन रूझानों के ओजस में, हम देखते हैं कि "वर्ग" सम्बोध, जो–कम से कम जर्मनी में हाल के दशकों में सार्वजनिक बहस से पूरी तरह से अनुपस्थित था, धीरे–धीरे शैक्षणिक और राजनीतिक विमर्श में लौट रहा है। "प्रोजेक्ट क्लासेनैनलिस जेना" हाल ही में फ्रेडरिख शिलर विश्वविद्यालय, जेना में प्रारम्भ किया गया। हम वर्ग से सम्बन्धित पूर्व की चर्चाओं को पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं, समकालीन वर्ग सिद्धान्त में योगदान और वर्तमान वर्ग राजनीति पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसमें हम दुनिया भर के शिक्षाविदों और कार्यकर्त्ताओं के साथ वार्तालाप प्रारम्भ करना चाहते हैं।

> "वर्ग" के बारे में बात क्यों करें?

वर्ग की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की ताकत है कि वे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक असमानताओं के मध्य आंतरिक संबंधों पर फोकस करती हैं। मार्क्सवाद परम्परा में "वर्ग' शब्द की आलोचनात्मक क्षमता यह है कि वह श्रम के आर्थिक विभाजन और उसके स्वामित्व संरचनाओं में निहित शक्ति और नियंत्रण की संरचनाओं को उजागर करती है। अतः मार्क्स के लिए, वर्ग एक संबंधात्मक श्रेणी है : वेतनभोगी कर्मचारियों का वर्ग पूंजीपतियों के वर्ग के प्रति विरोधी और संघर्षपूर्ण संबंध में खड़ा होता है। "परिवेश" या स्तरीकरण दृष्टिकोणों (उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, कामगार वर्ग इत्यादि) के विपरीत, मार्क्सवादी परंपरा में "वर्ग" शब्द एक संरचनात्मक संबंध जो सिर्फ आर्थिक असमानताओं का वर्णन करने के बजाय सामाजिक समूहों की एक–दूसरे की कामकाजी और रहवास की स्थितियों के साथ संबंधित हो सकता है। "शोषण" (मार्क्स), सामाजिक समापन (वेबर), 'प्रमुखत्व' (बोर्दयू) और "अफसरशाही नियन्त्रण" (राइट) की अवधारणाओं के द्वारा "वर्ग" सम्बोध मुख्य रूप से असमानता की ऊर्ध्वाधर संबंधों के बारे में उल्लेख करता है और यदि शक्ति संबंधों की तरफ इशारा करता है तो यह राजनीतिक सम्बोध के साथ सामाजिक सिद्धान्त की अवधारणा भी है। इसमें राजनीतिक आधिपत्य और प्रतिनिधित्व के साथ वर्ग सम्बन्धों के सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रसंस्करण के कथात्मक पूर्वापेक्षाओं के प्रश्न भी सम्मिलित हैं।

> नई चुनौतियां

नई चुनौतियों और गतिशील एवं हानिकारक सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, एक समकालीन वर्ग सिद्धान्त को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों एवं मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होगी :

वर्ग विखण्डन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट

दुनिया भर की आबादी की रहवास स्थितियों पर नवउदारवाद द्वारा छोड़े गये स्थायी निशान वर्ग विश्लेषण के लिए बड़ी चुनौती पैदा करते हैं। कामकाजी परिस्थितियों और उत्पादन के संबंधों के विखण्डन ने मजदूर वर्ग में और अंतर कर दिया है और उनके भीतर व्यापक विविधता पैदा कर दी है। यह घटनाक्रम एक ओर तो एक छोटे उच्च वर्ग के पक्ष में धन की सकेन्द्रता में वृद्धि के साथ "नये खतरनाक वर्गों" के उभरने (गॉय स्टैडिंग) और मध्यम वर्गों के मध्य विभाजन के साथ चलता हे। यह वह उपजाऊ जमीन है जिस पर सामाजिक विभाजन ओर दक्षिणपंथी लोकप्रियता की विचारधाराएं पनपती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और रोजमर्रा के राजनीतिक जीवन में वर्ग एकता परिपेक्ष्य का लोप होना एक "विघटित वर्ग समाज" (क्लॉस डोरे) की तरफ इशारा करता है, जहां वर्ग सम्बन्धित गतिशीलता सामाजिक विमर्श की सतह के नीचे काम करना जारी रखती है जबकि उन्हें राजनीतिक स्पेस में बमुश्किल इस तरह लेबल किया जाता है। वित्तीय पूंजीवाद और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट, वामपंथी दलों और ट्रेड यूनियनों की कमजोरी और रक्षात्मक स्थिति के साथ ही साथ इस कमजोरी के साथ जुड़ी व्यापक सामूहिक चेतना का विलय दक्षिणपंथ की तरफ राजनीतिक झुकाव का मार्ग है। उसी समय, हमने फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस जैसे देशों में वामपंथी बलों एवं संरचनाओं में चढ़ाव देखा है। वैश्विक उत्तर के कई देशों में प्रतिरोध प्रवासन संबंधित मुद्दों पर स्थानांतरित हो गया है। राजनैतिक वामपंथ पर चर्चा अक्सर वर्ग बनाम "पहचान" के गलत विरोधाभास तक सीमित रही है। इस परिस्थिति में उठने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये सम्मिलित हैं :

- आर्थिक संरचनाओं, राजनीतिक चेतना और संस्कृति के मध्य क्या संबंध हैं?
- वर्ग और संघर्ष के अन्य अक्षों (लिंग, प्रवास इत्यादि) के मध्य क्या संबंध है?
- प्रभुत्व वर्गों के भीतर विवर्गीकरण और प्रमुखत्व की क्या भूमिका

>>

“ हम एक वर्ग सिद्धान्त, जो एकल समाजों के विशिष्ट लक्षणों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर की सामान्य प्रवृत्तियों का भी खुलासा करता हो, के लिए वैश्विक आदान–प्रदान का आह्वान करना चाहते हैं ”

होती है? राजनीतिक संगठनों में वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर वर्ग सम्बन्ध कैसे प्रभावी होते हैं?

- एकल समाज के अन्तर्गत और वैश्विक स्तर पर भी कौन से वर्ग गुट हावी हैं ओर वे अपने हितों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं?

वर्ग-विशिष्ट असमानताएं और राष्ट्रपार वर्ग सम्बन्ध

ओईसीडी देश बेरोजगारी, निर्धनता और अनिश्चितता में वृद्धि द्वारा चिन्हित होते हैं। धन और आय में विषमता नाटकीय ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। यह रूझान इस हद तक ठोस होता प्रतीत हो रहा है कि वर्ग–विशेष असमानताएं आगे के आर्थिक विकास के लिए भी बाधा बन रही हैं। इस प्रकार, वे खुद नवउदार वैश्वीकरण के मुख्य राज्यों में राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा खतरा पैदा कर रही हैं। वैश्विक दक्षिण में, वर्ग संघर्ष अक्सर विजातीय और अनौपचारिक आर्थिक संबंधों पर आधारित होते हैं, जिनमें ग्रामीण उत्पादन के नगरीय और ग्रामीण तरीकें की (आंशिक रूप से सह–मौजूद) बहुलता सम्मिलित होती है। इसके अलावा, वि–औद्योगीकरण की प्रवृत्तियां आजकल वैश्विक उत्तर के देशों तक भी पहुंच गई है। इसलिए, हमें पूछना होगा :

- वैश्वीकरण एवं इसके संकटों की पृष्ठभूमि के सम्मुख वर्ग कैसे बनते हैं? राष्ट्र–राज्य क्या भूमिकाएं निभाते हैं? क्या हम ट्रान्सनेशनल वर्गों जैसे किसी का उल्लेख कर सकते हैं?
- किन संघर्षों को वास्तव में “वर्ग संघर्ष” के रूप में और किन्हें ऐसा नहीं देखा जाता है? क्या इन संघर्षों के मध्य वैश्विक समानताएं या संबंध हैं?
- अनौपचारिक आर्थिक संबंधों को देखते हुए, वैश्विक दक्षिण में हम वर्गों और वर्ग संघर्ष का वर्णन कैसे कर सकते हैं?

पारिस्थितिक संकट

वैश्विक पारिस्थितिक संकट के कारण और संभालने के प्रयास वर्ग संबंधों और पूंजी संचय के तर्क के साथ अंतरंगता से जुड़े हैं। आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता लाभ के लिए स्थिर प्रयास अपनी पारिस्थितिक नींव और जैव–भौतिकीय सीमाओं के प्रति उदासीन हैं। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और पारिस्थितिक जोखिमों एवं बोझ का वितरण दोनों ही वर्ग–विशेष रूप से विवादास्पद है। दुनिया भर में निर्धन–विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में : पारिस्थितिक घर्षण का मुख्य बोझ सहन करते हैं। ये सामाजिक–पारिस्थितिक संघर्ष भविष्य में निश्चित रूप से और बढ़ेंगे। एक समकालीन वर्ग सिद्धान्त इन्हें व्यवस्थित रूप से सम्मिलित करने के लिए विवश है :

- वर्ग संघर्षों पर पारिस्थितिक विकृतियों का क्या प्रभाव है?
- पारिस्थितिक बोझ विभिन्न वर्गों को कैसे प्रभावित करते हैं?
- सामाजिक–पारिस्थितिक परिवर्तनों के बारे में किस वर्ग (रैक्शन) को आश्वस्त किया जा सकता है?
- ऐसे परिवर्तनों को कौन से वर्ग हित बाधित करते हैं?

> विनिमय के लिए आह्वान

यह स्पष्ट है कि ऐसे ओर भी प्रश्न हैं जिनको सम्बोधित किया जाना है और उपरोक्त उल्लेखित सभी प्रश्न प्रत्येक राष्ट्रीय संदर्भ से संबंधित नहीं है। वे आज विश्व पूंजीवाद को आकार देने वाली प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं। इसलिए, हम इन मुद्दों पर एक वैश्विक आदान–प्रदान, एक वैश्विक संवाद का निमंत्रण देना चाहते हैं ताकि एक ऐसे वर्ग–सिद्धान्त के मॉडल को बनाया (आगे) जाए जो वैश्विक स्तर पर सामान्य प्रवृत्तियों को प्रकट करते हुए एकल समाजों के विशिष्ट लक्षणों को ध्यान में रखेगा। हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों, सहयोग और आदान–प्रदान के लिए उत्सुक हैं। ■

सभी पत्राचार <projekt.klassenanalyse@uni-jena.de> पर प्रेषित करें।

> लेटिन अमरीका में वर्ग एवं वर्ग हित

पाब्लो पेरेज, सेंटर फॉर सोशल कंफ्लिक्ट एंड कोहेजन स्टडीज एवं यूनिवर्सिडेड अल्बर्टा हर्टाडो, चिली और **रोडोल्फो एल्बर्ट**, कोनिसेट और इस्टीट्यूटो डी इंवेस्टिगेशियन्स गीनो जर्मनी, ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय, अर्जेन्टीना और श्रम आंदोलनों पर आईएसए शोध समिति (आरसी 44) के सदस्य

सैंनटियागो, चिली में 2018 में मई दिवस प्रदर्शन। फोटो : पाब्लो पेरेज।

हाल के दशकों में लैटिन अमरीकी विद्वानों ने कई बार वर्ग की अवधारणा को दफनाने का प्रयास किया है। 1980 के दशक से, कुछ मतभेदों के बावजूद, विद्वानों का मत है कि नवउदार नीतियों ने कामगार वर्गों को इतना दुर्बल कर दिया है कि ये अब लैटिन अमरीकी समाजों में सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की गतिशीलता को प्रभावित नहीं करते हैं। पिछले दशक में, यद्यपि, श्रमिक वर्ग ने कामगार वर्ग की विदाई के इन निमंत्रणों की अनदेखी की। कार्य सम्बन्धित मुद्दों के इर्द–गिर्द यूनियन की गतिविधियों को पुनर्जीवित करना और अन्य लोकप्रिय आंदोलनों के साथ गठबंधन में एक उचित आय वितरण की मांग करते हुए, कुछ देशों में लेटिन अमरीकी श्रमिकों ने जिद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में संघर्ष और राजनीति की व्याख्या करने के लिए वर्ग कारक बना रहता है।

>>

निश्चित रूप से, 2000 के दशक के प्रारम्भ से ही वर्ग की अवधारणा का सामाजिक–आर्थिक असमानता (अर्थात वर्ग गतिशीलता अध्ययन) के मात्रात्मक विश्लेषण और श्रमिकों की सामूहिक कार्यवाही के गुणात्मक अध्ययन के माध्यम से समाजशास्त्रीय एजेंडे में पुनः प्रवेश हुआ है। हमारा कार्य इस व्यापक एजेंडे का हिस्सा है जो व्यक्तिनिष्ठ परिणामों, विशेष तौर पर, विरोधी पहचान एवं हित, को आकारित करने वाले वस्तुनिष्ठ तंत्र के रूप में ध्यान केंद्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण कार्यक्रम के डाटासेट पर आधारित हमारे हालिया शोध ने दर्शाया कि अर्जेन्टीना और चिली में 10 में से 9 व्यक्ति एक सामाजिक वर्ग से आत्म–पहचान प्राप्त करते हैं। एक पुरानी अवधारणा के लिए इतना कुछ! दोनों देशों में कामगार वर्ग की स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग स्थिति वालों की तुलना में स्वयं को श्रमिक के रूप में देखने की अधिक संभावना है। हमने पाया कि अर्जेन्टीना की तुलना में चिली में कामगार वर्ग की पहचान की समग्र दरें अधिक हैं। हम इन परिणामों का चिली में उच्च असमानता और आर्थिक संकेन्द्रकरण और इस देश में ''कट्टरपंथी'' पार्टी संघ विन्यास के इतिहास को अर्जेन्टीना में श्रम के राज्य–निगमीय समावेश की तुलना में देखते हुए विश्लेषण करते हैं।

हम सोचते हैं कि इस तरह का शोध विश्व में सबसे अधिक असमान में रैंक करने वाले क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की समझ में योगदान दे सकता है। वर्ग केवल लेटिन अमरीकियों के सामाजिक संरचना और पहचान में ही मौजूद नहीं है : इसे लोगों के सामाजिक–राजनीतिक हितों को आकार देते हुए भी अवलोकित किया जा सकता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के व्यक्ति वर्ग संदर्भ में दुनिया के बारे में सोचते हैं (शायद कुछ विद्वानों के स्वीकार किये जाने से अधिक), और अपने वर्ग हितों की रक्षा हेतु ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर एवं वोट करने से लेकर यूनियन या पार्टी में शामिल होना जैसे राजनीतिक कार्यों में भाग लेते हैं। इस आधार पर, हमारा नया प्रोजेक्ट वर्ग संरचना, सामूहिक कार्यवाही, और वर्ग हितों के मध्य सम्बन्धों पर केन्द्रित है। हम एरिक ओलिन राइट के काम का अनुसरण करते हैं जो वर्ग चेतना को चेतना के उन पहलुओं के रूप में परिभाषित करते हैं जिनमें वर्ग सामग्री और वर्ग–प्रासंगिक प्रभाव होता है। उनका तर्क है कि विश्लेषण के सूक्ष्म स्तर पर, वर्गीय हितों की व्यक्तिपरक धारणा वर्ग चेतना के मुख्य पहलुओं में से एक है। राइट के मार्क्सवाद प्रेरित फ्रेमवर्क से आकर्षित हो, हम वर्ग हितों की उन तरीकों से जांच करते हैं जिनमें भिन्न वर्गों के लोग पूंजीवादी संस्थाओं और सामाजिक वर्ग की गतिशीलता का विषयपरक मूल्यांकन करते हैं।

हाल का साहित्य दर्शाता है कि श्रमिक–वर्ग के लोगों में पूंजीवाद और असमानता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण होने, वर्ग पर विरोधी विचार रखने, और नियोक्ताओं या प्रबंधकों की तुलना में पुनर्वितरण नीतियों का समर्थन करने की अधिक संभावना है। हमारे प्रारंभिक निष्कर्ष इस साहित्य के अनुरूप है : देशों के मध्य अंतर को अलग कर, श्रमिक वर्ग या अनौपचारिक स्वरोजगार वर्ग स्थान में स्थित लेटिन अमरीकियों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग स्थान में स्थित उत्तरदाताओं (जैसे विशेषज्ञ प्रबंधक) की तुलना में नवउदार संस्थाओं, विचारों, या परिणामों (जैसे उनके आय विषमता या सरकारी हस्तक्षेपों का अभाव की आलोचना करने की संभावना अधिक है) के प्रति आलोचनात्मक रूख होता है।

हमारा वर्तमान कार्य इन निष्कर्षों को सामूहिक कार्यवाही, कैसे लोगों की वर्ग स्थिति द्वारा आकारित भौतिक हितों के बारे में लोगों की समझ को सुदृढ़ करने का एक तंत्र हो सकती है, के अध्ययन द्वारा विस्तारित करना चाहता है। अतः हमारा उद्देश्य वर्ग, सामूहिक कार्यवाही और वर्ग चेतना के मध्य कारकीय सम्बन्धों के कम जाने (परीक्षित) पक्ष के विश्लेषण में योगदान देना है। हमारी परिकल्पना है कि लोकप्रिय कट्टरपंथी लामबंदी के हालिया अनुभव वाले देशों में, अर्थात् उन देशों में जहां श्रमिक वर्ग और लोकप्रिय क्षेत्र वामपंथ के उभार का समर्थन करने वाले मुख्य कर्ता रहे हैं, विवादास्पद राजनीति के न्यून स्तरों वाले देशों या जहां राजनीतिक लामबंदी से श्रमिक वर्ग का अपवर्जन जारी है, की तुलना में वर्ग स्थिति और हितों पर सामूहिक कार्यवाही की भागीदारी का प्रभाव अधिक मजबूत है।

हमारा मानना है कि इन जांचों को विकसित करना इसलिए लाभदायक नहीं है कि इस क्षेत्र में वर्ग ही राजनैतिक सक्रियता का एक मात्र स्रोत है बल्कि इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि लेटिन अमरीका में मुक्तिकरण की संभावनाएं श्रमिक वर्ग की राजनीतिक भागीदारी से निर्धारित होती हैं। इस प्रकार का सक्रियतावाद निश्चित रूप से उत्पीडन के अन्य स्रोतों (और उनके प्रतिच्छेदन) के खिलाफ लामबंदी जैसे अर्जेन्टीना और चिली में गर्भपात के वैधकरण के खिलाफ बड़े पैमाने पर महिला प्रतिरोध, या हाल ही में ब्राजील में एलेनाओं आंदोलन जहां महिलाओं और नस्लीय उत्पीड़ित समूहों ने चरम दक्षिणपंथ के विकास के खिलाफ संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया। ऐतिहासिक संदर्भ में जहां दक्षिण पंथ सत्ता में लौट रहा है, केवल एक सशक्त श्रमिक वर्ग, जो अन्य उत्पीडित समूहों के गठबंधन द्वारा अपने वर्ग हितों की रक्षा करता है, ही नव–फासीवाद को रोकने के लिए मजबूत वामपंथी आंदोलन को विकसित करने में सक्षम होगा। ■

सभी पत्राचार पाब्लो पेरेज को <pperez@uahurtado.cl> पर
और रोडोल्फो एल्बर्ट को <elbert.rodolfo@gmail.com> प्रेषित करें।

> समाजवाद–पश्च रूस में निर्धनता और सामाजिक अपवर्जन

स्वेतलाना यारोशेंको, सेंट पीटर्सबर्ग राज्य विश्वविद्यालय, रूस द्वारा

घर से कार्य करते हुए।
फोटोः सोलमाज गुसेनोवा

मैंने 1990 के दशक, जब उदार बाजार सुधार लागू किये गये थे, के प्रारम्भ से रूस में निर्धनता पर शोध करना शुरू किया। सोवियत वितरण प्रणाली से पूंजीवादी प्रणाली में संक्रमण के दौरान निर्धनता को अतिवादी सामाजिक परिवर्तन की लागत माना जाता था। यह मान लिया गया था कि बाजार के प्रवेश से आर्थिक वृद्धि होगी, निर्धनता घटेगी और लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने व स्वयं को राज्य–समर्थन से मुक्त करने की परिस्थितियां पैदा होंगी।

आशावादी पुर्वानुमानों के विपरीत, और 2000 के दशक के दौरान आर्थिक स्थिरता के बावजूद, रूस में निर्धनता बनी हुई है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, रूस की 11 प्रतिशत से 25 प्रतिशत आबादी की पहचान निर्धन के रूप में की जा सकती है। आधिकारिक रूप से कम निर्धनता दर, 2017 में लगभग 13 प्रतिशत, निर्धनता और जीवनयापन की न्यूनतम लागत की गणना के लिए प्रयोग में लिये गये कृपण तरीकों का परिणाम है, जबकि निम्न बेरोजगारी दर अनौपचारिक और अववैतनिक रोजगार के विस्तार से प्राप्त हुई है। रूस के मुख्य नगरों का त्वरित विस्तार आंतरिक प्रवास, पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों से श्रमिकों के आव्रजन और गैर–महानगरीय क्षेत्रों में निर्धनता के माध्यम से सम्पन्न हुआ है। फिर भी सरकारी विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि केवल 40 प्रतिशत रूसी बाजार अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। यह रूसियों का वही प्रतिशत है जिनकी आय पिछले बीस वर्षों में बढ़ी है जबकि अन्य 60 प्रतिशत की आय समान रही है या काफी सिकुड़ी है। नौकरीपेशा लोग और बच्चों वाले परिवारों में निर्धनता लगातार बनी रही है। रूस का जिनी गुणांक, सामाजिक असमानता में वृद्धि, जो 1991 में 0.26 से बढ़कर 2010 में 0.421 हो गई, से जन्मा है।

कोमी विज्ञान केन्द्र में मेरे सहयोगियों और मैंने 2000 के दशक में रूस के उत्तरी क्षेत्र में पंजीकृत निर्धन लोगों का अनुदैर्ध्य गुणात्मक शोध और शहरी निवासियों का सर्वेक्षण किया। हमने पाया कि सामाजिक अपवर्जन का विस्तार हो रहा था। वर्ग, लिंग और बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं ने निर्धनता की सतात्यता और इसके विशिष्ट लक्षणों में योगदान दिया है। सामाजिक अपवर्जन संस्थागत हो गया है।

अल्पार्जक रोजगार क्षेत्र का विस्तार हुआ है। 1990 के दशक में रोजगार के पहले पुनर्गठन से भारी उद्योग में छंटनी और खुदरा व्यापार और सेवा क्षेत्रों में विस्तार हुआ। ये नई नौकरियां आमतौर पर कम वेतनवाली और न्यूनतम लाभ प्रदान करती थीं। इसके बाद 2000 के दशक में, सार्वजनिक क्षेत्र को अनुकूलित किया गया और गैर–बाजार सेवाएं जैसे शिक्षा एवं चिकित्सा देखभाल सहित सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में कटौती की गई। तदुपरान्त वि–औद्योगीकरण और फिर बाजारी सेवा अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी, यह चर्चा उभरी की कौन से क्षेत्र को बाजार सुधारों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और तदनुसार कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे : अंत्यावसायी या सार्वजनिक क्षेत्र के कामगार। हमने पाया कि अंत्यावसायी न केवल बाजार वस्तुओं के नकारात्मक प्रभावों को अनुभव करने वाले पहले थे अपितु वे अत्यधिक निर्धन में भी सबसे बड़े खण्ड का गठन करते थे।

इसके अलावा, अधिकांश सामाजिक रूप से अपवर्जित रूसी यानी लम्बे समय से अत्यधिक निर्धनता में रहने वाले लोग श्रम बाजार की सीमाओं पर कार्यरत थे। बाजार के लैंगिक प्रभाव भी थे : हमने पाया कि निर्धनता न सिर्फ अत्यधिक स्त्रैण थी जबकि पुरुष व्यापक रूप से निर्धनीकरण से गुजर रहे थे। हमारे आधे मामलों में,

>>

लोगों की आय स्वयं के अलावा किसी अन्य के भरण–पोषण के लिए बहुत कम थीं।

जबकि 2000 के दशक के प्रारंभ में, जितना निम्न एक व्यक्ति का सामाजिक वर्ग था, उतनी ही उनके गरीबी में आने की संभावना उच्च थी। दस वर्ष पश्चात लिंग अब सामाजिक वर्ग पर निर्भर नहीं था : भिन्न सामाजिक वर्गों की एकल माताओं की आर्थिक कठिनाई से पीड़ित होने की संभावना अधिक थी। अन्य शब्दों में, दिहाड़ी श्रमिकों को मौजूदा समाजवाद में मिलने वाले सामाजिक लाभों में कटौती को उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के बढ़ते अवसरों से पूरा नहीं किया गया है। संरचनात्मक बाधाओं का दबाव बढ़ गया है : वर्ग और लिंग समानांतर में संचालित हुए हैं।

जब तक बाजार सम्बन्ध रोजगार (उत्पादन और पुनरूत्पादन) तक विस्तारित हुए, सामाजिक नीति मौलिक रूप से बदल गई। मुक्त बाजार, मौजूदा समाजवाद की असमान आलोचना और सोवियत पितृसत्ता (''अप्रभावी'' और ''अधिनायकवादी'' सोवियत व्यवस्था जिसने राज्य पर निर्भरता की संस्कृति को आकारित किया) से मुक्ति की आवश्यकता पर व्यापक बयानबाजी में विश्वास के मध्य, कल्याण के बुनियादी स्तर को बनाये रखने में राज्य के दायित्वों में वास्तव में कटौती की गई। 1991 के बाद से, रूस में जीवनयापन की न्यूनतम लागत की गणना की विधि को तीन बार संशोधित किया गया और अधिक कठोर बनाया गया एवं न्यूनतम मजदूरी ने वित्तीय सुरक्षा के लिए वास्तविक न्यूनतम के साथ सहसम्बन्ध समाप्त कर दिया है।[1]

इस बीच, सामान्य वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करने के श्रम–आधारित सिद्धान्त को सामाजिक नीति मानदंड के रूप में बनाए रखा गया है, जैसा न्यूनतम मजदूरी, पेंशन और बच्चों के पालन–पोषण के लाभ से लेकर जीवन की न्यूनतम लागत तक के लाभ से स्पष्ट हैं।[2] हालांकि कार्यस्थल अब लाभ–आवंटन का उपरिकेंद्र नहीं है, इसे परिवार द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। बच्चों के पालन–पोषण के लाभ, आवास अनुदान और लक्षित सामाजिक सहायता तक पहुंच अब घरेलू आय के आकलन से निर्धारित की जाती है। लाभार्थी की आय और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सामाजिक नीति को चुनिंदा रूप से लागू किया जाता है।

नतीजतन, निर्धनता को कलंकित किया गया है : यह जीवन का एक हिस्सा और अस्थाई प्रघटना होने से, जैसा कि सोवियत काल में था, अब लगातार पूर्ण समस्या बन गई हैं। इसके अलावा, सामाजिक सहायता के प्रावधान को इस प्रकार प्रबंधित किया गया है कि जरूरतमंद लोगों की अनदेखी होती है। पंजीकृत निर्धन लोगों में, एक तिहाई अत्यधिक निर्धन हैं, दो–तिहाई कार्यरत हैं, और दो–तिहाई महिला प्रधान परिवार हैं। इस प्रकार, लक्षित सामाजिक समर्थन कम मजदूरी की भरपाई करता है। यह बेरोजगारी और निर्धनता के जोखिम के विरूद्ध अब एक बीमा नहीं है।

व्यक्तिगत जिम्मेदारी की विचारधारा ने अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों को उनके पास के सभी संसाधनों को जुटाने और निर्धनता एवं सामाजिक अपवर्जन से बचने के लिए अविश्वसनीय प्रयास करने की आवश्यकता बताई है। वे पुनर्गठित रोजगार प्रणाली, भूतपूर्व समाजवादी वितरण प्रणाली के ढहने और पूर्ववर्ती समाजवादी देश में सर्वाधिक उदार बाजार प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के प्रभावों को ऑफसेट करने के लिए पहले से एकत्रित संसाधनों का उपयोग करते हैं। श्रमिकों को रोजगार की तलाश और दूसरे एवं अंशकालिक नौकरियां लेने के लिए मजबूर किया गया। श्रमिक और निजीकृत सामाजिक देखभाल के संदर्भ में प्राथमिक देखभाल कर्ता के रूप में सेवा क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं लैंगिक मुद्दों पर संघर्ष करती हैं। पेशन को कम मजदूरी के पूरक के रूप में लिया जाता है : हमारे एक–तिहाई उत्तरदाता, जो कार्यरत थे, पेंशनभोगी थे।

वर्तमान में हम इस भंवर को विस्तृत होते देख रहे हैं क्योंकि चिकित्सक और विश्वविद्यालय प्राध्यापक जैसे पेशेवर आर्थिक अस्थिरता का सामना करते हैं। जैसा कोमी गणतंत्र के एक अवनत हिस्से में तातियाना लिटकिना के शोध ने दर्शाया, निर्धनता संकेंद्री वृत्तों में बाहर की तरफ विस्तारित हुई है, अंततः वह शहर के सभी निवासियों तक पहुंच गई। स्पष्ट रूप से मुख्य शहरों में कुछ समूहों द्वारा प्राप्त अवसरों और लाभ की बाजार द्वारा आपूर्ति की जाती है क्योंकि यह कई अन्य लोगों को समाज के हाशिये पर विस्थापित करती है।

इस बीच, हाल ही में राज्य द्वारा प्रस्तावित पेंशन सुधार, जिसमें सेवानिवृति की उम्र में वृद्धि सम्मिलित थी, विभिन्न राजनीतिक समूहों के लिए देश की संभावनाओं और आम रूसियों की जरूरतों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की बजाय ध्यान आकर्षित करने का एक क्षेत्र बन गया। 1990 के दशक की तरह, रूसी युवा प्रतिरोध करने के लिए शहर की सड़कों पर आ गये और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य की मांग करने लगे।

यह निबन्ध निम्नलिखित आलेखों पर विश्वास करता है : स्वेतलाना यरोशेंको (2017), ''लिशनी लियुदी, इली हे रीजाइम इस्किलीचेनिया बी पोस्टोसेवत्सोम ओवस्चवेव'' (अनावश्यक लोग या सोवियत–पश्च रूस में सामाजिक अपवर्जन का शासन), इकोनोमिचेशिया सोत्सोलोगिया 18(4): 60-90; तातियाना लिटकिना एंव स्वेतलाना यारोशेंको (आगामी), ''वोजमोनिया ली सोत्सोलोगिया डैलिया ट्रुडियाशिखिया क्लेशोव सी रोसि'' (क्या रूस में ब्लू कॉलर समाजशास्त्र संभव है?), मीर रोसि। ■

1. मई 2018 से ही न्यूनतम मजदूरी जीवनयापन की न्यूनतम लागत पर आंकी गई थी।
2. 2010 में, रूस में एक व्यक्ति के लिए रहने की न्यूनतम लागत 5685 रूबल थी। न्यूनतम वेतन 4,330 रूबल प्रतिमाह था। न्यूनतम मासिक बेरोजगारी लाभ भुगतान 850 रूबल प्रति माह था। जबकि अधिकतम भुगतान 4,900 रूबल था। न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान 6177 रूबल प्रति माह था, जबकि विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को 1340 रूबल का मासिक वजीफा मिलता था। न्यूनतम बाल पालन सहायता भुगतान 2020 रूबल प्रति माह था जबकि औसत मासिक वेतन 20,952 रूबल था।

सभी पत्राचार स्वेतलाना यारोशेंको को <ps.yaroshenko@spbu.ru> पर प्रेषित करें।

> चीन में लम्पनप्रोलिटेरियेट और नगरीय दलित

न्गाई-लिंग सम, लंकास्टर विश्वविद्यालय, यूके द्वारा

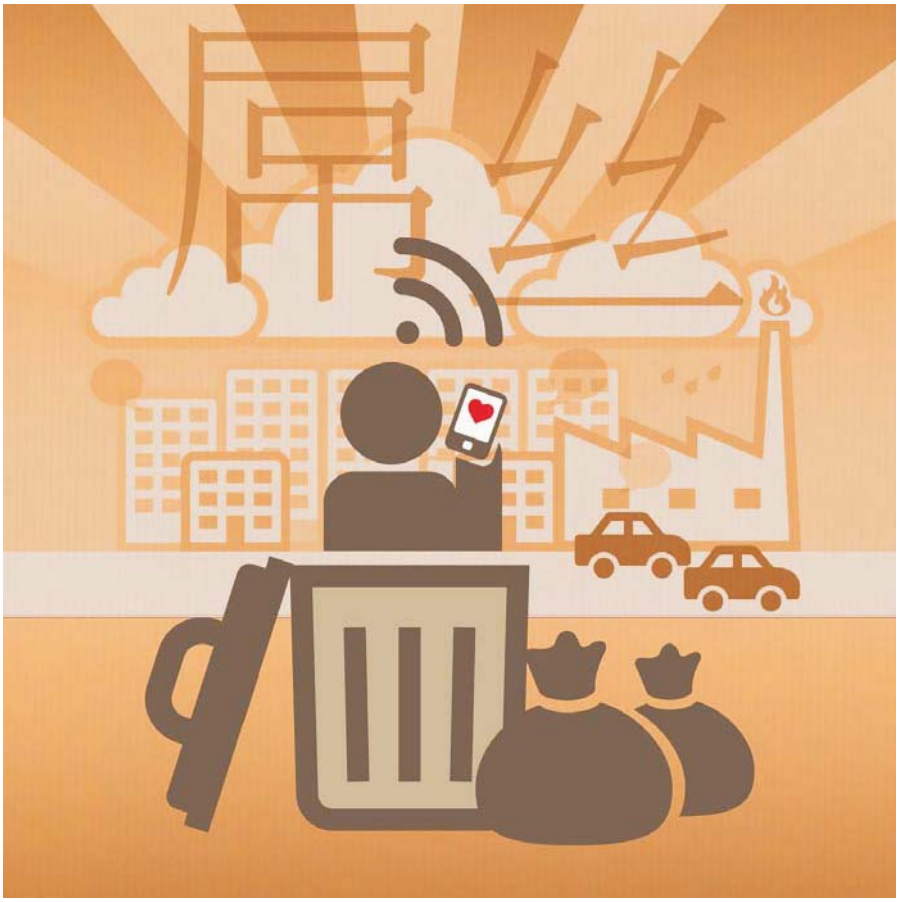

अर्बू द्वारा चित्रण।

मार्क्स और एंग्रेल्स ने लम्पनप्रोलिटेरियेट शब्द को मुख्य रूप से वर्णनात्मक, निन्दात्मक और शब्दाडंबरपूर्ण तरीके में काम में लिया था। हाल ही के आर्थिक और राजनीतिक विमर्श में "अंडरक्लास" (निम्न वर्ग) समान ही स्थान रखता है, जबकि "प्रीकेरियेट" में अधिक सकारात्मक अर्थ निहित है। यह आलेख ग्राम्शी के "सबाल्र्टन" या "अधीनस्थ" वर्गों की अवधारणा को काम में लेता है जिसका उद्देश्य विविध अधीनस्थ समूहों के शोषण, उत्पीड़न और सीमांतता के बहुआयाममी प्रकृति के साथ प्रमुख सामाजिक समूहों के आधिपत्य से स्वायत्तता का अपेक्षाकृत अभाव को पकड़ना है। मेरा वैयक्तिक अध्ययन यह देखता है कि चीन में 2008 के वित्तीय संकट के बाद से नगरीय निर्धन के एक विशेष तबके की निर्धनता और असमानता के जीवंत अनुभव एक नई पहचान डियोसी के विकास में प्रतिबिंबित होते हैं। डियोसी निजी और उपसंस्कृति दोनों के सृजन हेतु सामाजिक मीड़िया को काम में लेता है जो प्राधान्य मूल्यों एवं प्रतिमानों को आत्म–उपहास तरीके से पलट देता है।

> चीन में सबाल्र्टन दियोसी (हारे हुए) की पहचान

2008 के वित्तीय संकट ने नगरीय अंडरक्लास की स्थिति को भड़काया, शुरूआत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण और फिर कर्ज–आधारित नगरीय मेगा–प्रोजेक्ट एवं बड़े पैमाने पर सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम के कारण रियल–एस्टेट में उछाल के कारण। कर्ज द्वारा उत्तेजित सम्पत्ति उछाल ने आवास की बढ़ती कीमतें, आवासीय किराए और भूतहा शहरों को जन्म दिया; उत्तरोत्तर, अनिश्चित प्रवासी श्रमिकों को नगरीय आवास और सम्बन्धित कल्याण लाभ के अधिकार के बिना कम वेतन पर लम्बे समय तक काम करना पड़ा। जिनके पास फ्रैक्ट्री–प्रदत्त शयनग्रह नहीं थे, उन्हें शहरी सीमा पर घटिया आवासों के लिए उच्च किराये का भुगतान करना पड़ता था या नगरीय केन्द्रों में अवसीमिय स्थानों (जैसे बाल्कनियों, छतों, कंटेनर या भूमिगत बंकर) में रहना पड़ता था। उदाहरण के लिए, 2014 में बीजिंग में, लगभग एक मिलियन प्रवासियों ने भूमिगत हवाई हमला आश्रम स्थलों और प्राकृतिक

>>

रोशनी के अभाव वाले और सामूहिक शौचालय और रसोई वाले भंडार गृहों में लगभग 65 अमरीकी डालर प्रतिमाह किराये पर छोटे कमरों को साझा किया। इनमें कम वैतनिक सेवाकर्मी जैसे बैरे, केश प्रसाधक, चौकीदार, दुकान सहायक, फेरीवाले, रसोइये, सुरक्षा प्रहरी और निर्माणकर्मी सम्मिलित थे। इन सबाल्टर्न समूहों को एक "मूषक जाति" के रूप कहा गया, जैसा सी वाय सिम अपने 2015 के वीडियो : http://creativetimereports.org/2015/01/24/sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-underground-apartments/ (अंग्रेजी में लिखित भाषांतर) में दिखाते हैं।

2011 के अंत से, वास्तविक या डिजीटल कारखानों में कार्यरत कई युवा प्रवासी श्रमिक जो इंटरनेट पॉप संस्कृति और सामाजिक मीडिया में गम्भीर रूप से लिप्त हैं, ने अपनी असमानता और अन्याय की भावनाओं का प्रत्युत्तर एक नई पहचान के रूप में उनकी सीमातंता और अधीनस्थता का वर्णन कर के दिया। दियोसी की वैषयिक स्थिति वास्तव में एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी के प्रशंसक–प्रतिद्वंधी प्रशंसकों के मध्य आनलाइन लड़ाई में उभरी। इस पहचान को फिर एक नजदीकी हमनाम "शिश्न के प्रशंसक" के रूप में आत्म–उपहास के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया गया। यह प्रतिस्थापन शीघ्र ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पहचान के निर्मित होने के दो माह बाद, इसने 41.1 मिलियन गूगल सर्च और चीन के ट्विटर जैसे वायबो पर 2.2 मिलियन ब्लाग पोस्ट को आकर्षित किया। युवा दलितों ने स्वयं को दियोसी घोषित करना शुरू कर दिया और सभी प्रकार के सहयोगी चैट रूम और सोशल मीडिया प्रारम्भ किये गये (जैसे वाय वाय और क्यू क्यू चैट्स)।

सोशल मीडिया में जैसे विमर्श और पहचान संचरित हुए, नये अर्थ जुड़ने लगे। शीघ्र ही यह प्रवासी श्रमिकों की असमानता, सीमातंता, अपवर्जन, आर्थिक कठिनाई, हताशा और सामाजिक पीड़ा के साथ उनकी अधूरी उपभोक्ता और रूमानी इच्छाओं का सघन करने लगे। वे स्वयं को अल्पाधिकार पृष्ठभूमि वाले के रूप में दर्शाते हैं जो अल्प वेतन कमाते हैं, कम उपभोग करते हैं और जिनके पास सामाजिक नातों का अभाव है। उनकी अल्प आय, उपभोग एवं उधार लेने की क्षमता के साथ उनकी निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा सामाजिक–भावनात्मक रूप से अवमूल्यित जीवन जीने की धारणा : कार्य के लम्बे घंटे, खराब आवास, अनिश्चित कैरियर सम्भावनाएं, लापता पारिवारिक जीवन, घर पर माता–पिता के प्रति अपराध बोध और एक रिक्त भावनात्मक एंव रूमानी जिंदगी के साथ जुड़ी हैं। यह अक्सर दियोसी द्वारा दिये गये वृत्तान्तों – कैसे उन्होंने वेलन्टाइन दिवस, क्रिसमस, उत्सव मौसम और इंटरनेट पर साथियों को ढूंढने में रात्रि प्रहर में उजागर किया जाता है। हाशिये से ऐसे आत्मीय प्रवचन रोजमर्रा के नगरीय आर्थिक और सामाजिक जीवन में उत्पन्न असमानताआं में जकड़े सामूहिक सामाजिक अनुभव को व्यक्त करते हैं।

दियोसी सबाल्टर्निटी का यह दैनिक अस्तित्व भी एक जैव–राजनीतिक द्विगुण जो आय, उपभोग, अवसर, शक्ति नेटवर्क, प्रेम, रोमान्स और अंतरंगता तक उनकी असमान पहुंच पर आधारित दो मुख्य लैंगिक बॉडी–टाइप के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। पुरुष दियोसी स्वयं को "गरीब, ठिगने एवं कुरूप" हरवैया के रूप में देख आत्म–निंदा करते हैं। अल्प आय और अनाकर्षक काया के साथ वे स्वयं को लडकियों को भौतिक उपहार देने और उन्हें रिझाने में असमर्थ के रूप में निर्मित करते हैं। उनके पास कोई घर, कार, दुल्हन/प्रेमिका नहीं है और वे अपना अधिकांश समय घर पर सस्ते मोबाइल का उपयोग कर, इंटरनेट पर सर्फिंग करते हुए और डीओटीए जैसे मीडिया गेम्स खेल कर बिताते हैं। यह स्थिति धीरे–धीरे महिला सबाल्टर्नस तक फैल गयी है। फिर गॉफशुई हैं। इस श्रेष्ठतर समूह के सदस्य हैं : (1) "लम्बे, धनी और सुंदर"; और (2) "राजकुमार" जिनके पार्टी और राज्य के साथ विशिष्ट सम्बन्ध हैं जो उन्हें रोजगार और पहुंच में लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। वे "तीन खजानों" (आईफोन, स्पोर्ट्स कार और डिजाइनर घड़ी) का आनंद लेते हैं और सुंदर लड़कियों को आकर्षित कर सकते है। इस युग्मक में अव्यक्त समालोचना, आत्म–उपहास, आत्म रक्षा और आत्म–मनोरंजन का मेल सम्मिलित है। यह राज्य पूंजीवादी चीन में प्रतिरोध करने और असुरक्षा को जीने का दैत्य तरीका है। इन दो कल्पित समूहों के मध्य परिणामी अंतर व्यंग्यात्मक कार्टून, तस्वीरों, टीवी शो, फंतासी वार्ता इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन अधिक उजागर होता है। दोनों समूहों के पास परिवहन (बस बनाम बीएमडब्ल्यू), स्मार्ट फोन (नोकिया बनाम आइफोन), खाने की जगह (पार्श्व मार्ग पर स्टोर बनाम महंगे रेस्त्रां) एवं रूमानी मिलन के भिन्न प्रकार के तरीके हैं। संक्षेप में, दियोसी वृत्तान्त बिना भविष्य या उम्मीद के भाग्य के आत्म–उपहास; राजकुमारों द्वारा सन्निहित सामाजिक कुलीनवाद की तरफ अप्रकट बैर; और एक असमान समाज में स्वीकार नहीं किये जाने की निराशा को प्रतिबिंबित करते हैं। ■

सभी पत्राचार न्गई–लिंग सुम को <n.sum@lancaster.ac.uk>
पर प्रेषित करें।

> वर्ग विन्यास और कृषि पूंजीवाद

तानिया मरे ली, टोरोंटो विश्वविद्यालय, कनाडा द्वारा

तेल ताड के बागानों से घिरा एक गांव। फोटोः तानिया ली।

कौन किसका मालिक है? कौन क्या करता है? किसको क्या मिलता है? अधिशेष के साथ वे क्या करते हैं? कृषि विद्वान हेनरी बर्नस्टीन द्वारा पूछे गये ये चार सारिक प्रश्न ग्रामीण वर्ग विन्यास के विश्लेषण के लिए एक उपयोगी प्रारंभिक बिन्दु प्रस्तुत करते हैं। ये प्रश्न उन स्थानों पर विशेष रूप से अच्छी तरह काम करते है जहां खेत का स्वामित्व और फार्म स्केल एवं दक्षता में वृद्धि के लिए अधिशेष को निवेश करने की क्षमता यह निर्धारित करती है कि कौन से किसान अपने खेतों को बनाये रख सकते हैं और संचय कर सकते हैं और कौन से अपने भूमि से बेदखल हो सकते हैं। मैंने ग्रामीण इंडोनेशिया के दूरदराज के कोने में एक ऐसी जगह का अध्ययन किया, जहां मैंने देशज पठारी किसानों द्वारा उनकी पूर्व आम भूमि से वैयक्तिक भूखंड काटे जाने और कोको की खेती प्रारम्भ करने के बाद ग्रामीण वर्गों के तीव्र गठन को ट्रेक किया। तब से, उनके पास निर्वाह उत्पादन में लौटने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उनके छोटे अवशिष्ट भूखण्ड परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं उगा सकते थे और कपड़े, स्कूल फीस इत्यादि के लिए आवश्यक नकद की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। अतः उन्हें बाजार–अभिमुखित उत्पादन बढ़ाना पड़ा और यह आशा रखनी पड़ी कि वे अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने एवं खेतों को उत्पादक बनाये रखने हेतु पर्याप्त धन जुटा पायेंगे। जो असफल हुए, उन्होंने अपनी जमीनें खो दीं। यह एक पाठन योग्य मामला था कि जब छोटे किसान लघु फर्मों जैसे बन जाते हैं तब क्या होता है : पूंजीवादी सम्बन्धों द्वारा अधिशासित, जब वे उद्यम को प्रतिस्पर्धी बनाये रखने के लिये निवेश नहीं कर सकते हैं उन्हें सब कुछ खोने का जोखिम होता है, और वे जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते हैं क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं।

कृषक वर्ग विन्यास की जिस प्रक्रिया को मैंने अभी वर्णित किया है वह अन्य कारकों की एक श्रृंखला से संशोधित होती है। सबसे महत्वपूर्ण सरकारी अंतरण एवं विप्रेषण हैं। ब्राजील के "बोल्सा फैमिलिया" की तरह नियमित सरकारी नकद अंतरण या कही अन्य स्थान पर कार्य करने वाले परिजनों से धन विप्रेषण प्राप्त करने वाले कृषक परिवार के पास कठिन समय (जैसे जब कीमतें कम हो, असहनीय कर्ज, खराब फसल, बीमारी या पारिवारिक आपात स्थिति हो) में अपने खेतों को खोने से बचाने के लिए एक कुशन होता है। विप्रेषण को भूमि क्रय करने, धन उधार देने, या शिक्षा में निवेश के लिए काम में लिया जा सकता है। उसका उपयोग प्रभावशाली घरों का निर्माण करने के लिए या भव्य विवाह का आयोजन, जो अनावश्यक खर्च की तरह दिख सकता हैं, लेकिन वह एक परिवार के सामाजिक नेटवर्को के निर्माण एवं उत्पादक संसाधनों (जैसे अनुबंध, कर्ज, सूचना, अनुदान) तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए

>>

किया जा सकता है। आज हम ग्रामीण एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में सब तरफ "विप्रेषण घर" एवं भूमि, श्रम और पूंजी के रूपांतरित भूमिकाओं के अन्य लक्षणों को देख सकते हैं। इस बिन्दु पर ऊपर उल्लेखित चार प्रश्न (कौन किसका मालिक है, कौन क्या करता है, किसे क्या मिलता है, अधिशेष के साथ वे क्या करते हैं) अभी भी ग्रमीण वर्ग विन्यास का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन कृषितर संबंधों की व्यापक श्रृंखला को समाविष्ट करने के लिए उनकी अधिक व्यापक रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता है।

लघु या कुटुम्ब आधारित खेतों से भूमि के बड़े भू–भाग पर नियन्त्रण तक बढ़ने से वर्ग विश्लेषण गैर–बाजार शक्तियां जो यह निर्धारित करती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में "कौन किसका मालिक है" और – "किसे क्या मिलेगा", के द्वारा जटिल बनता है। लेटिन अमरीका की तरह फिलीपीन्स में, बड़े जमींदार जिन्होंने स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान अपनी जमीनें प्राप्त की थीं, राजनीति में हावी हैं और वे इस तरह से नियम बनाते हैं कि वे अपनी जमीनों पर कब्जा बनाये रख सके चाहे वे उत्पादक हो या नहीं। इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अन्यत्र, जहां बड़े भू–स्वामियों का कोई औपनिवेशिक इतिहास नहीं है, समकालीन राजनेता और सरकारी अफसर अपने कार्यलय की आधिकारिक और गैर–आधिकारिक शक्तियों को भूमि के बड़े भू–भाग तक पहुंच के लिए काम में लेते हैं। इन स्थानों पर, भूमि राजनैतिक कार्यालय को निर्मित नहीं करती हैं बल्कि राजनैतिक कार्यालय भूमि को उत्पन्न करता है। चूंकि जमीनें सट्टे में लगी हो सकती हैं, या लाभ के लिए पलटी जा सकती हैं, "जमींदार" होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पूंजीवाद या कृषि के साथ संलग्नता हो।

बड़े खेतों और बागानों के वर्ग चरित्र को समझना आज आवश्यक हो गया है, क्योंकि उत्पादन का यह स्वरूप व्यापक रूप से विस्तृत हो रहा है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया में ताड़ तेल के महाकाय बागान दस मिलियन हेक्टेयर तक फैले हैं और सरकार इस क्षेत्र को २० मिलियन तक विस्तारित करना चाहती है। लाओस और कंबोडिया में रबर के बागान हैं, जो अधिकाधिक जगह लेते हैं। ब्राजील और पड़ोसी देशों में, बड़े पैमाने पर मशीनीकृत सोया फार्म हैं। ये बड़े खेत और बागान, चाहे वे व्यक्तियों के या राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय निगमों के स्वामित्व में हों, अक्सर पाठ्यपुस्तकीय अर्थ में "पूंजीवादी" नहीं होते हैं क्योंकि वे अपने किसी भी निवेश के लिए बाजार मूल्य का भुगतान नहीं करते हैं। उन्हें मुफ्त या फिर न्यूनतम लागत पर राज्य स्वामित्व वाली भूमि लीज पर, राज्य द्वारा आपूर्ति किये गये बुनियादी ढांचे, कर में छूट और सस्ते ऋण द्वारा बहुत अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है। कभी–कभी, वे राज्य समर्थित प्रवासन योजनाओं द्वारा आसानी से आपूर्ति किये सस्ते श्रम को भी प्राप्त करते हैं। वास्तव में, अक्सर मॉडल पूंजीवादी के रूप में कल्पित बहुराष्ट्रीय "निवेशक" शायद बहुत कम या बिल्कुल भी निवेश नहीं करने के बजाय, मुफ्त या रियायती निवेश पर निर्भर रहते हैं। बड़े कृषि उद्यम अनुबंध खेती या आउटग्रोअर स्कीम पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं जो कौन वास्तव में किसका मालिक है और मिलने वाले लाभ में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा के प्रश्नों को धुंधला कर देते हैं। बड़े खेतों के लिए सब्सिड़ी इस तर्क से न्यायसंगत मानी जाती हैं कि बड़े पैमाने के उत्पादक "विकास" और रोजगार लाते हैं। ऐसा वे उनके द्वारा विस्थापित विविध प्रकार के रोजगार और विकास को भारी छूट दे कर या जबरदस्ती और दबाब के अवसरों जो उनकी एकाधिकार की स्थिति के साथ जाते हैं, के द्वारा करते हैं।

सरकारी अधिकारी और राजनेता बड़े कृषि उद्यमों के विस्तार से लाभ प्राप्त करते हैं जो परमिट, फीस किकबैक और जबरन वसूली से राजस्व की एक धार खोल देते हैं। वे अक्सर कार्पोरेट बोर्डों पर बैठते हैं। हम इन निजी राज्य–कार्पोरेट हाईब्रिड के वर्ग विन्यास का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? उत्पादन के समय पूंजी और श्रम के मध्य जिन वर्ग सम्बन्धों को हम अवलोकित करते हैं वे अभी भी महत्वपूर्ण हैं लेकिन अन्य पैमानों और सम्बन्धों को भी जांचना आवश्यक है। ब्राजील या इंडोनेशिया जैसे देशों में वैश्विक पूंजी स्वयं ही नहीं अवतरित होती है – उसका मार्ग सभी प्रकार के लिंग, गठबंधनों, कानून और विचार–विमर्श द्वारा प्रशस्त होता है। साहित्य में प्रचलित कुछ शब्द राज्य और गैर–राज्य शक्तियों के इस तरह के निवेश को सक्षम बनाने वाली उलझनों को उजागर करते हैं अतः "परभक्षी कुलीन" या "क्रोनी पूंजीपति"। ऐसे हाईब्रिड कृषि या वैश्विक दक्षिण के लिए अनूठे नहीं हैं। प्रमुख कार्पोरेशन अक्सर राजनीतिक एहसानों और राज्य लाइसेंस प्राप्त एकाधिकार द्वारा समर्थित होते हैं और अनुपार्जित किराये पर कब्जा करने की अपनी क्षमता से मेगा–लाभ प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक चार प्रश्न अभी भी इन विन्यासों के विश्लेषण के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं : हमें अभी भी यह जानने की जरूरत है कि कौन किसका मालिक है, कौन क्या करता है, किसे क्या मिलता है और अधिशेष के साथ वे क्या करते हैं। लेकिन फिर से विभिन्न पैमानों पर कार्यरत सम्पत्ति, कार्य और निवेश के स्वरूपों को सम्मिलित करने के लिए प्रश्नों को खींचने की आवश्यकता है। वर्ग विन्यास जितने अधिक फैले और उलझे होंगे, उतने ही वे बागान श्रमिकों, अनुबंध किसानों या स्वतन्त्र लघु कृषकों, जो ऐसे निष्कर्षित संबंधों में जकड़े हैं जिसे वे पहचान नहीं सकते हैं और संघर्ष भी नहीं कर सकते हैं, के लिए अस्पष्ट हैं। ■

सभी पत्राचार तानिया मरे ली को <tania.li@utoronto.ca>
पर प्रेषित करें।

> ब्रिटेन के कल्याणकारी सुधारों के साथ जीवन (और संघर्ष)

रूथ पैट्रिक, यॉर्क विश्वविद्यालय, यूके द्वारा

कॉपीराइटः निर्धनता 2 समाधान, 2017.

पिछले 35 वर्षों में ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में उत्तरोतर सुधारों की लहर चली है। इन सुधारों को ऐसे प्रयासों के अंत के रूप में लागू किया गया, जिसे राजनेता अक्सर 'कल्याण की निर्भरता की संस्कृति' के रूप में वर्णित करते हैं और कल्याणकारी स्थितियों के लिए कोई बड़ी भूमिका प्राप्त हुई है – लाभ प्राप्त करने की परिस्थितियों (सबसे अधिक कार्य से संबंधित) पर शर्तें लगाना। नई लेबर सरकारों के दौरान और सन् 2010 के बाद कंजर्वेटिव नेतृत्व द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। राज्य समर्थन में बड़े पैमाने की कटौती चौका देने वाली थी और उसके परिणाम अब चरम सीमा पर हैं। यहाँ इसके कुछ आँकड़े बोधप्रद होंगे।

सन् 2010 की तुलना में सन् 2021 तक, कीमतों और जीवन स्तर की लागत में वृद्धि के बावजूद, कार्यशील–आयु की सामाजिक सुरक्षा पर 37 अरब पौण्ड कम खर्च किये जायेंगे। यह कुल लाभ पर व्यय में 25 प्रतिशत कमी को दर्शाता है। विशेषकर विकलांगता के लाभों में बड़ी कटौती जो हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों की सहायता के लिए बनाये गये थे।

इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा सहायता की इन कटौतियों के असर बाल गरीबी में वृद्धि, निराश्रयता में वृद्धि, और ब्रिटेन के कई सबसे गरीब परिवारों की खाद्य बैंकों पर बढ़ती निर्भरता में दिखाई देता है। दि इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज का अनुमान है कि 2015-16 और 2021-22 के मध्य पूर्ण बाल गरीबी में चार प्रतिशत के अंकों की वृद्धि होगी। इस वृद्धि का तीन–चौथाई भाग (4 लाख बच्चों के बराबर) लाभ में परिवर्तन के कारण होगा। निर्धनता विरोधी चैरिटी – दि जौसेफ रैनट्री फाउंडेशन का अनुमान है कि कुछ स्थितियों में 2017 में 1.5 करोड़ लोगों को अभावों का सामना करना पड़ा, जबकि ब्रिटेन के सबसे बड़े फूड बैंक प्रदाता 'द ट्रसल ट्रस्ट' ने वर्ष 2017-18 के वित्तीय संकट के दौरान तीन दिवसीय आपातकालीन खाद्य आपूर्ति के लिए 1,332,952 पार्सल दिये।

इन आँकड़ों के बावजूद ब्रिटेन की सरकार सामाजिक सुरक्षा लाभों में परिवर्तन करने और कल्याणकारी सुधार के अपने पैकेज को उचित ठहराने और जारी रखने को प्रतिबद्ध है। वह सार्वभौमिक क्रेडिट, एक लाभ कार्यक्रम जो लाभ व्यवस्था को सरल बनाने और कार्य करने को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था लेकिन जो डिजाइन और कार्यान्वयन की समस्याओं से ग्रस्त है, को जारी रखता है। दो–तिहाई गरीब लोग ऐसे घरों में रह रहे हैं जहां कोई

>>

"ऑल इन दिस टुगेदर। आर बेनेफिट्स एवर अ लाइफस्टाइल च्वाइस?" फिल्म से चित्र, डोल एनिमेटर्स द्वारा प्रस्तुत (2013)।
कॉपीराइटः डोल एनिमेटर्स।

काम कर रहा है, के सबूत के बावजूद प्रधानमंत्री थेरेसा मे का लगातार तर्क है कि 'काम गरीबी से बाहर निकलने का बेहतर मार्ग है'।

> कल्याणकारी सुधारों के जीवंत अनुभव

इस संदर्भ के विरुद्ध लाभ भत्तों में परिवर्तन के प्रतिदिन के अनुभवों का पता लगाना महत्वपूर्ण है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन पर कल्याणकारी सुधारों के प्रभावों का दस्तावेजीकरण करना आवश्यक है। *कल्याणकारी सुधारों के दैनिक अनुभवों के अध्ययन* जिसने लाभ भत्तो के परिवर्तन से प्रभावित इंग्लैण्ड के उतरी शहर में रहने वाले लोगों को ट्रेक किया का यह लक्ष्य रहा है। रोजगार तलाश रहे लोगों, एकल माता–पिता और विकलांग लोगों से कई बार किये गये साक्षात्कारों के माध्यम से कल्याण सुधारों का व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को ट्रेक करना संभव है और इसे राजनीतिक कथ्य जो कहता है कि 'कल्याण सुधार आवश्यक हैं और ये कार्य कर रहे हैं', के तरीकों जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित के साथ विरोधाभासी हैं, के साथ देखना चाहिए। तब एक मजबूत विरोधाभास दिखाई देता है।

इस अध्ययन में भाग लेने वालों के लिए, उनके लाभ भत्तों में बारम्बार होने वाले परिवर्तनों ने सामाजिक असुरक्षा का वातावरण पैदा किया है जो उन्हें लगातार चिंता में डालता है कि वे व्यक्तिगत तौर पर इन परिवर्तनों के प्रभावों का मुकाबला कैसे करेंगे। इन लाभ भत्तों की प्राप्त करने की प्रक्रिया भी चिंता का कारण बनती है, विशेष रूप से विकलांगता के भत्ते का आकलन भय और अनिश्चितता का स्त्रोत हैं। शेरोन ने बताया कि विकलांगता भत्ते के लगातार पुनः मूल्यांकन के बारे में उन्हें कैसा लगा, "वह [मुझे] बहुत तनाव देता है ... मैं हर समय इसके बारे में सोचती हूँ।"

इसके अतिरिक्त लोककल्याण पर बढ़ी हुई शर्तों को नकारात्मक रूप से अनुभव किया जाता है, साथ में प्रतिबंधों के खतरे और आय में निरंतर कमी एक निरंतर संभावना जगाती कि दावेदारों की भविष्यवाणी उन्हें ओर भयभीत करे कि यदि उनके भत्ते छीने लिए गये तो वे चीजों को कैसे सामना करेंगे। यहाँ तक कि जो शर्तों की प्रत्येक बात की अनुपालना करते हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है और भय के कारण जॉब सेंटर प्लस 'समर्थन' से जुडना नहीं चाहते हैं कि यह आगे की अन्य शर्तों का नेतृत्व करेगा, लोगों के इस अनुमोदन से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई प्रतिभागियों ने उनके द्वारा मुश्किल विकल्पों के चयन (अक्सर प्रतिदिन) जैसे कि गर्म करें या खाये और माता–पिता कितनी बार बिना खाये रह जाते हैं ताकि उनके बच्चों को वह मिल सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है, का वर्णन कर बढ़ती निर्धनता और कठिनाइयों का सबूत दिया। जैसा कि क्लो ने कहा, "हम गरीब हैं, हम बहुत अधिक गरीब हैं। ऐसा लगता है कि हम ऐसे दौर में रहते हैं जब आप ये सब विज्ञापन देखते हैं कि जो यह कहते हैं – कृपया हमारे बच्चों को खिलाएं, मेरे बच्चों को खिलाएं।"

शोध में यह भी दिखाया गया है कि लोग किस तरह से भत्तों के कलंक का अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी स्वयं की पात्रता और समर्थन के लिए पात्रता को शर्तों की अनिवार्यता से और दोहराये जाने वाले भत्ते पुनर्मल्यांकन की माँग से प्रश्नांकित किया गया है। उन्होंने संस्थानों के कलंक के अनुभवों की भी व्याख्या की है, जब वे रोजगार केन्द्र गये या कल्याण–से–काम के समर्थन के विभिन्न प्रकारों में संलग्न हुए। यहाँ वे उन सलाहकारों से नियमित मुठभेड़ करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उन्हें नीचा दिखाते हैं और उनके साथ बिना किसी सम्मान और आदर का व्यवहार करते हैं। सोफी ने समझाया हैः "मूलरूप से वे (जॉब सेंटर के सलाहकार) हमें कचरे की तरह देखते हैं।"

कुल मिलाकर, यह शोध "कल्याण" की लोकप्रिय राजनीतिक विशेषताओं और जीवन की वास्तविकताओं के मध्य तीव्र असंगतताओं और कल्याण सुधार किस प्रकार से निर्धन लोगों के जीवन को अध्कि कठिन बना रहे है, का चित्रण करता है।

> बढ़ता प्रतिरोध

हाल के वर्षों में लगातार भत्तों में परिवर्तन के कारण ब्रिटेन सुधारों को लेकर बढ़ते प्रतिरोध का भी गवाह रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिरोध लोगों के समूह के उस हिस्से से आ रहा है जिनका गरीबी का प्रत्यक्ष अनुभव है और उन्होंने बेराजगार रहकर सामाजिक सुरक्षा की स्थिति देखी है। वे इसलिए साथ में आये हैं कि 'लोककल्याण' की लोकप्रिय प्रवृति को चुनौती दे सकें और इसके बदलाव का अभियान चला सकें। उदाहरण के लिए कल्याणकारी सुधारों के दैनिक अनुभवों का अध्ययन करने वाले कुछ सदस्य सन् 2013 में अपने अनुभवों के लिए फिल्मांकन के लिए साथ आये जो बाद में डोल एनिमेटर्स प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। डोल एनिमेटर्स सक्रिय रहते है और हाल ही में पोवर्टी टू सोल्यूशन्स में लगे हुए हैं, जहां वे दो अन्य समूहों के साथ यह ब्लूप्रिंट बनाते है कि गरीबी से निपटने में क्या प्रभावी हो सकता है। ये दो उदाहरण अन्य अनगिनत उदाहरणों से जुड़ते हैं जो मुख्यधारा के राजनीतिज्ञों द्वारा प्रस्तुत किये गये लोककल्याण के सुधारों के आंशिक पक्ष को इंकार करने के प्रमाण देते हैं। यह गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद का एक जरूरी स्त्रोत है, विशेषरूप से जब बढ़ती गरीबी और संकटों के संदर्भ में यह तर्क स्थापित किया जाता है कि ब्रिटेन में भत्तों के परिवर्तन प्रभावी हो रहे हैं। ■

सभी पत्राचार रूथ पैट्रिक को <ruth.patrick@york.ac.uk> या ट्विटर <@rpatpat00> पर भेजें।

> वर्ग एवं पारिस्थितिकी

रिचर्ड योर्क, ओरेगन विश्वविद्यालय, यूएसए एवं **ब्रेट क्लार्क**, ऊटाह विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा

एक बेहतर दुनिया के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए पूंजी की दुनिया पर पकड़ को तोड़ना होगा। आई.रैंस्ले/फ्लिकर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी वर्ग द्वारा एवं स्वयं के लिये, के अंतहीन संग्रहण पर आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था इस उद्देश्य को, अनियंत्रित सम्पत्तिहरण एवं शोषण के द्वारा प्राप्त करती है, जो अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय अधोगति एवं सामाजिक असमानताओं को उत्पन्न करता है।

सम्पत्तिहरण – लूट की एक प्रक्रिया में प्रथागत अधिकारों के विनाश एवं गैर पूंजीवादी उत्पादक संबंधों के विघटन के साथ–साथ दासता भी सम्मिलित थी। औपनिवेशिक हिंसा एवं भूमि अधिग्रहण ने उत्पादन के साधनों का निजीकरण करने में मदद की, जिससे वर्ग एवं संग्रहण की एक नस्लीय प्रणाली का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया ने दुनिया भर में प्राकृतिक संपदा एवं लोगों को लूटने की अनुमति प्रदान की, जिसने आंशिक रूप से औद्योगिक पूंजीवाद के उदय की नींव के रूप में काम किया। इस तरह बेदखल लोगों को निर्वाह के साधनों को क्रय करने के लिए कमाने के लिए अपने श्रम को बेचने को मजबूर होना पड़ा। कम मजदूरी वाले देशों में, श्रम शक्ति के शोषण की दर काफी अधिक हैं। यहां अति शोषण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अधिशेष प्रमुख पूंजीवादी देशों को स्थानांतरित होता है। पूंजीवादी सामाजिक अधिशेष, जो समग्र रूप से समाज द्वारा वृहद जेव–भौतिक विश्व के साथ अंतःक्रिया से उत्पादित होता है, पर नियंत्रण रखते हैं, एवं जिससे धन संग्रहित होता हे। इसके अतिरिक्त वे अवैतनिक सामाजिक प्रजनन कार्य, जो जीवन को बनाये रखने में मदद करता है का भी अधिशोषण करते हैं। यह कार्य असंगत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो अतिरिक्त सामाजिक असमानताओं को उत्पन्न करता है।

>>

पूंजीवाद लोगों के कल्याण के साथ–साथ पर्यावरण को भी खतरे में डालता है। एम. क्रैंडल/फ्लिकर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

पूंजीवादी के विकास की अनिवार्यता को देखते हुये, यह प्रणाली नक्षत्रीय सीमाओं को रौंदती है। वृहद स्तर पर आर्थिक प्रक्रियाओं को चलाने हेतु, उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक विस्तार अतिरिक्त संसाधन (जैसे ऊर्जा एवं पदार्थ) की मांग को उत्पन्न करते हैं एवं अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं। यह उत्तरोत्तर मानव इतिहास में पहले कभी न देखे गये पैमाने पर पर्यावरणीय शोषण में फलीफूत होता है जो पारिस्थितिकी तन्त्र की पुनर्योजी क्षमता के बाहर है एवं जिसका परिणाम पारिस्थितिक बाढ़, प्राकृतिक चक्र का विनाश एवं संसाधनों का अधिशोषण है। पूंजी का सामाजिक चयापचय अलगाव–समाज एवं वृहद जैव–भौतिक विश्व के मध्य आदान प्रदान का संबंध–जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के ह्रास के प्रवर्धन एवं समुद्र अम्लीकरण में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हैं। ये सिर्फ कुछ ही नाम है जो पर्यावरणीय चिंताओं के विषय है।

पूंजी के तर्क में, सम्पूर्ण विश्व–मानव, गैर मानवीय जानवर, पौधे, चट्टानें, हवा, जल आदि–निजी लाभ के संचय के लिये माध्यम बनने का कार्य करते हैं। जब पूंजीवाद की कार्य प्रणाली को अच्छे से समझा जाता है, तब वर्ग शोषण एवं पर्यावरणीय ह्रास के मध्य सम्बन्ध भी स्पष्ट होता है। यह वर्ग संघर्ष की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं उग्र पर्यावरणीय आंदोलन सम्मिलित हैं।

हालांकि विश्व भर में पूंजीवाद के प्रभुत्त्व ने न केवल पर्यावरणीय समस्याओं एंव सामाजिक अन्याय के कारणों की लोकप्रिय समझ को विकृत किया है, अपितु मानव स्थिति में सुधार लाने का क्या अर्थ है, को भी प्रभावित किया है। दो शताब्दियों और उससे भी अधिक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश राष्ट्रों में यह वृहद रूप से स्वीकार किया गया कि आर्थिक वृद्धि, "सामाजिक प्रगति" एवं "विकास" का पर्याय है। इसलिये, यह माना जाने लगा कि समाजों को अंतहीन आर्थिक वृद्धि (मुद्रीकृत विनिमय मूल्य द्वारा मापी गई) का अनुसरण करना चाहिए। ये दृष्टिकोण तथाकथित रूप से उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने एवं वस्तु एवं सेवा की गुणवत्तता एवं मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं ताकि सबको लाभ मिले, चाहे असमान रूप से ही। इस प्रकार के विकास को व्यापार एवं सरकारी नेताओं द्वारा गरीबी का समाधान एवं श्रमिकों की परिस्थितियों को बेहतर करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। इसको पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान का उचित मार्ग ढूंढ़ने के लिये भी चिह्नित किया गया, जो यह नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी समाधान को लाकर कर सकता हे। दूसरे शब्दों में यह तर्क दिया जाता है कि सभी सुधार निरंतर आर्थिक वृद्धि पर निर्भर हैं। यह लोकप्रिय चित्रण इस तथ्य को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करता है कि, पूंजीवाद के आधुनिकीकरण कार्यक्रम ने पर्यावरणीय समस्याओं के संचय की एक लम्बी श्रृंखला को उत्पन्न किया है। साथ ही करोडों लोगों को गरीबी में छोड़ राष्ट्रों के भीतर एवं राष्ट्रों के मध्य असाधारण असमानता को उत्पन्न किया है।

तथापि पूंजी के वैचारिक प्रभुत्व, उसके संरचनात्मक संगठन, उसकी वैश्विक शक्ति एवं उत्पादन के अलगाववादी व्यवस्था के कारण, कई श्रमिक श्रम संघ और यहां तक कि दुनिया भर की वामपंथी झुकाव वाली सरकारें पूंजीवादी विकास एजेंडे को पूर्णरूप या आंशिक रूप से जीवन की गुणवत्तता को बेहतर करने के तरीके के रूप में स्वीकार करती हैं। विशेष रूप से इसका एक दुर्भावनापूर्ण पहलू यह है कि अधिकतर लोग जिनको पूंजीवाद ने हानि पहुंचायी है, अपनी तकलीफों के लिये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दोष नहीं देते हैं, अपितु पर्यावरणवादियों, प्रवासियों, समाजवादियों, नारीवादियों, अन्य प्रजाति के लोगों एंव विभिन्न समूहों को दोष देते हैं, जो उनके दुश्मन नहीं है, अपितु संभावित साथी हैं।

पूंजीवाद की कार्य प्रणाली ने इस व्यवस्था के विरूद्ध व्यापक लामबंदी के लिए कई चुनौतियां एवं रूकावटों को पैदा किया है। स्तरीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था ने असमान विकास उत्पन्न किया, जहां पर वैश्विक दक्षिण के सस्ते श्रम को "उत्तर" के लिये बनायी गयी वस्तुओं के उत्पादन के लिये उपयोग में लिया गया। इन परिस्थितियों में, आर्थिक अधिशेष उत्तर के पूंजीपतियों को स्थानांतरित होता है, जबकि वस्तु उत्पादन से सम्बन्धित पर्यावरणीय ह्रास एवं औद्योगिक प्रदूषण असंगत रूप से दक्षिण में केन्द्रित हो गया। स्थिति को और जलवायु परिवर्तन के तात्कालिक परिणाम, जैसे बाढ़ एवं विषम सूखा, ने वैश्विक दक्षिण पर पहले ही विनाशकारी प्रभाव डाला हुआ है, विशेषतः अतिसंवेदनशील

>>

जनसंख्या पर। पूंजीवादी कार्यप्रणाली ने पर्यावरण अन्यायों की संपूर्ण श्रृंखला को उत्पन्न किया है, जिसने गरीब एवं अश्वेत लोगों पर असमानुपातित भार डाला है। जिसके परिणामस्वरूप आबादी के भीतर अतिरिक्त विभाजन एवं असमानता बढ़ी है। इसी समय पूंजी अपना बल एवं प्रभाव को अपने संचालन को बनाये रखने एवं पर्यावरणीय समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन को सम्बोधित करने के लिए गंभीर जन चर्चाओं एवं राजनीतिक क्रिया को रोकने में लगाती है। इन सब में पूंजीवादी व्यवस्था अनेक सामाजिक एवं पर्यावरणीय विरोधाभास को उत्पन्न करती है। यह स्पष्ट है कि एक व्यापक, एकीकृत आन्दोलन, जिसमें विभिन्न वर्ग हो, जिनके शोषण एवं संपत्तिहरण के विभिन्न अनुभव हो, की आवश्यकता है। हालांकि यह विपक्ष किस प्रकार व्यवस्थित होता है एवं भौगोलिक सीमाओं और विभिन्न सामाजिक विभाजनों से परे जाता है, अभी निर्माणाधीन है।

यह वैश्विक विद्रोह एक बेहतर विश्व के निर्माण की संभावना प्रदान करता है। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के मूल में पूंजीवाद किस प्रकार विकास के अर्थ को जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्तता और धन को फ्रेम करता है, सम्मिलित है। पूंजीवाद की कार्यप्रणाली मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने एवं पर्यावरणीय ह्रास को बचाने में विरोधात्मक है। पूंजीवादी का क्रांतिकारी, परंतु मुखर रूप से समझदार, विकल्प ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां मुख्य लक्ष्य, उत्पादन एवं निजी धन सम्पदा के संचय खपत को बढ़ाना न हो। इसका लक्ष्य समानता एवं न्याय में संलग्न समुदायों, जहां लोगों की सिर्फ बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो अपितु उन्हें रचनात्म्क वातावरण, अवकाश समय एवं कलात्मक खुशी मिले जिसमें खूबसूरत पर्यावरण सम्मिलित हो, का निर्माण कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इस वैकल्पिक दुनिया के निर्माण में जीवाश्म ईधन, अधिक कारें, अधिक हवाईजहाज, अधिक प्लास्टिक, अधिक इलेक्ट्रोनिक सामान, अधिक शॉपिंग मॉल या अधिक फैक्ट्री फार्म आवश्यक नहीं हैं। इसलिए इसे पर्यावरणीय विनाश की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

संक्षेप में एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जो विविध पारिस्थितिक तन्त्रों, स्थाई जलवायु एवं एक विषहीन पर्यावरण को पोषित करता है, विश्व पर से पूंजीवाद के नियंत्रण को तोड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वह सभी लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर भी प्रदान कर पाये। इस सत्यता के प्रकाश में, पर्यावरण समस्याओं को संबोधित करने वाले नवदारवादी उपागम जो बाजार समाधान एवं प्रौद्योगिकी सुधारों की तालश में हैं, अवश्य असफल होंगे। जरूरत है क्रांतिकारी पर्यावरणीय आन्दोलन की, जो शक्ति को चुनौती देगा एवं सामाजिक–आर्थिक संबंधों के पुर्ननिर्माण के लिए कार्य करेगा, जिससे सारपूर्ण गैर–अलगाववादी कार्य का सृजन होगा। इसमें (किस प्रकार) उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की संस्कृति ने राष्ट्रों के मध्य एवं राष्ट्र के भीतर भी नस्लीय एवं आर्थिक अन्याय को पोषित किया है का सामना और साथ ही पारिस्थितिक तन्त्र पर, निगमों सरकारों एवं विकास संस्थानों द्वारा की जाने वाली सर्वग्राही हमलों को भी खत्म करना है, सम्मिलित है।

इसी प्रकार यदि हमें बेहतर विश्व का निर्माण करना है, तो समाजवादियों, नारीवादियों, उपनिवेशवाद–विरोधियों एवं अन्य जो सामाजिक न्याय के लिये कार्य करते हैं, को समझना चाहिये कि पर्यावरणीय संकट औरों के साथ केवल एक मुद्दा नहीं हैं, बल्कि यह लोगों के शोषण से भी गुथा हुआ है एवं यह पूंजीवाद के अंतर्विरोध के केन्द्र में है। ■

सभी पत्राचार रिचर्ड योर्क को <rfyork@uoregon.edu> पर एवं ब्रेट क्लॉर्क को <brett.clark@soc.utah.edu> पर प्रेषित करें।

> चोक–चेन प्रभाव

तीव्र वृद्धि के पार पूंजीवाद

जेम्स के. गॉलब्रेथ, टेक्सास विश्वविद्यालय, यूएसए और **क्लॉस डोरे**, जेना विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा

'ग्रेट ट्रास्फोरमेशन। द फ्यूचर ऑफ मार्डन सोसाइटीज' पर संगोष्ठी सितम्बर 2019 जेना, जर्मनी में आयोजित होगी।
कॉपीराइटः सराह कॉड्र्स

प्रारंभिक औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने तीव्र वृद्धि के समय को पीछे छोड़ दिया है। इन देशों में तीव्र आर्थिक वृद्धि के अंत के कारणों में से एक है लाभों पर सख्ती करने की प्रवृत्ति जिसे जेम्स गॉलब्रेथ ने "चोक–चेन प्रभाव" कहा है।

यह शब्द इस तथ्य का वर्णन करता है कि संसाधन और ऊर्जा–गहन अर्थव्यवस्था जो 1945 के बाद पूर्व और पश्चिम में समान तरह से उभरी, जिसने उच्च विकास दरों के माध्यम से समृद्धि सुनिश्चित की, अपरिवर्तित ना रह सकी, क्योंकि इस प्रकार की एक अर्थव्यवस्था की दक्षता तब तक ही बढ़ती रह सकती थी जब तक संसाधन सस्ते बने रहें। हालांकि, संसाधन गहनता का अर्थ उच्च निश्चित लागत भी हैं, जिनका एक लम्बे समय में ही वापिस भुगतान किया जा सकता है। ये लागतें तभी उचित हो सकती हैं यदि व्यवस्था की एक लंबे समय के लिये लाभदायक बने रहने की उम्मीद हो। इसलिए, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि की एक केन्द्रीय प्रकार्यात्मक शर्त है। उनकी स्थिरता की आवश्यकताओं के कारण, उच्च निश्चित लागत व्यवस्था विशेष रूप से आद्यात योग्य हैं। परन्तु तब क्या होता है जब समय अनिश्चित हो जाता है और वस्तुओं और ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं? लाभों और निवेश के लिये समय क्षितिज घट गया हैं, और एक कंपनी का कुल अधिशेष और लाभ स्थिर समय की तुलना में कम हैं। चूंकि लाभ सिकुड रहे हैं, सभी स्तरों पर श्रमिकों, प्रबंधन, मालिकों और कर अधिकारियों के मध्य वितरणात्मक संघर्ष गहरे हो रहे हैं क्योंकि सकारात्मक विकास में विश्वास डगमगाने लगा है।

यह "चोक–चेन प्रभाव" आगे और गहरा हो जायेगा यदि (अ) महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी हो, इस अर्थ में कि सामान्य कीमतों पर कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो और (ब) उस वस्तु की आपूर्ति में जमाखोरी और सट्टे से हेरफेर किया जा सकता हो।

श्वान द्वारा पहने चोक कॉलर की तरह, यह प्रभाव आवश्यक रूप से आर्थिक वृद्धि को नहीं रोकता है। परन्तु जैसे ही ऊर्जा संसाधनों की खपत बढ़ती है कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और लाभप्रदता तेजी से घटती है। इससे निवेश कम हो जाता है, यह वृद्धि की धारणीयता के बारे में संदेह पैदा करता है और अन्य आर्थिक उत्तोलकों के (विकृत) कसाव को भी ट्रिगर कर सकता है।

ये विचार जलवायु परिवर्तन की उच्च लागत को भी सम्मिलित नहीं करते हैं। सामग्री और ऊर्जा लागतें 2007-2009 के प्रमुख

>>

संकट का एकमात्र कारण नहीं है, ना ही वे पुराने पूंजीवादी केन्द्रों में तुलनात्मक रूप से से निम्न वृद्धि दरों का अकेला कारण हैं। हालांकि, एक बार जब जलवायु परिवर्तन की कीमतें तीव्र हो जाती हैं, संसाधन के मुद्दे विकास में एक बड़ी बाधा साबित हो सकते हैं। समस्या स्पष्ट हैं : इस ग्रह पर संगठित जीवन को अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखते हुये संगठित बनाये रखने के लिये, कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कटौती आवश्यक होगी, और यह महंगा होगा; इसके अलावा, वर्तमान ऊर्जा–खपत व्यवसायिक गतिविधि का अधिकांश भाग लाभहीन हो जायेगा।

इसके चारों ओर आंतरिक आर्थिक विवाद के बावजूद, पूंजीवाद, वृद्धि और लोकतंत्र की चर्चा के लिये यह विश्लेषण कम से कम तीन तरह से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि पोस्ट ग्रोथ समाज – अधिक सटीक रूप से, धनी उत्तर में तुलनात्मक रूप से कमजोर और बिना वृद्धि वाले पोस्ट–ग्रोथ पूंजीवाद – लम्बे समय से एक सामाजिक वास्तविकता बन गये हैं। इस तरह के विकास के कारण आंशिक रूप से संरचनात्मक, और आंशिक रूप से राजनीतिक हैं। बैंकों को बचाने के लिये निजी ऋणों का सार्वजनिक ऋणों में रूपांतरण से, यूरोजोन के देशों ने समय खरीद लिया है, परन्तु संरचनात्मक आर्थिक असंतुलनों का एक धारणीय समाधान किये गये उपायों में शामिल नहीं है। यूरोपीय मितव्ययता नीति विफल हो गयी है, और यहां तक कि इसके कुछ पैरोकार अब यह स्वीकार भी करते हैं, विशेषतः ग्रीक मामले में।

परन्तु उच्च वेतन और बढ़ी हुई मांग वाली कीन्स की नीतियां वास्तव में एक विकल्प नहीं हैं। वर्तमान प्रस्ताव संरचनात्मक शक्ति अंतर को नजरअंदाज करते हैं जो यूरोपियन ऋण व्यवस्था के साथ आगे समेकित हो जाता है। क्योंकि वित्तीय बाजार वैश्विक रूप से जुड़े हुये हैं, और निवेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोखिमों का आकलन करते हैं, इसलिये व्यक्तिगत देशों में समायोजन बहुत अधिक नहीं होता है। अन्य शब्दों में, संरचनात्मक बाधायें स्थायी आर्थिक सुधारों की राह को अवरोधित करती हैं। यह बहुत सम्भव है कि कुछ देशों और क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था एक लंबे समय के लिये उच्च दरों पर विकसित होंगी, परन्तु वृद्धि तथा वितरण और अधिक असमान होते जा रहे हैं, और कुल मिलाकर अतीत की उच्च विकास की दरों पर वापसी की उम्मीद नहीं हैं।

दूसरा, यदि यह सही है तो इसका अर्थ यह है कि पोस्ट ग्रोथ समाज की अवधारणा की मानक रूप से अतिश्योक्ति करने का या इसे उत्तर–पूंजीवादी विकल्पों के लिये आरक्षित करने का कोई अर्थ नहीं है। इसके बजाय, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि पूंजीवाद और लोकतंत्र के बीच सम्बन्ध के लिये धीमी वृद्धि के साथ स्थायी कम वृद्धि दरों का क्या अर्थ है। यह स्पष्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्थायें लंबे समय तक उनके सामाजिक–आर्थिक ढांचे के केन्द्र में बिना बदलाव के ठहर (जापान, इटली को देखें) या सिकुड (ग्रीस) सकती है। और इसकी शक्ति संरचना में, कमजोर वृद्धि दर के साथ अपेक्षाकृत स्थिर पूंजीवाद इस तरह लम्बे समय के लिये सम्भव है – परन्तु क्या यह लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर भी लागू होता है या नहीं, ये दूसरा मामला है।

तीसरा, इसका मतलब यह भी है कि जब हम यह तर्क देते हैं कि तीव्र वृद्धि की ओर लौटना सम्भव नहीं है, पूंजीवाद और वृद्धि का और ठहराव या सिकुडती अर्थव्यवस्था के विचार की एक व्यापक समालोचना आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। बल्कि, एक सचेत रूप से धीमी गति से बढ़ती नयी अर्थव्यवस्था जो अपने कार्यकारी तंत्र में इसकी जैवभौतिक नींव को सम्मिलित करती है, एक समाधान हो सकती है। एक स्थिर या सिकुडती अर्थव्यवस्था हमेशा कुछ विजेताओं और कई हारे हुये लोगों को पैदा करेगी। इन कारणों से भविष्य में एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि की जरूरत है, जो लम्बे समय के लिये धीमी, स्थिर वृद्धि की गारंटी दे सके। हम धीमी वृद्धि के साथ एक विकेन्द्रीकृत पूंजीवाद को वांछित मानने का सुझाव देते हैं। ऐसा पूंजीवाद, हालांकि, अपनी वित्तीय किस्मों से काफी अलग होगा। इसे संस्थाओं और संगठनों (सैन्य) के आकार को महत्वपूर्ण रूप से कम करना होगा जिनकी निश्चित लागत में संसाधनों का व्यापक उपयोग शामिल है, और समग्र रूप से बैंकिंग क्षेत्र को समाप्त करना होगा। यह सभी नागरिकों के लिये एक सभ्य जीवन स्तर को सुनिश्चित करेगा, जल्दी सेवानिवृति को संभव करेगा, न्यूनतम मजदूरी को दृढ़ता से बढ़ायेगा श्रमिकों पर करों के बोझ को हल्का करेगा परन्तु उत्तराधिकार और उपहार करों में काफी वृद्धि करेगा। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, यह निष्क्रिय संचयन के बजाय सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से धारणीय बुनियादी ढ़ांचे पर सक्रिय खर्च को सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करेगा। क्या यह यथार्थवादी परिदृश्य है, यह एक खुला प्रश्न है।

समाजशास्त्र को इसके उत्तर की खोज में शामिल होना चाहिये। जर्मन यूनिवर्सिटी शहर जेना में सितम्बर 2019 के अंत में होने वाले सम्मेलन *"ग्रेट ट्रांसफोर्मेशंसः द फ्यूचर ऑफ माडर्न सोसायटीज्"* के एक हिस्से के रूप में एक प्रयास किया जायेगा। वहां, हम एक अनुसंधान नेटवर्क शुरू करना चाहते हैं जो समाजशास्त्रीयों और अर्थशास्त्रीयों के लिये तीव्र वृद्धि के पास के भविष्य पर वैश्विक चर्चा में भाग लेने की संभावनाओं को खोलेगा। ■

सभी पत्राचार क्लॉस डोरे को <klaus.doerre@uni-jena.de> पर प्रेषित करें।

> पोस्ट–ग्रोथ स्थितियां

एरिक पिनाउल्ट, डू क्यूबेक अ मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, कनाड़ा और पोस्ट–ग्रोथ समाजों पर शोध समिति, जेना विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा

आर्थिक वृद्धि लम्बे समय तक पश्चिमी राजनीति के केन्द्र में रही है।
फोटो : LendingMemo.com./फ्लिकर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

पूंजीवादी समाज में वृद्धि के कई अर्थ और निहितार्थ होते हैं जैसा वह इसके अंत और टूटने के दशकों में करता रहा है। यह एक भौतिक तथ्य है, आर्थिक पैमाने का मौद्रिक प्रतिनिधित्व, और एक विचार भी है, एक केन्द्रीय विचार जिसे एक पूंजीवादी समाज में चुनौती देना मुश्किल है। वृद्धि के बाद की स्थितियां यहां उस संदर्भ की तरफ इशारा करती हैं जहां यह चुनौती आवश्यक ही नहीं अवश्यम्भावी हो जाती है।

वृद्धि के पहले उदाहरण में वृद्धि को जीडीपी और अन्य राष्ट्रीय खातों किसका मापन करते हैं के संदर्भ में देखा जा सकता है: एक मौद्रिक उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में पूंजीवाद का आकार और गतिशीलता। इसमें माल उत्पादन (उत्पाद) का मूल्य और उपभोग की वस्तुओं (मांग) की मात्रा भी शामिल है, स्टॉक का संचय और निश्चित पूंजी में किया गया निवेश भी शामिल है जो मूर्त (मशीनें) और अमूर्त (आर एंड डी, पेटेंट) के रूप में हो। यह रोजगार में बदलकर श्रमिकी, लाभ, कर, ब्याज और लाभांश के रूप में मौद्रिक आय पैदा करता है।

इस संकीर्ण आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्धि का अर्थ अधिक उत्पाद और अधिक उत्पादन करने की क्षमता दोनों है। प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होकर वृद्धि दर इस विस्तार प्रक्रिया की तीव्रता का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक पूंजीवादी समाजों में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति के रूप में एक संख्या है जिसे जीडीपी कहते हैं और इसकी निर्मिति असंख्यक सामाजिक और भौतिक संबंधों को अभिव्यक्त और निर्वहित करती हे। वृद्धि की कम दर से पूंजी, श्रम और राज्य के मध्य वितरण के विरोधाभास पैदा होने की स्थिति पनपेगी। वृद्धि दर में लम्बी गिरावट (धर्मनिरपेक्ष ठहराव) अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति पैदा करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गिरती दर एक आत्मनिर्भर घटना है : राज्य खर्चों में कटौती करते हैं; कॉरपोरेट निवेश रद्द करते हैं और उत्पादन में कटौती करते हैं; पूंजीपति या तो मुनाफा कमाते हैं या उन्हें वित्तीय क्षेत्र में स्थानांतरित करते हैं; श्रमिक अपनी वर्गीय सामूहिक शक्ति को खो देते हैं क्योंकि वे रक्षात्मक संघर्षों में विभाजित हो जाते हैं और उन अर्थव्यवस्थाओं में मांग की स्थिति कमजोर हो जाती है जिन्हे मजदूरी द्वारा वृद्धि गतिशीलता प्राप्त होती है। सन् 2008 में संकट के बाद इसे कई मुख्य पूंजीवादी देशों ने अनुभव किया है।

तब, वृद्धि पूंजीवादी समाजों के आंतरिक वर्गीय विरोधाभासों को विनियमित करने का एक केन्द्रीय साधन है। शोषण के माध्यम से संचय पर स्थापित, पूंजीवाद वृद्धि में स्थिरता पाता है : मुनाफे का साथ मिलने से श्रमिकी में वृद्धि होती है; उच्च निवेश के साथ पूर्ण रोजगार पैदा होता है; वर्ग संघर्ष दिखाई देने लगता है और

>>

प्रबंधनीय हो जाता है; बढ़ता हुआ अधिशेष अधिकांश लोगों के बढ़ते जीवन–स्तर के अन्तर्गत खप जाता है और यह सब एक व्यापक कल्याणकारी राज्य भी करता है। यदि वृद्धि एक दर से नीचे आ जाती है तो सब कुछ बिगडने लगता है। यह पूंजीपतियों के लिए तुरंत एक चिंता का विषय नहीं है जो उत्पादन से अधिक मुनाफा निकालकर इस अस्थिरता की भरपाई कर सकते हैं। बेशक यह आगे मांग और वृद्धि को कम करता है क्योंकि यह श्रमिक की आय है जिसे अंततः सिकोडा गया है, लेकिन श्रमिक हमेशा क्रेडिट कार्ड का सहारा ले सकते हैं या उत्पाद को कहीं अन्य उन उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है जो निचुडे नहीं गये हों। इस सम्मिश्रण में यह मजदूर वर्ग के संगठित हिस्से हैं जो 'वृद्धि के मांगकर्ता' हैं : वे उन नीतियों को प्रस्तावित करते हैं और संघर्ष करते हैं जो उच्च विकास दर को प्रेरित करती हैं: राज्य द्वारा उच्च सामाजिक व्यय, वेतन वृद्धि और अंत में फर्मों द्वारा वास्तविक और रोजगार पैदा करने वाला निवेश हो। यदि धर्मनिरपेक्ष ठहराव, जिसे एक शून्य वृद्धि दर की तरफ गहन रूप से सन्निहित और वर्ग–प्रबलित संरचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में समझा जाता है, वास्तव में उन्नत पूंजीवादी समाजों के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है तब हम भूखे श्रमिकों और सामाजिक आंदोलनों की वृद्धि के विरोधाभासों में होंगे – जिसे हम एक प्रगतिशील वृद्धि का गठबंधन कह सकते हैं – जो उदासीन निगमों और विरक्त पूंजीवादियों का सामना करेगी। कोई भी इस चुनौती की आसानी से कल्पना कर सकता है जो आलोचनात्मक समाजशास्त्र और पूंजीवाद के सिद्धांतो का प्रतिनिधित्व करता है।

जीडीपी स्वयं के संबंध में अर्थव्यवस्था के आकार को मापती है। चूंकि यह मौद्रिक इकाइयों में अभिव्यक्त होती है, ऐसा लगता है जैसे कि पूंजीवाद एक स्व–निहित प्रणाली है जो 'स्वयं पर वृद्धि' करती है। लेकिन हम जानते हैं कि पोलान्यी के बाद से पूंजीवादी संबंध व्यापक सामाजिक संबंधों और संस्थानों के अंदर होते हैं और उसी में वे बढ़ते हैं, जो कभी कभार उनके तर्क से प्रभावित होते हैं, वे कई बार इस प्रक्रिया में वृद्धि के आधारों को भी नष्ट कर देते हैं। नारीवादी सिद्धांत ने 'उपेक्षित' प्रजनन के कार्य और देखभाल पर श्रम, मूल्य और पूंजी की केन्द्रीय निर्भरता को दिखाया है। अर्थव्यवस्था न सिर्फ किन्ही (सामाजिक संबंधों) के माध्यम से वृद्धि करती है बल्कि यह किन्हीं पर बढ़ती है (प्रजनन कार्य एवं देखभाल)। उत्तर–दक्षिण संबंधों पर इसे लागू कर यह तर्क दिया जा सकता है कि उन्नत पूंजीवादी केन्द्रों का विकास एक शाही जीवन स्तर में निहित दबाबों को वैश्विक दक्षिण या परिधी द्वारा बाहर रखने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। जब इसे सामाजिक संबंधों के वस्तुकरण के विस्तार, बाह्यकरण के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाता है और उपेक्षित प्रजनन कार्य पर अधिक गहन मांग के रूप में, प्रगतिशील वृद्धि गठबंधनों द्वारा एक अधिक मजबूत, सुदृढ़ और समावेशी वृद्धि की मांग एक संयत बैचेनी को भड़का सकती है।

यह तब और जटिल हो जाता है जब विकास को एक भौतिक प्रक्रिया की तरह मान लिया जाता है, जब उत्पादन और उपभोग से पैदा अपशिष्टों की निकासी के विघनकारी प्रभाव होते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी, जीवित प्राणियों और वैश्विक जैव–रासायनिक चक्रों पर पड़ने वाले प्रभावों के रूप में देखा जा सकता है जैसे कि जलवायु परिवर्तन का मामला है। अर्थव्यवस्था के बायोफिजिकल स्केल का कुल आकार पारिस्थितिक तंत्रों के सापेक्ष होता है और वैश्विक स्तर पर पृथ्वी की प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ता है जो इसमें अंतर्निहित है और बायोफिजिकल प्रभावों में होने वाली तेजी (ह्रास, प्रदूषण और कृत्रिमता) अपनी अंतर्निहित सीमाओं और सीमित अर्थव्यवस्था का एक नया प्रतिनिधि स्वरूप प्रस्तुत करती है। सामाजिक इकोलॉजी के बढ़ते क्षेत्र ने ऐसी मैट्रिक्स और श्रेणियों का विकास कर लिया है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि और उसके पैमाने को बायोफिजिकल संदर्भों में ग्रहण करती है। समाजशास्त्रीय अनुमान है कि समाज में व्यक्तियों के रूप में हमारे उपापचयों का निर्धारण व्यापक सामाजिक संगठन के उपापचयों द्वारा होता है। सामाजिक–आर्थिक उपापचयों का मापन उत्पादों के लिये आवश्यक पदार्थ और ऊर्जा की प्रवाह प्रणाली से होता है और ये पूंजीवादी समाज में वस्तुओं और सेवाओं में निवेश के रूप में भी देखा जाता है। एक बार जब हम मौद्रिक उत्पादन पर केन्द्रीय अर्थव्यवस्था के किसी भी जैव–भौतिकीय आधार पर विघटित हो जाते हैं, अपदार्थीकृत संचयन (जैसे कि हम ट्विटर फीड बंद कर सकते हैं!) और सुगठित बायोफिजिकल प्रवाह क्षमता और मौद्रिक उत्पादन के कसे हुए संयोजन के साथ शिल्पकृत्तियों (इमारतें, मशीनें और आधारभूत ढांचा) में पूंजी के मूर्त रूप को समझते हैं जो केवल तभी कार्य करती है जब उर्जा और पदार्थ उन्हें उपलब्ध कराये जाएं, तब वृद्धि की जैव–भौतिक सीमा का प्रश्न जीडीपी के समान पुष्ट और स्पष्ट तथ्य बन जाता है।

इस बायोफिजिकल परिप्रेक्ष्य से पोस्ट–वृद्धि की स्थितियों में पूंजीवादी समाज के पारिस्थितिक विरोधाभासों और इसकी आर्थिक वृद्धि के संकेतों को देखा जा सकता है। ये विरोधाभास स्वयं में अंतर्निहित हैं और अब इन्हें द्वितीयक और श्रम और पूंजी के सच्चे अंतर्विरोधों की व्युत्पति की तरह नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार वृद्धि–पश्चात की स्थिति अधिक पारंपरिक ऐतिहासिक भौतिकवाद जिस पर मार्क्स के बाद से महत्वपूर्ण सिद्धान्त विकसित हुए हैं, के साथ एक समृद्ध पारिस्थितिक भौतिकवाद के बारे में है।

चूंकि पूंजीवादी विश्लेषण का यह तरीका पिछले दशकों में विकसित हुआ है, यह स्पष्ट है कि उन्नत पूंजीवाद समाज के उपापचय को कम किया जाना चाहिए। लेकिन इससे यह भी स्प्ष्ट हो गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जैव–भौतिक स्तर को कम करना असंभव है, जैसा कि जॉन बेलैमी फोस्टर ने तर्क दिया है कि जब जीडीपी वृद्धि दर अचानक कम हो जाती है तो बॉयोफिजिकल स्केल उसकी अनुपालना नहीं करता है। पारिस्थितिक रूप से अस्थिर चयापचय और जैव–शारीरिक प्रक्रियाओं में पूंजी के संचयी ट्रेडमिल को बनाये रखने वाले असंख्य तरीकों को पारिस्थितिक सामाजिक सिद्धान्त द्वारा श्रमसाध्य रूप से प्रलेखित किया गया है।

इन पारिस्थितिक अंतर्विरोधों का सामना करने और उनका समाधान करने का तात्पर्य है कि पूंजीवादी समाजों की आर्थिक प्रक्रिया की गति को कम करना। लेकिन उत्पादन के सामाजिक संबंधों का संस्थानीकरण और पूंजीवादी समाजों में उपभोग अर्थव्यवस्था के निरंतर परिमार्जन ओर इसके प्रभावों की गहनता पर आधारित होता है। जितना अधिक यह विरोधाभासों से ग्रसित होगा और विकास में बाधाओं का सामना करेगा उतना ही अधिक सामाजिक वर्गों द्वारा समाधान निकाला जायेगा। आधुनिक पूंजीवादी समाजों की आवश्यकता और चाहत है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि, सामाजिक आर्थिक कारकों से जैव–भौतिक उपापचय कम किया जाये। उनके पास राजनीतिक शब्दावली और कल्पनाओं का अभाव जो उसके अपने अंतर्विरोधों को अभिव्यक्त कर पाये। यह वह समस्या है जो उत्तर–विकास स्थितियां समान्यतः आलोचनात्मक समाजशास्त्र और समालोचनात्मक सिद्धांत के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं। ■

सभी पत्राचार एरिक पाइनौल्ट को <eric.pineault@uni-jena.de> पर प्रेषित करें।

> डी ग्रोथ :
अतिवादी सामाजिक–पारिस्थितिक रूपांतरण का आह्वान

फेडरिको डेमारिया, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बार्सिलोना स्वायत्त विश्वविद्यालय, स्पेन द्वारा

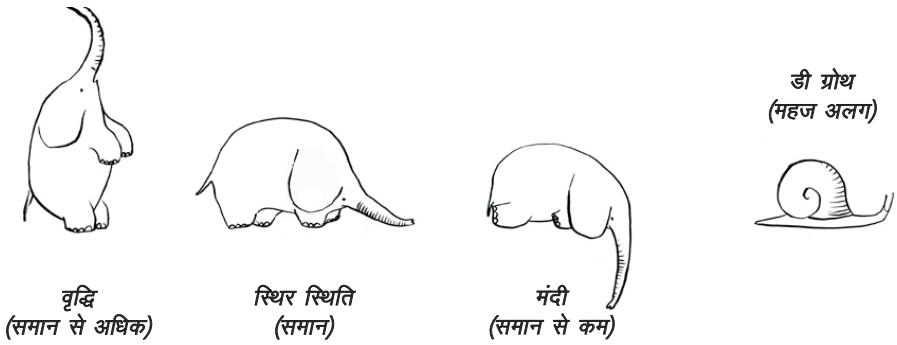

घोंघा डी ग्रोथ आंदोलन का प्रतीक बन गया है। कॉपीराइटः बारबरा कास्त्रो उरीओ।

"वृद्धि की खातिर वृद्धि" सभी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सिद्धान्त रहा है। आर्थिक वृद्धि को दुनिया की सभी समस्याओंः निर्धनता, असमानता, संवहनीयता, जिसका भी नाम लो, के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वामपंथी और दक्षिणपंथी नीतियां सिर्फ इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाये पर भिन्न होती हैं। हालांकि एक असहज वैज्ञानिक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा : आर्थिक वृद्धि पर्यावरणीय दृष्टि से संवहनीय नहीं है। इसके अलावा, एक निश्चित सीमा के बाद, यह सामाजिक रूप से आवश्यक भी नहीं है। फिर मुख्य प्रश्न यह उठता है : हम वृद्धि के बिना अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?

यह प्रश्न विज्ञान से लेकर राजनीति तक, विभिन्न क्षेत्रों में वैधता हासिल कर रहा है। उदाहरण के लिए, सितम्बर 2018 में, यूरोपीय संसद में पोस्ट–ग्रोथ सम्मेलन में 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने 100,000 नागरिकों के साथ अपने खुले पत्र जिसका शीर्षक था "यूरोप, अब वृद्धि निर्भरता का अंत करने का समय है" के द्वारा यूरोपीय संस्थानों से इस पर अमल करने की गुहार की। ऐसा अचानक ही नहीं हुआ। यह बहस कम से कम दो दशकों तक जीवंत रही, जैसा कि 200 से अधिक अकादमिक आलेखों, दस विशिष्ट अंकों, हजारों प्रतिभागियों वाले द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, ग्रीष्मकालीन विद्यालयों और यहां तक कि बार्सिलोना में हमारे विश्वविद्यालय में एक स्नात्तकोत्तर उपाधि से देखा जा सकता है। हमारी पुस्तक *डीग्रोथ : अ वोकेबुलरी फॉर अ न्यू इरा* का दस से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ। पर्यावरणीय दृष्टि से विनाशकारी परियोजनाओं (पर्यावरण न्याय एटलस में मैप किये 2000 से भी अधिक जैसे स्टॉप कोल, प्रोटेक्ट द क्लाइमेट। अभियान, जर्मनी में एंडी गेलेंडे) के विरोध से लेकर कामन्स, एकजुट अर्थव्यवस्था, एवं सह–आवास जैसे विकल्पों के निर्माण वाले महत्वपूर्ण जमीनी पहले प्रारम्भ हो रही हैं। लेकिन डीग्रोथ से हमारा वास्तव में क्या अर्थ है?

आमतौर पर, डीग्रोथ आर्थिक वृद्धि के प्राधान्य को चुनौती देता है और पर्यावरणीय संवहनीयता, सामाजिक न्याय और सुख को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में औद्योगिक देशों में उत्पादन और खपत की लोकतांत्रिक तरीके से अग्रेषित कटौती के पुनर्वितरण का आह्वान करता है। आमतौर पर डीग्रोथ इस विचार से जुड़ा है कि छोटा सुंदर हो सकता है। हालांकि, बल केवल कम पर नहीं अपितु भिन्न पर भी देना चाहिए। एक डीग्रोथ समाज में सबकुछ अलग होगा : गतिविधियां, ऊर्जा, सम्बन्ध, लैंगिक भूमिकाएं, वैतनिक और अवैतनिक कार्य के मध्य समय आवंटन, गैर–मानव दुनिया के साथ सम्बन्ध के स्वरूप और प्रयोजन।

डीग्रोथ का उद्देश्य वृद्धि की जडासक्तिमें डूबे समाज से बचना है। इस तरह का संबंध विच्छेद अतः शब्दों और वस्तुओं दोनों से, प्रतीकात्मक और भौतिक प्रथाओं से, कल्पना के वि–औपनिवेशीकरण और अन्य संभावित दुनिया के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है। डीग्रोथ प्रोजेक्ट अन्य वृद्धि का लक्ष्य नहीं रखता है, न ही अन्य किसी प्रकार के विकास (संवहनीय, सामाजिक, निष्पक्ष इत्यादि) का, बल्कि एक अलग समाज, मित्तव्ययी बहुतायत का समाज (सर्ज लाटौच), एक पोस्ट–ग्रोथ समाज (निकोपेच) या बिना वृद्धि के समृद्धि वाला (टिम जैकसन) के निर्माण का उद्देश्य रखता है। अन्य शब्दों, में प्रारम्भ से ही यह एक आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्रोजेक्ट है जिसका अर्थ है यथार्थ और

>>

डी ग्रोथ पर साहित्य कई भाषाओं में उपलब्ध है।
फोटोः फेडरिको डेमारिया।

साम्राज्यवादी विमर्श के रूप में अर्थव्यवस्था से पलायन करना है। 'साझा करना', 'सादगी', मिलनसारिता', 'देखभाल' और 'कामन्स' यह समाज किस तरह दिख सकता है प्राथमिक अभिप्राय हैं।

यद्यपि यह पारिस्थितिक अर्थशास्त्र को संघटित करता है, डीग्रोथ एक गैर–आर्थिक अवधारणा है। एक तरफ डीग्रोथ का आशय सामाजिक उपापचय (अर्थव्यवस्था की ऊर्जा और सामग्री) में कटौती है ताकि वह मौजूदा जैव भौगोलिक बाधाओं (प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र की आत्मसात करने की क्षमता) का सामना कर सकें। दूसरी तरफ, डीग्रोथ समाज बाजार आधारित सम्बन्धों की सर्वव्यापकता और सामाजिक कल्पना के वृद्धि आधारित जड़ो को चुनौती देने का एक प्रयास है जो उन्हें मित्तव्ययी बहुतायत के विचार से प्रतिस्थापित करता है। यह एक अधिक गहन लोकतंत्र के लिए भी आह्वान है जो मुख्यधाराई लोकतांत्रिक क्षेत्र के बाहर रहने वाले मुद्दे जैसे प्रौद्योगिकी, पर लागू होता हे। अंत में, डीग्रोथ का आशय वैश्विक उत्तर और दक्षिण के मध्य और इर्दगिर्द के साथ वर्तमान और भावी पीढ़ियों के मध्य धन का न्यायोचित पुनर्वितरण है।

पिछले कुछ दशकों में, वृद्धि के एकल–विचारधारा का विजयी चेहरा "सतत विकास" के कदाचित सहमतिजन्य नारे, एक अच्छा विरोधाभास, के अन्दर सन्निहित है। उसका लक्ष्य पारिस्थितिक संकट में आर्थिक वृद्धि के धर्म को बचाने का प्रयास करना था। यह विचार वैश्वीकरण–विरोधी आंदोलनों द्वारा अच्छी तरह स्वीकृत प्रतीत होता है। वैश्वीकृत बाजार के पूंजीवाद को एक अन्य सभ्यतागत प्रोजेक्ट के द्वारा विरोध करना या अधिक विशेष रूप से, लम्बे समय से निर्मित योजना जो भूमिकत प्रगति कर रही थी को दृश्यता प्रदान करना आवश्यक हो गया था। विकासवाद, तथाकथित विकासशील देशों के काम के लिए उत्पादवाद का एक स्वरूप, का सम्बन्ध–विच्छेद इस प्रकार की वैकल्पिक प्रोजेक्ट की नींव था।

1972 में राजनीतिक पारिस्थितिकी विज्ञानी एंड्रे गोरज ने 'डीग्रोथ' शब्द का प्रस्ताव दिया गया और इसे 1979 में निकोलस जार्जसस्कू–रोगेन के निबंधों के फ्रेंच अनुवाद के शीर्षक के रूप में लिया गया। बाद में फ्रेंच पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा डीग्रोथ को 2001 में पर्यावरणवाद को पुनः राजनीतिक रंग देने के लिए एक उत्तेजक नारे के रूप में लांच किया गया। डीग्रोथ के आदर्शवाक्य को दोगलेपन से अलग होने की आग्रही आवश्यकता और अक्सर संवहनीय विकास की अर्थहीनता द्वारा लांच किया गया। अतः यह वाक्यांश मूल रूप से एक अवधारणा नहीं है (कम से कम आर्थिक वृद्धि के सममित तो नहीं) बल्कि एक विद्रोही राजनीतिक नारा है जिसका उद्देश्य हमें सीमाओं का अर्थ स्मरण कराना है। डीग्रोथ न मंदी है और न ही नकारात्मक वृद्धि है और इसकी शाब्दिक व्याख्या नहीं करनी चाहिएः डीग्रो के लिए डीग्रो करना उतना ही बेतुका होगा जितना वृद्धि के लिए वृद्धि करना।

डीग्रोथ संक्रमण उतार का एक अनवरत प्रक्षेपवक्र नहीं है बल्कि उन खुशनुमा समाजों में परिवर्तन है जो आमतौर पर सादगी और कम के साथ रहती हैं। ऐसे परिवर्तन को सफल बनाने वाली और ऐसे समाजों को पनपने की अनुमति देने वाली प्रथाओं और संस्थाओं के बारे में कई विचार प्रचलित हैं। डीग्रोथ का आकर्षण चिंतन के विभिन्न स्रोत या धाराओं (जिसमें न्याय, लोकतंत्र और पारिस्थितिकी सम्मिलित हैं) से और स्पष्ट करने की शक्ति; और कृषि विज्ञान से लेकर जलवायु न्याय जैसे विभिन्न विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले विषम कर्ताओं को एक साथ लाने से निखरता है। डीग्रोथ इन विषयों का समपूरक है और एकल–मुद्दे की राजनीति से परे जा कर इन मुद्दों में एक अनुयोगी धागे (नेटवर्कों के नेटवर्क के एक पंच के रूप में) के रूप में कार्य कर इन्हें मजबूत बनाता है।

वास्तव में, डीग्रोथ एक विकल्प नहीं बल्कि विकल्पों का एक आव्यूह है जो आर्थिक अधिनायकवाद के प्रमुख आवरण को उठाकर रचनात्मकता और नियति की बहुलता के लिए मानव–एडवेंचर/जोखिम को पुनः खोलता है। यह होमो–इकोनोमिक्स के मौजूदा पैराडाइम या मार्कुस के एकल–आयामी मानव, ग्रह के समरूपीकरण और संस्कृतियों की हत्या का मुख्य स्त्रोत, से बाहर निकलने के बारे में है। यदि "विकास" अब सामाजिक जीवन को संयोजित करने का सिद्धान्त नहीं है, तो विविधताओं के लिए स्थान है। जैसा जपातिस्तास कहते हैं, यह "एक ऐसी दुनिया होगी जहां कई दुनिया समायेगीं"। विकास के विकल्पों के रूप में विश्वदृष्टि की बहुलता जैसे ब्यून विविर, एफ्रोटोपिया, एवं स्वराज में से डीग्रोथ एक है। हमारी नई पुस्तक *प्लुरीवर्स : अ पोस्ट डेवलेपमेंट डिक्शनरी* में हमने दुनिया भर से सौ से भी अधिक एकत्रित किये हैं। इसलिए डीग्रोथ के लिए तैयार समाधान प्रदान करना सम्भव नहीं है बल्कि किसी भी गैर–उत्पादक सतत समाज के मूल सिद्धान्तों और संक्रमणकालीन कार्यक्रमों के ठोस उदाहरणों को रेखांकित करना है।

डीग्रोथ प्राक्कल्पना का मानना है कि अतिवादी सामाजिक–पारिस्थितिक रूपातंरण आवश्यक, वांछनीय और सम्भव है। सामाजिक गतिकि, कर्ताओ, गठबंधनों, संस्थानों और डीग्रोथ परिवर्तन को निर्मित करने वाली प्रक्रियाओं से सम्बन्धित एहसासों और राजनीतिक प्रश्नों की स्थिति खुली रहती हैं और यूरोप में और उसके बाहर इन पर सक्रिय बहस होती है। समय, न सिर्फ वैज्ञानिक डीग्रोथ जो असहज प्रश्न पूछता है के लिए परिपक्व है बल्कि एक राजनीतिक एजेंडे के लिए भी तैयार है। जैसा पारिस्थितिकी अर्थशास्त्री टिम जैकसन और पीटर विक्टर ने द न्यू योर्क टाइम्स में तर्क दिया : "वृद्धि के बिना दुनिया की कल्पना करना समाज के लिए संलग्न होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों में से है।" ■

सभी पत्राचार फ्रेडरिको डेमारिया को <federicodemaria@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> नारीवाद और डी–ग्रोथ

गठबंधन या आधारभूत सम्बन्ध

एन्ना-सावे-हरनेक, जेना विश्वविद्यालय, जर्मनी, **कोरिन्ना डेंगलर,** वीटा विश्वविद्यालय, जर्मनी और **बारबरा मुरका,** ओरेगन राज्य विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा

कई लोगों को "डी–ग्रोथ" शब्द २००७ के वित्तीय संकट के बाद सिकुड़ती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन डीग्रोथ इसके बारे में नहीं है। कार्यकर्ताओं का नारा "उनकी मंदी हमारी डीग्रोथ नहीं है।" स्पष्ट करता है कि एक अकादमिक विमर्श और एक सामाजिक आंदोलन के रूप में डीग्रोथ को वृद्धि पैराडाइम के अन्तर्गत ऋणात्मक वृद्धि (जैसे मंदी) के विवरण के रूप में गलत नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत, डीग्रोथ बुनियादी तौर पर इस पैराडाइम पर सवाल उठाता है और आर्थिक वृद्धि के दबाव पर समाजों को उनकी निर्भरता से मुक्ति दिलाने की आवश्कयता पर जोर डालता है। इसका अर्थ है कि डीग्रोथ सामाजिक एवं पारिस्थितिक शोषण के निरंतर त्वरण, विस्तार और गहनता पर निर्भर हुए बिना आधुनिक समाजों के पुनरूत्पादन की संभावनाओं की तलाश करता है और स्पष्ट करता है। एक मूर्त आदर्श के रूप में, डीग्रोथ सक्रियतावाद एवं विद्धता सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं पर्यावरणीय रूप से संवहनीय समाज पर एक उर्ध्वगामी परिवर्तन की कल्पना करता है और वैकल्पिक सामूहिक परिपाटियों से बुनियादी संस्थाओं में परिवर्तन की इस वृहद दृष्टि की तरफ संभावित कदमों का सुझाव देता हे। इसलिए और यह एक और सक्रियतावादी नारा है जब हम डीग्रोथ की बात करते हैं, तो इरादे से डीग्रोथ न कि आपदा से, के रूप में इसे संदर्भित करते हैं।

और फिर भी, यदि हम ग्रीस में लागू आर्थिक डीग्रोथ को देखते हैं, तो ऐसी बाते हैं, जिन्हें हम डीग्रोथ विद्वानों और कार्यकर्ताओं के रूप में सीख सकते हैं। ग्रीस में आर्थिक संकट के बाद वृद्धि दरों में गिरावट सामाजिक और लोक सेवाओं के बारे में मुख्य सामाजिक चुनौतियों का कारण बनीं। एक डीग्रोइंग अर्थव्यवस्था का अर्थ था कि नागरिक समाज को सरकारी कर्ज की प्रतिक्रिया के रूप में मित्तव्यतता नीतियों का सामना करना पड़ा। सरकारी खर्चों में कटौती के प्रभावों को कम करने के लिए अस्पताल, बालवाड़ी और मोहल्ले के सामुदायिक नेटवर्कों का निर्माण किया गया। इनमें से कई पहले आर्थिक संकट (जैसे आपदा से डीग्रोथ) के प्रकट प्रभावों के परिणामस्वरूप उभरे थे जैसे थिस्सलुनीक में समन्वय क्लिनिक उन विचारों (आदर्शों) से मेल खाते हैं जिन्हें डीग्रोथ "इरादे" के अनुसार निर्मित करना चाहते हैं। लेकिन वे एक स्थापित नारीवादी चिंता के बारे में भी बोलते हैं : विशेष रूप से ग्रीक मामले में, महिलाएं संकट द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई क्योंकि उन्होंने मित्तव्यतता नीतियों द्वारा निर्मित अंतर को भर दिया। जहां थोड़े अधिक पारम्परिक पुरुष नौकरियां अलोप हुई, महिलाओं ने पूर्व में लोक सेवाओं के दायरे में, विशेष रूप से देखभाल क्षेत्र में और सामाजिक पुनरूत्पादन से सम्बन्धित गतिविधियों के बड़े हिस्से का भार उठाया। ग्रीस का उदाहरण नारीवादियों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है कि आपदा द्वारा डीग्रोथ और संभवतः इरादे से भी, महिलाओं के लिए काफी जोखिम भरी हो सकती है और इसकी सामाजिक पुनरुत्पादन और देखभाल कार्य के पुनः पारम्परिककरण में योगदान देने की संभावना है। यह नारीवादी सरोकार डीग्रोथ पथ को रेखांकित करने वाली विद्वता जो बुनियादी सामाजिक संस्थाओं जैसे श्रम और सभी के लिए अच्छे जीवन की परिस्थितियों के पुनर्संयोजन की मांग नहीं करती है, के द्वारा आगे और सुदृढ़ होती है। डीग्रोथ की अपेक्षाकृत रूढ़िवादी समझ के खिलाफ अधिक अतिवादी परिपेक्ष्य जैसे "नारीवादी और डीग्रोथ गठबंधन" (एफएडील) के अन्तर्गत जीवन्त चर्चा एक डीग्रोथ समाज की मुक्तिबोधक क्षमता को उजागर करती है। ऐसा वे नारीवाद के विभिन्न स्वरूपों और परम्पराओं द्वारा प्रेरित मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर निर्मित हो कर करती हैं।

डीग्रोथ विमर्श को बल मिलने के बहुत पहले नारीवादी कार्यकर्ताओं, विद्वानों और पर्यावरणविदों के मध्य गहन विचार–विमर्श हुआ है। उदाहरण के लिए, 1980 के दशक में जर्मनी द्वारा विकसित निर्वाह परिपेक्ष्य ने पर्यावरणीय चिंताओं और महिलाओं एवं उपनिवेशों के शोषण के मध्य अंतसम्बन्धों पर जोर दिया। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र का 1997 का विशिष्ट अंक "महिला, पारिस्थितिकी एवं अर्थशास्त्र" इस प्रयास में एक और मील का पत्थर था। जहां यह संवाद डीग्रोथ पैरोकारों द्वारा अधिकाधिक माना जा रहा है, नारीवादी तर्क अभी भी डीग्रोथ प्रस्ताव का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है।

हम तर्क देते हैं कि डीग्रोथ को अभी भी नारीवादी परम्पराओं से बहुत कुछ सीखना है; नारीवादी योगदान डीग्रोथ द्वारा कल्पित न्यायपूर्ण एवं समन्वय–अभिमुखित सामाजिक–पारिस्थितिक रूपांतरण के लिए आवश्यक हैं। पहला, पारिस्थितिक नारीवाद की एक मुख्य अंतदृष्टि यह है कि "प्रकृति" (जिसे पश्चिमी चिंतन परम्परा में "स्त्री" के रूप में निर्मित किया जाता है) और "सामाजिक पुनरूत्पादन" (जो प्राकृतिक/स्वाभाविक रूप से घटने वाला माना जाता है) पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया का मूल आधार है। फिर भी, पूंजीवादी वृद्धि पैराडाइम के

>>

“ डी ग्रोथ द्वारा कल्पित न्याय संगत और एकजुटता–उन्मुख सामाजिक–पारिस्थितिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए नारीवादी योगदान आवश्यक है ”

अन्तर्गत दोनों का ही संरचनात्मक रूप से अवमूल्यन किया जाता है, वे अलोप होती हैं और दैनिक आधार पर नष्ट किया जाता है। डीग्रोथ को सामाजिक और पारिस्थितिक पुनरूत्पादन के समानांतर शोषण एवं अवमूल्यन को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और उन्हें एक अधिक संवहनीय मानवीय–प्रकृति संबंध को बनाने के अपने संघर्ष में प्रमुख घटक बनाना है। दूसरा, नारीवादी सिद्धांतों ने बहुत पहले वृद्धि पैराडाइम में सन्निहित शक्ति सम्बन्धों का खुलासा किया था। उदाहरण के लिए, मारिया माइस का पितृसत्ता और ''कभी न अंत होने वाले संचय के पैराडाइम'' और ''वृद्धि'' के मध्य सम्बन्धों का 1986 का वृत्तान्त दर्शाता है कि नारीवादी और डीग्रोथ आंदोलन के मध्य क्रॉस–निषेचन न सिर्फ संभव है अपितु पूंजीवाद में उत्पीड़न की संरचनाओं का पूर्णतः सम्बोधित करने के लिए आवश्यक है। तीसरा, नारीवाद ने देखभाल को परिवारों या निजी क्षेत्र में पुनः आवंटन, जिसे बिना रूपांतरण के आर्थिक सिकुड़न आवश्यक रूप से लाता है के बजाए देखभाल को कामन्स के रूप में नियोजित करने के सिद्धांतों को व्यक्त और कार्यप्रणालियों को समर्थन दिया है। अमाया पेरेज ओरोज्को के ''जीवन की सवंहनीयता'' का वृत्तान्त एक डीग्रोथ समाज में देखभाल कार्य की कल्पना करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिन्दु प्रदान करता है।'' देखभाल का सामान्यीकरण'' भी व्यक्तिगत, अवसर महिला देखभालकर्मी का समर्थन करता है और जैसा कि सिल्विया फेडेरिसी ने बताया कि देखभालकर्मियों के मिलने, आदान–प्रदान करेन और राजनीतिक आवाज विकसित करने के लिए कए सामाजिक स्थान प्रदान करता है। देखभाल को संयोजित करने का यह तरीका डीग्रोथ प्रथाओं की व्यापक श्रृंखला के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है।

यद्यपि, नारीवाद और डीग्रोथ के मध्य संवाद को बढ़ावा दे कर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, इस तरह के प्रयास में कई चुनौतियां भी हैं। नारीवाद के कुछ धड़ों की इसमें भाग लेने की संभावना कम हो सकती है। अत्यधिक संवादात्मक साझेदारों पारिस्थितिक नारीवाद और डीग्रोथ में भी उनके द्वारा भरोसा की गई भिन्न शब्दावलियो के कारण उनके आपसी समझ में अभाव पैदा हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, त्वरित पारिस्थितिक आपदा की वास्तविक और महसूस की गई की अत्यावश्यकता के मद्देनजर, हस्तक्षेप अधिक जोखिमपूर्ण सामाजिक समूहों जिसमें आमतौर पर सामाजिक पुनरूत्पादन करने वाले सम्मिलित हैं, के निहितार्थों की उपेक्षा करने का जोखिम उठाते हैं। जैसा फैडेरिसी ने हाल ही में (2018) में दिखाया, हम दुनिया भर में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में वृद्धि का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से उनमें जो स्थानीय समुदायों को निर्वाह, स्वदेशी ज्ञान और देखभाल से एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी हैं। कुलीन वर्ग के लिए वृद्धि सुनिश्चित करने के नवउदार धर्मयुद्ध के तहत वैश्विक ''अनुलग्नकों'' की एक नवीकृत लहर से हिंसा अग्रेषित होती है। यही कारण है कि समय के दबाब के बावजूद डीग्रोथ सक्रियता और विद्वता के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि वे पितृसत्ता की चुनौती, जो जैसा हमने पहले इंगित किया है, पूंजीवादी वृद्धि पैराडाइम से नजरीकी से जुड़ी है, को कमतर करने के जाल में न फंसें।

नारीवाद को डीग्रोथ आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने की चुनौती एफएडीए नेटवर्क के जीवंत चर्चाओं में प्रतिबिंबित होती हैं। कुछ सदस्य तर्क देते हैं कि दो विमर्शों और आंदोलनों के मध्य गठजोड़ बनाने की कोशिशों के बजाए, जिससे उनके सम्बन्ध केवल एक संभावना के रूप में फ्रेम हों और समान संघर्ष में अंतर उजागर होंगे, इन दोनों के मध्य आधारभूत सम्बन्धों पर फोकस होना चाहिए। वृद्धि पैराडाइम के परे समाज के आमूल परिवर्तन को पूंजीवादी वृद्धि दबाब और इसे संयोजन में गहरी पितृसत्तात्मक जड़ो को सम्बोधित करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। नारीवाद और डीग्रोथ का समन्वय करना एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है जिसमें हम सभी आमंत्रित हैं। नारीवादी डीग्रोथ समाज के सृजन के लिए वैश्विक संवाद में संलग्न होना हमारा कर्त्तव्य है। ■

सभी पत्राचार
एन्ना–सावे–हरनेक को <anna.saave.harnack@uni-jena.de> पर
कोरिन्ना डेगलर को <corrina.dengler@uni-vechta.de> पर
बारबरा मुरका को <abarbara.muraca@oregonstate.edu> पर
प्रेषित करें।

> एक डी ग्रोथ रणनीति के लिए चुनौती

ग्रीस का मामला

ग्रेबियल साकेलरिडिस, एथेंस विश्वविद्यालय, ग्रीस द्वारा

लंदन में "ग्रीस को सांस लेने दो" का प्रदर्शन, 2015.
शीला/फ्लिकर।
कुछ अधिकार सुरक्षित।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में यह स्वयं सिद्ध माना जाता है कि अपने नागरिकों की समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिये एक देश में आर्थिक वृद्धि जरूरी है। वृद्धि का आकर्षण, हालांकि, सिर्फ सार्वजनिक चर्चाओं और वैज्ञानिक प्रतिमानों में प्रचलित प्रमुख विचारों के एक सेट के रूप में नहीं समझा जाना चाहिये। वृद्धि की देवसदृश्यता शक्तिशाली अकादमिक अभिजात वर्ग और वोट मांगने वाले राजनीतिज्ञों के द्वारा लागू की गयी "विकास विचारधारा" का एक साधारण मामला नहीं है। इसके विपरीत, इस "विकास विचारधारा" को पूंजीवादी उत्पादन के तरीको को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली कानूनों के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिये, जिनके अनुसार प्रतिस्पर्धा, पूंजी संचयन और अधिकतम लाभ कमाना इनके आनुवांशिक संकेतों में बसा है।

विकास की अनिवार्यता को डी ग्रोथ के विचार के द्वारा प्रतिद्वंदित किया गया है, जो पर्यावरणीय संकट के लिये बढ़ती चिंता के साथ उभरा है। संक्षेप में डी ग्रोथ को एक सामाजिक और पारिस्थितिकीय रूप से लाभकारी तरीके में "उत्पादन और उपभोग के समानानुपातिक कमी" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वृद्धि अनिवार्यता के मुकाबले में, डी ग्रोथ सिद्धांतवादी और कार्यकर्ता तर्क करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन, कार्य दिन की लम्बाई, जीवन की गुणवत्ता एवं अन्य कई कारकों के द्वारा वृद्धि के लिये विशिष्ट सामाजिक बाधायें हैं। जीडीपी को समृद्धि का एक भ्रामक संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण चरों को छोड़ देता है जो मौद्रिक संदर्भों में व्यक्त नहीं किये जाते हैं और इसके अलावा, समाज को उत्पादनवाद और उपभोक्तावाद की दौड में बांधता है।

हाल ही में वित्तीय संकट के बाद की वैश्विक मंदी के प्रकाश में, अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन मॉडल विवादित रहा है। जहां अर्थशास्त्रीयों ने वैश्विक चालू खातों के असंतुलनों के संदर्भ में अधिकतर प्रश्न उठाये हैं "डी ग्रोथ शिविर" से पैदा हुई, कई आलोचनायें रही हैं जो इस संकट को वृद्धि की खोज से दूर सामाजिक प्राथमिकताओं को पनु:ग्रहित करने के एक अवसर के रूप में देखती हैं।

ग्रीस थोपी गयी मितव्ययता के प्रभाव से संबंधित सार्वजनिक बहसों का उपरिकेन्द्र रहा है, जैसा कि देश ने महामंदी के बाद विकसित पूंजीवादी देशों में सबसे गहरी मंदियों में से एक को अनुभव किया है; इसने 2008 से 2017 के बीच में अपनी वास्तविक जीडीपी को 28.1 प्रतिशत खो दिया, जबकि उसी काल में बेरोजगारी 7.8 प्रतिशत से 21.5 प्रतिशत पर पहुंच गयी (2013 में 27.5 प्रतिशत के शीर्ष पर)। आर्थिक संकट ने देश को एक गहरे सामाजिक संकट में धकेल दिया, जो एक गहरे प्रतिनिधित्व संकट के रूप में राजनीतिक स्तर पर भी परिलक्षित होता हैं जहां आरोपित राजनीतिक पहचान और दल संबद्धता ध्वस्त हो गयी, जबकि नयी आकार ले रही थी।

सामाजिक परिदृश्य को देखते हुये, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या धारणीय और जानबूझकर की गयी डी ग्रोथ रणनीति लाभदायक साबित हो सकती है। यदि नहीं, जैसा कि यहां तर्क दिया है यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि कौन से प्रमुख तंत्र थे जिन्होंने इसे इतना कठिन बना दिया। डी ग्रोथ की चुनौती को इसके एजेंडा को अस्वीकार करने के कारण की तरह नहीं माना जाना चाहिये, परन्तु इसके विपरीत, डी ग्रोथ सिद्धांतकारों द्वारा इस अपनी रणनीतियों की नीवं को मजबूत करने में उत्पन्न में बाधाओं पर काबू की तरह देखा जाना चाहिये।

>>

जैसा कि आगे के दो अनुच्छेदों में स्पष्ट हो जायेगा, ट्रोइका नीति निर्देश ओर वाम विकल्प, दोनों वृद्धि की धुरी के चारों और घूमते हैं और इसलिये सम्पूर्ण सार्वजनिक बहस वृद्धि की अनिवार्यता के आसपास विकसित हुई।

ट्रोइका के द्वारा अपनायी गयी नीति ने ग्रीक अर्थव्यवस्था के लिये निवेश और निर्यात जनित वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयास किया। उन्होंने श्रम और उत्पाद बाजार के आंतरिक अवमूल्यन और संरचनात्मक सुधारों के सुझावों को आगे बढ़ाते हुये, और वास्तविक विनिमय दर को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की एक रणनीति के रूप में लक्षित करने और ग्रीक अर्थव्यवस्था को एक ने चक्र में रखने का उद्देश्य रखा। हालांकि, इसके परिणाम ग्रीक लोगों के एक बड़े हिस्से के लिये भयानक साबित हुये।

ट्रोइका नीति के लिये वाम द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग दो प्रकार के थे। एक ओर, वे जिन्होंने यह वकालत की कि ग्रीस को यूरोजोन में रहना चाहिये परंतु वे "मितव्ययता–विरोधी" खेमें में रहे, ने एक नये "मार्शल प्लान" का प्रस्ताव दिया जो सार्वजनिक निवेश और साथ ही समग्र मांग प्रबंधन को बढ़ा देगा, जिससे निजी खपत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीक सार्वजनिक ऋण की पुर्नसंरचना के साथ संयोजन में, यह नीति इसकी धारणीयता सुनिश्चित करेगी और कीनेसियन तंत्र के माध्यम से नौकरियां और आय पैदा करेगी। दूसरी ओर, ग्रेक्सिट के समर्थकों ने दावा किया कि यूरो के खिलाफ अवमूल्यन की गयी एक नयी राष्ट्रीय मुद्रा को अपनाने से निर्यात बढ़ेगा और आयात घटेगा, जो उत्पादन पर आधारित निर्यात जनित वृद्धि और आयात प्रतिस्थापन के संयोजन तक ले जायेगी।

ग्रीस में एक ठोस डी ग्रोथ वृत्तान्त के विकास के लिये पहली चुनौती सार्वजनिक ऋण स्थिरता और इसके उत्पादन वृद्धि से संबंध से पैदा होती है। जिस क्षण से ग्रीस एक सार्वजनिक ऋण करदान क्षमता संकट का सामना कर रहा था, कम से कम आलंकरिक रूप से में ऋण स्थिरता चल रही नीतियों का लक्ष्य बन गयी। राजकोषीय ऋण स्थिरता के लिये मुख्य चर राजकोषीय प्राथमिक जमा राशि और सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दरों और मामूली उत्पादन वृद्धि दरों के मध्य संबंध हैं। यदि मामूली वृद्धि दर ब्याज दरों से कम हैं तब तथाकथित "स्नोबॉल प्रभाव" शुरू हो जाता है, जो प्राथमिक अधिशेष के तहत भी राजकीय ऋण को बढा देता है। तब उत्पादन वृद्धि सार्वजनिक ऋण स्थिरता के लिये सबसे महत्वपूर्ण चर बन जाती है। ऐसी दवाब वाली परिस्थितियों में, डी ग्रोथ रणीनतियों के प्रस्ताव में बहुत कम आकर्षण रह जाता है।

दूसरी चुनौती समकालीन पूंजीवाद के वित्तीय रूप से उत्पन्न होती है और और ऋण अपस्फीति से जुड़ी है, जो अर्थव्यवस्था को एक "निजी ऋण मंदी" के दुष्चक्र में उलझा देती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं धन–उत्पादन की अर्थव्यवस्थायें हैं, और उनकी इकाईयों की बैलेंस शीट एक जटिल वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं। अत्यधिक निजी ऋण की उपस्थिति के तहत, मंदी ऋण अपस्फीति तक जाते हुये ऋण के बोझ को बढ़ा देती है।

तीसरी चुनौती बेरोजगारी और इसकी सहवर्ती सामाजिक लागत से जुड़ी हुयी है। यह तर्क देने की जरूरत नहीं है कि बेरोजगारी दरें जो 2013 में 27.5 प्रतिशत तक पहुंच गयी, जबकि यह 2007 में 7.8 प्रतिशत थी, ने ग्रीक समाज की नींव को हिला दिया, और महत्वपूर्ण राजनीतिक जोखिम भी पैदा किया। यह देखते हुये कि बेरोजगारी आर्थिक वृद्धि से मजबूत सकारात्मक सहसंबंध रखती है, ग्रीस में नीतिगत एजेंडा अपरिहार्य रूप से वृद्धि रणनीति से बंधा है, जो वास्तविक राजनीतिक समय में उच्च बेरोजगारी को संबोधिक करने के दवाब के साथ पथ–निर्भरता के बने रहने का कारण पैदा करता है। अन्य शब्दों में, चूंकि नयी नौकरियों के सृजन में सक्षम डी ग्रोथ की रणनीतियों की कोई तैयारी नहीं थी, "हमेशा की तरह व्यापार" प्रतिमान सार्वजनिक बहस पर हावी रहा, अर्थात उच्च वृद्धि–ज्यादा नौकरियां।

चौथी चुनौती इस तथ्य से पैदा होती है कि मंदी के दौरान ग्रीस जैसी एक पूंजी प्रवाह के लिये भूखी अर्थव्यवस्था ने निवेश को आकर्षित करने के लिये अपने पर्यावरणीय मानकों में महत्वपूर्ण कमी की। फास्ट ट्रैक निवेशों पर नये कानून ने उपरोक्त प्रवृति की, पुष्टि की है। निवेश के ऐसे कई उदाहरण हैं जो संकट से पहले सामाजिक प्रतिरोध को बढ़ा सकते थे, परन्तु आजकल सामाजिक रूप से वैद्य माने जाते हैं। इसमें उत्तरी ग्रीस के चलकीडिकी में नयी सोने की खदानों सहित निष्कर्षण परियोजनाएं या अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं जिन पर ग्रीस सरकार ने आयोनियमन और क्रेतन समुद्रों के प्राकृतिक गैस भंडारों और तेल के दोहन के लिये तेल कंपनियों से अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं। विकास की इस तृष्णा का दूसरा उदाहरण एलीनिकों में पूर्व एंथेस हवाईअड्डे को रियायत देना है, जिसको वर्तमान सरकार ने विदेशी और घरेलू निवेशकों के दवाब में एक वृहद रियल एस्टेट योजना द्वारा एक महानगरीय पार्क में परिवर्तित करने की प्रतिबद्धता दे दी है। चुनौतियों की आर्थिक प्रकृति जिसका सामना "डी ग्रोथ एजेंडो" को करना पड़ता है, अर्थवाद को स्वीकृति नहीं देता है। यह, हालांकि, विशिष्ट बाधाएं उत्पन्न करता है जिनको उनकी वृद्धि अर्थव्यवस्था" में महत्ता के कारण समझने की जरूरत है। "अर्थवाद के पहलुओं" के रूप में उनको नजरअंदाज करना सच्चाई को अनदेखा करना है और यह एक डी ग्रोथ रणनीति की संभावनाओं को कमजोर करता है।

उसी समय, यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि उत्पादन को संगठित करने या उपभोग के स्वरूप पर सवाल उठाने के वैकल्पिक तरीके ग्रीस में संकट के समय नहीं उभरे। इसके विपरीत, इस तरह की कई पहलों का जन्म हुआ, जिसमें समय बैंक, शहरी बागबानी, कृषि उत्पादों और यहां तक कि स्व–प्रबन्धित व्यापार उपक्रमों के लिये "बिना बिचौलिया" नेटवर्कों, यद्यपि स्थानीय स्तर पर, सम्मिलित थे। फिर भी, ये पहले अक्सर खंडित थी और एक व्यवहारिक विकल्प शामिल नहीं करती थी, खासकर एक गहरी मंदी की दवाब डालने वाली परिस्थितियों में। हालांकि ये सामाजिक जरूरतों की प्रमुख धारणा पर वैचारिक रूप से सवाल उठाते हुये और उन्हें पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक लोकतंत्र की ओर पुनर्निदेशित करते हुये सामाजिक संगठन के एक विरोधी प्रतिमान के बीज को संपुटित करती हैं। वे अर्थवाद का विरोध करती हैं और उत्पादन और उपभोग पैटर्न के केन्द्र में सामाजिक जरूरतों को रखते हैं। ■

सभी पत्राचार ग्रेबियल साकेलरिडिस को
<gabriel.sakellaridis@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> चिली : नवउदारवाद से पोस्ट ग्रोथ समाज तक?

जॉर्ज रोजस हर्नांडेज, यूनिवर्सिडाड डी कॉन्सेपियन, चिली द्वारा

परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवहारिक के साथ आदर्शवादी विचारों की भी आवश्यकता है। टाइम्स अप लिंज/फ्लिकर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

अपने अपेक्षाकृत छोटे इतिहास में, चिली कई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक शासनों का गवाह रहा है। कुछ सरकारों ने सुधारों और कुछ ने क्रांतियों का वादा किया, लेकिन ऐसा करने से संघर्ष अधिक गहरे हुए। फ्रेंते पॉपुलर का मध्य–वाम गठबंधन शासन 1938 में शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला। वर्ष 1964 में एदुअर्दो फ्री मोंतालवा ने क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीता। उनकी सरकार ने समाजवाद और पूंजीवाद के विकल्प के रूप में तीसरी धारा की शुरूआत की, जिसमें आधारभूत सुधार और समाज के राजनीतिकरण पर जोर दिया गया। उनका प्रमुख लक्ष्य कृषि क्षेत्र में सुधार था।

वर्ष 1970 से 1973 तक, सल्वाडोर अल्लेंदे सत्ता में थे, जो समाजवादियों, साम्यवादियों और अन्य छोटे वाम दलों के गठबंधन यूनिदाद पॉपुलर की लोकप्रिय सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों (बैंकिंग, कृषि, तांबे का खनन और बड़े उद्योगों) का राष्ट्रीयकरण किया। अल्लेंदे की सरकार चिली के शासन तंत्र में उभरे 'लॉन्ग मार्च' आन्दोलन के परिणामस्वरूप बनी, जिसके दौरान कामकाजी वर्ग तथा समाज के गरीब निचले तबकों के लिए न्याय और अधिक समानता के अवसर प्राप्त किये गये। 60 के दशक में शुरू हुए राजनैतिक सशक्तिकरण के अभियान के रूप में उनके द्वारा लागू सुधारों से प्रगति का एक नया माहौल बना। लेकिन दुर्भाग्य से, लोकतान्त्रिक समाजवाद का यह प्रयोग वर्ष 1973 में एक सैन्य विद्रोह के साथ नाटकीय रूप से समाप्त हो गया।

तब सैन्य तानाशाही ने नवउदारवादी अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर निजीकरण की अतिवादी नीति लागू की। उनका उद्देश्य केवल आर्थिक व्यवस्था को बदलना नहीं था, बल्कि वे चिली के समाज को बदलना चाहते थे और एक नया सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा खड़ा करना चाहते थे। एक नवउदारवादी और बाजारोन्मुखी समाज; एक अराजनैतिक और व्यक्तिवादी समाज, जो मुख्यतः उपभोक्तावादी था और जिसमें वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धा को व्यक्तिगत तरक्की और खुशी के लिए "उचित साधन" के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य को अपने सामाजिक दायित्वों और

>>

अर्थव्यवस्था से बड़े स्तर पर पीछे हट गया था। 90 के दशक की लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान भी यह माहौल बना रहा।

निजीकरण और व्यक्तिकरण की नीतियों के चलते चिली की जनसख्या के बड़े हिस्से को भविष्य के खतरों का डर सताने लगा. इसके परिणामस्वरूप, विरोध और नागरिक आंदोलनों जैसे कि वर्ष 2006 के 'पेन्गुइंस' अभियान की शुरूआत हुई। यह एक छात्र आन्दोलन था, जिसमें बड़ी संख्या में भाग ले रहे छात्र सार्वजनिक शिक्षा में बेहतरी की बात कर रहे थे। इसके बाद, विश्वविद्यालयों में निशुल्क पढ़ाई की मांग को लेकर वर्ष 2011 में बड़े छात्र आन्दोलन की शुरूआत हुई। इन दोनों ही आंदोलनों ने आने वाली सरकार के नीति कार्यक्रमों को प्रभावित किया। परिवर्तन की प्रक्रियाएं कठिन और धीमी हैं, लेकिन अंततः इनका सकारात्मक राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है।

21वीं सदी के प्रारंभ में विकास के मौजूदा मॉडलों, जो वर्तमान की सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थानिक आपदाओं की व्याख्या करना चाहते थे, उनकी हवा निकल गई। लेकिन आज भी, औद्योगिक समाजों में एक तार्किक भाव रहता है, जो मानवीय क्रियाकलापों को वैश्विक उत्तर के लिए निर्णायक रूप से उत्पादन के लिए आवश्यक और वैश्विक दक्षिण के क्षेत्रों में निष्कर्षों को प्रकृति से अलग करता है। इन मानवीय क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप जैवमंडल, जलवायु और सामाजिक जीवन में भारी परिवर्तन हुए हैं। हाल ही में फैलाई गई प्रगति और वृद्धि की नवउदारवादी विचारधाराएं, जो आधुनिकता के पंखों पर सवार है, और भूमंडलीकरण को नये माहौल से जोश प्राप्त करती है अब पृथ्वी पर जैव मंडलीय तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य सीमाओं का लांघ रही है। यह विकास चिली की सीमाओं तक ही सिमटा नहीं रहता। आज हम अपने जैवमंडल और समाज के प्रति जवाबदेह तथा निरंतर विकासशील रह सकने वाले सामाजिक ताने–बाने से कहीं दूर आ खड़े हुए हैं।

चिली में सैन्य तख्तापलट के समय शुरू हुए हिंसक बदलाव धीरे–धीरे ही सही, आज कई देशों में वैश्वीकरण से जुड़ी धीमी पर स्थिर नवउदार प्रक्रियाओं के रूप में महसूस किये जा रहे हैं। 1980 के दशक के चिली के नवउदारवादी म डल से यह ज्ञात हुआ है कि उत्पादन के अधिक बाह्यीकरण से अधिक लचीले कामकाजी माहौल और एक नये अनिश्चित समाज का निर्माण होता है। आज भूमंडलीकरण भी इसी तरह काम कर रहा है। टेक्नोल जी के क्षेत्र में हुई क्रांति (4.0), जो अभी शुरू ही हुई है और इसके चलते दुनिया भर में नौकरियों में भारी कमी होने का अनुमान लगाया गया है, का भी प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरणीय आपदा और जलवायु परिवर्तन हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इस पर्यावरणीय क्षति और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से रोजगार कैसे प्रभावित होंगे। इन सभी कारकों से सामाजिक बिखराव और विषमताएं बढ़ रही हैं। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। अनेक देशों में सामाजिक समावेशन में आई यह कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है और स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के साथ–साथ व्यक्तिगत और नागरिक अधिकारों पर खतरा बढ़ गया है। यह स्थिति अंततः समाज को विनाश की ओर ले जाती है। लेकिन चिली और पूरे लेटिन अमेरिका सहित दुनिया के अनेक हिस्सों में सामाजिक और पर्यावरणीय आन्दोलन चल रहे हैं। इनके माध्यम से समस्याओं के स्थाई समाधान के साथ–साथ बेहतर भविष्य के लिए भी सुधारों की मांग की जा रही है।

क्या नवउदारवाद का संकट और वृद्धि का वर्तमान मॉडल नये पोस्ट–ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है। कई देशों में प्रभावी दक्षिणपंथी रुझान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये सामाजिक–पर्यावरणीय बदलावों और परिवर्तन के उदार रूपान्तरण के खिलाफ विरोधी धारा के रूप में आ रहे हैं। लेकिन यह संभव है कि वर्तमान सामाजिक पर्यावरणीय आन्दोलन, जो वर्तमान संकट के प्रत्युत्तर में और साथ ही दक्षिणपंथी नीतियों का विरोध के रूप में उभरे, आने वाले समय में और मजबूत होंगे। उदहारण के लिए, चिली में विगत राष्ट्रपति पद और संसदीय चुनावों में एक नए वामपंथी गठबंधन *फ्रेंते अम्प्लियो* ने हिस्सा लिया। अपने अस्तित्व के दो वर्ष में ही इसने 20 प्रतिशत वोट हासिल किए और संसद में जगह बनाई। पारंपरिक वामपंथियों के मुकाबले इस समूह ने राजनीति, समाज और प्रकृति के विषयों में नए विचारों को अपनाया है.

इस सबके बीच कुछ अन्य मजेदार घटनाक्रम भी हुए हैं। वैकल्पिक व्यवसायों के विकास में चिली कई देशों के मुकाबले अग्रणी है। उदहारण के लिए, 'एम्प्रेसस बी' (इन्हें 'बी कारपोरेशन' या बेनिफिट कारपोरेशन' भी कहा जाता है)। सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों के प्रति जागरूक नई पीढ़ी द्वारा स्टार्ट–अप के रूप में प्रारम्भ हुए। बाजार में इनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। पूरे लेटिन अमेरिका में पर्यावरणीय और सामाजिक सरोकारों, नवाचार और बेहतरीन गुणवत्ता के मानकों पर आधारित कंपनियां गठित हो रही हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण भी किया जाता है. इस सबसे नई कार्य संस्कृति और जीवन शैली का उदय हुआ है।

वर्ष 2017 के अन्त तक लेटिन अमेरिका में 450 प्रमाणित एम्प्रेसस बी थे, जिनमें से अकेले 130 चिली में थे। ये सामाजिक–पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित नए वैश्विक आंदोलन बी और सिस्तेमा बी व्यापार के मॉडल हैं। जन कल्याण, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ तारतम्यता, री–साइकिलिंग और जैविक अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सहकारिता के नये स्वरूपों आदि मानकों से इनकी कार्यकुशलता का आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर भी सिस्तेमा बी गठित किए जा रहे हैं और एकेडेमिया बी इनकी वैज्ञानिक शोध के माध्यम से मदद कर रहे हैं। वर्तमान में चिली ऐसे कार्यक्रमों को मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनमी, डेवलपमेंट एवं टूरिज्म के प्रोडक्शन डेवलपमेंट कारपोरेशन आदि के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रशिक्षित करना और कौशल–युक्त रोजगार के अवसर पैदा करना है।

वर्ष 2018 के अन्त में, दक्षिणी चिली के पुएर्तो मोंट, पुएर्तो वारस और फ्रुतिल्लर में 30 देशों के 1000 से अधिक लोगों ने मूवमेंट बी की पहली वैश्विक बैठक में भाग लिया। ऐसी पहले पिछले दशकों में हुए सांस्कृतिक और राजनैतिक बदलावों के परिणामस्वरूप संभव हुई हैं। आज की नई पीढ़ी स्वाधीनता, स्वतंत्रता, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, सृजन और नवाचार, सम्मान, सहिष्णुता, एकजुटता और पर्यावरणीय जागरूकता जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करती है.

यह आशा की जानी चाहिए कि इन नए और गतिशील तौर–तरीकों, जो चिली में अपनाए जा रहे हैं, को राजनैतिक समर्थन मिलता रहेगा और ये भविष्य में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा राजनैतिक नेतृत्व में प्रतिबिंबित होंगे। ■

सभी पत्राचार जॉर्ज रोजस हर्नांडेज को <jrojas@udec.cl> पर प्रेषित करें।

> एक नये वर्ग विश्लेषण के रूप में पारिस्थितिक नारीवादी समाजशास्त्र

ऐरियल सालेह, सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और सदस्य, पर्यावरण एवं समाज (आरसी 24) एवं सामाजिक आंदोलन, सामूहिक कार्यवाही एवं सामाजिक परिवर्तन (आरसी 48) पर आईएसए की शोध समिति

चूंकि पारिस्थितिक नारीवादी विश्लेषण रोजमर्रा के जीवन की प्रथाओं से जन्म लेते हैं, इसलिए वे अक्सर स्थापित राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा अधोमुख किए गये सामाजिक आंदोलनों के माने गये आधारों पर प्रश्न उठाते हैं।

उदाहरण के लिए, 1980 और 1990 के दशक के दौरान पारिस्थितिक नारीवादियों ने "गहन परिस्थितिकी" के दर्शन के अन्तर्गत सेक्स–लिंग जागरूकता संबंधी अभाव का मुकाबला किया था। ऐसा नहीं था कि कार्यक्रम के पर्यावरणीय उद्देश्य पारिस्थितिकी नारीवादियों द्वारा खारिज कर दिए गए थे अपितु, जैसा कि उन्होंने तर्क दिया कि इस विश्वव्यापी संकट का मूल बढ़ती वैश्विक व्यवस्था के पूंजीवादी पितृसत्रात्मक संस्थाओं और मूल्यों में निहित है। इस कारण से, यह आवश्यक था कि संकट समाधान के "पुरूषवादी अधिकार की संस्कृति" का समर्थन करने वाली प्रणाली को बदलना होगा। "पारिस्थितिक नारीवाद/गहन पारिस्थिति विवाद" के रूप में पहचाने जाने वाला यह विवाद, अमरिकी पत्रिका ऐन्वायरमेंटल एथिक्स में एक दशक से अधिक अपनी पकड को बनाए रखा है। इस प्रकार की मिलती–जुलती चेतना–वृद्धि की कोशिशों में पारिस्थितिक नारीवादी सिद्धांतकारों ने मार्क्सवादी विद्वता के साथ गंभीर रूप से अनुबंधता स्थापित की है। पिछले एक दशक में, *कैपिटलिज्म नेचर सोशलिज्म, द जर्नल ऑफ वर्ल्ड सिस्टमस रिचर्स* एवं अन्य स्थानों में प्रकाशित विभिन्न लेखों ने विवेचनात्मक समाजशास्त्र के रूप में पारिस्थितिक नारीवाद की सार्वजनिक समझ का अधिक व्यापक बनाया है। मेरा यह मानना है कि समकालीन वैश्विक कल्पना एक नव–समाजशास्त्रीय वर्ग–विश्लेषण का आह्वान करती है। अतः आगे प्रस्तुत की गई वार्ता, वास्तव में ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र की और जिसे मैं एक "सन्निहित भौतिकवाद" का लेबल देता हूँ, की संक्षिप्त रूपरेखा है।

> एक सन्निहित भौतिकवाद

प्रत्येक समाज की नींव प्रजनन श्रम है। इस श्रम के प्रायोगिक अनुभवों द्वारा माताएं यह सीखती हैं कि जिन देहों की व देखभाल करती है उनमें जैविक–क्रम को कैसे बनाए रखा जाए। इसी प्रकार कृषक एवं सग्रहक, भूमि पुर्नउत्पादन चक्र के साथ लय संगतता स्थापित कर लेते हैं। गैर विमुद्रीकृत श्रमिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बडे पैमाने पर अदृश्य हैं इन्हें न तो समाजशास्त्र में पर्याप्त रूप से स्वीकार किया जाता है, और न ही ये सिद्धान्तबद्ध हैं। परन्तु यह तर्क किया जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन को संभव करने में उनकें भौतिक–कौशल के कारण ये तीन श्रमिक समूह–माताएं, कृषक एवं संग्रहक एक ऐसे वर्ग का निर्माण करते है जो आज के समय में प्रांसगिक एवं महत्वपूर्ण है।

पारिस्थितिक नारीवाद शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से उस राजनीति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो पारिस्थितिकी तथा नारीवाद को समान–संघर्ष के रूप में देखता है। इसका उद्भव तब होता है जब शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण समुदायों में जीवन की परिस्थितियों में जोखिम में होती हैं। हालांकि, जीवन–अनुमोदन श्रम में महिला अथवा पुरूष दोनों की ही समान भागीदारी हो सकती है, परन्तु चूंकि विश्व–भर में महिलाएं ही मुख्यता तौर पर सामाजिक रूप से देखभाल एवं खाद्य–उत्पादकों के रूप में स्थापित है, अधिकतर पर्यावरणीय कार्यवाही में एक समुदाय की महिलाओं द्वारा ही सर्वप्रथम क्रियाशीलता प्रदर्शित की जाती है। इसी प्रकार के हस्तक्षेप किसी भी क्षेत्र, वर्ग अथवा जातीयता की सीमा से परे, सार्वभौमिक होते है। अर्थात यह अद्वितीय रूप से परस्परच्छेदित हैं। 1970 के दशक से हर महाद्वीप पर द्वितीय महायुद्ध के बाद के पूंजीवादी उपभोक्तावाद और विकास मॉडल की संपाश्विक क्षति का जवाब देने के रूप में महिलाओं ने जिसे वे कहती है "पारिस्थितिक नारीवाद" की शुरूआत हुई। इस क्रम में चाहे जहरीले प्रदूषकों, वनों की कटाई, परमाणु उर्जा अथवा कृषि उद्योगों का विरोध हो, इनकी राजनीति में सदैव "स्थानीय" एवं "वैश्विक" जुड़ाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। मारिया मिज जैसे जर्मन पारिस्थतिकी नारीविदों ने रोसा लक्जमबर्ग के समाजवादी योगदान पर अपने कार्य को स्पष्ट रूप से निर्मित किया है।

सन् 1980 के दशक ने "नव–सामाजिक आंदोलनों" एंटी–न्यूक्स, ब्लैक–पावर, महिला मुक्ति तथा स्वदेशी भूमि अधिकार के तीव्र उभार को देखा – और मार्क्सवादीयों का संशयी होना सही था। उग्रवादी पारिस्थितिकी को ग्रीन पार्टियों एवं तकनीकी पेशेवरों द्वारा सह

>>

मेटा–औद्योगिक श्रमिक पारिस्थितिक स्थिरता के साथ आर्थिक दक्षता कैसे प्राप्त करते है, इसका एक उदाहरण। फोटो : ऐरियल सालेह

विकल्पित कर दिया गया। नारीवाद, उदारवादी व्यक्तिवाद से विचलित हो गया, और समान अधिकारों के लिए राज्य के साथ सकल–मुद्दे की बातचीत में बदल गया। पारिस्थितिकी नारीवाद के अगले चरण ने 1992 के संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन को आधार बनाया, जिसने प्रकृति की रक्षा के नाम पर वैश्विक उत्तरी नव–औपनिवेशक नीतियों को तेज किया। अब क्षैत्रीय समझौतों के एक विश्व–व्यापी मास्टर प्लान ने मिट्टी के कार्पोरेट खनन और स्वदेशी औषधीय पौधों के कॉर्पोरेट पेंटेटिंग का रास्ता खोल दिया। रियो अर्थ समिट में वंदना शिवा एवं अन्य पारिस्थितिकी नारीवादी उपस्थित थे, जिन्होनें इन उपायों का विरोध करने हेतु भरपूर प्रयास किया। पेरू की समाजशास्त्री एना इस्ला, द्वारा यह रिकॉर्ड किया गया कि शीघ्र ही जलवायु परिर्वतन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क शक्तिहीन देशों को आगे रियायतों के लिए मजबूर करेगा। 20वीं शताब्दी का अंत सिएटल के युद्ध के साथ हुआ जहां एक अन्तर्राष्ट्रीय जमीनी विद्रोह द्वारा विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया गया। लोगों के वैश्वीकरण के विकल्प के लिए आंदोलनों की एक श्रृंखला में से इस विस्तृत आंदोलन ने सन् 2001 में अपना पहला विश्व सामाजिक फोरम आयोजित किया।

> वैश्वीकरण : विऔपनिवेशीकरण

नव–उदारवाद मुक्त व्यापार के विस्तार ने वैश्विक दक्षिण श्रेत्रों में कम मजदूरी वाले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में सर्वहारा वर्ग को रोजगार के लिए अपतटीय भेजकर महानगरीय राज्यों में इस वर्ग को ध्वस्त कर दिया है। परन्तु भू–राजनैतिक परिधि में कई लोगों के पास एक सकारात्मक – एक वि–औपनिवशीकृत ऐंजेडा था। उदाहरण के लिए ब्राजील में एक जोशपूर्ण भूमिहीन जन आन्दोलन पारिस्थितिकी ग्रम एवं खाद्य संप्रभुता के बारे में बात कर रहा था। इसी प्रकार इक्वाडोर में अकोइंन इकोलोजिया संगठन की महिलाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की 500 साल लंबी औपनिवेशिक चौरी का वर्णन करने के लिए "पारिस्थितिक ऋण" की अवधारणा का आविष्कार किया, जिसके अन्तर्गत विकास ऋणों पर विश्व बैंक द्वारा गठित आधुनिक चोरी तथा आर्थिक निष्कर्षी के परिणामस्वरूप आजीविका के चल रहे क्षरण संबंधी मुद्दे शामिल थे। 2010 के "कोचाबम्बा पीपुल्स कलाइमेंट सर्किट" में "सत्तता के साथ न्याय" मुद्दे को भी प्रस्तुत किया गया था। इसमें प्रगति के साथ हो रहे जीवन में क्षरण को रोकने हेतू एंडियन तरीको को वैकल्पिक प्रावधानों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रगति के साथ हो रहे औद्योगिकरण के समीकरण पर प्रश्नवाचक चिह्न लगाए गए थे।

2008 की वित्तीय मंदी के बाद वैश्विक रूप से जागरूक युवाओं ने कब्जा करों आंदोलन की शुरूआत की जिसमें पूंजीवादी वर्ग को घेरने/रोक लगाने के लिए वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज के पास शिविरों की स्थापना की गई। इन्हीं के द्वारा जर्मनी में भी फ्रैंकफर्ट बैंको को अवरूद्ध किया गया। इसी प्रकार युरोपीयन संघ के कठोर मित्तव्यत्तता प्रोग्रामों का प्रतिरोध करने वाले भू–मध्य सागरीय राज्यों में जीवन–पुष्टि "उत्पादक मूल्यों" पर आधारित एक और राजनीतिक उभरी। स्पेन में भी इंडिगोडोस द्वारा विभिन्न प्रकार की आत्म निर्भर अर्थव्यवस्थओं की शुरू की शुरूआत की गई है। 2012 के रियो +20 में, व्यवसायिक समूहों, राजनेताओं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने ग्रीन न्यू डील प्रस्ताव को एक कदम आगे बढाया, जिसके अन्तर्गत नैनो–प्रौघोगिकी जैव–अर्थव्यवस्था के लिये पब्लिक रिलेशन्स अभ्यास प्रस्तावित था। इसे भी पुनः परिस्थितिकी नारीवादियों द्वारा चुनौती दी गई। बाद में डीग्रोथ एवं जैसे मुद्दो पर चर्चा करने हेतु शिक्षाविद लीपाजिग एवं बुडापेस्ट में इकट्ठा हुये, हालाँकि, इस काल तक भी वेरोनिका बेनहोल्ड थॉम्सन जैसे परिस्थितिकी नारीवादी निर्वाहक विचारकों के उत्तर–विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता नहीं मिल पाई थी। आज, रोजा–लक्समबर्ग संस्थान, दक्षिण अमरीका के ब्यून, विविर, दक्षिण अफ्रीका के उबन्तु एवं भारत के स्वराज जैसे पारिस्थितिकी नारीवाद एवं अन्य समुदाय उन्मुख राजनीति के अभिसरण की जाँच कर रहा है।

परिस्थितिकी नारीवाद का अपना एक व्यापक साहित्य है जिसे अक्सर विश्वविद्यालयों पढाया जाता है। यह साहित्य यह समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार पूंजीवादी पित्तृसत्तात्मक संस्कृति के तहत, प्रकृति के बाजारीकरण एवं घेराव की गूंज, महिलाओं के श्रामिक–निकायों/शरीरों के बाजारीकरण एवं घेराव के गूंज की साथ तारतम्य स्थापित करता है। प्रकृति के माता संबंधी पारम्परिक संकेत, रूपक से कही अधिक हैं। जैसा कि ग्रेटा गार्द बताती हैं, परिस्थितिकी नारीवादी तंत्र–समूह में संवेदनापूर्ण वीगनवाद/शाकाहार के आचारों के समावेश हुआ है, साथ ही पशु–सुरक्षा पर भी नियमित अतंर्राष्ट्रीय बैठकें आयोजित की जाती है। अफ्रीफा भर में वे महिलायें जिनके गाँवों के पास हो रहे खनन कार्य से आजीविका पर खतरा है, ने जलवायु परिवर्तन पर स्वयं के परिस्थितिकी घोषणा पत्र के साथ एक महाद्वीपीय गैर–निष्काषित तंत्र वोमिन की स्थापना की है। संयुक्त राज्य अमरीका में एपलाचियन माताएं कोयला उद्योग द्वारा पर्वत शिखरों के क्षरण के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही का आयोजन करते है। इसी प्रकार भारत का नवधान्य स्कूल परिस्थितिकी– प्रचुरता बनायें रखने हेतु पारम्परिक बीजों का बैंक बनाता है ताकि इन्हें औषधीय पेटेन्टिंग से बचाया जा सके। ऐसे ही अन्य उदाहरण में चीन के सिचुआन क्षेत्र में कृषक महिलायें सदियों पुरानी जैविक तकनीकों कों पुनजीवित करके मिट्टी की उर्वरता को बहाल करती रही है। लंदन में, गृहाणियों द्वारा स्वेच्छा से अपने समय का अंश–दान कर थेम्स नदी के जलग्रहण क्षेत्र में सदियों से हो रहे क्षरण का मरम्मत कार्य करती है।

> नरकेन्द्रितवाद : पारिस्थितिक केन्द्रवाद

जब कार्यकर्त्ताओं अथवा जैसे आईएसए की आरसी 48 के समाजशास्त्रियों द्वारा इस बात की अनदेखी की जाती है कि किस प्रकार प्रजनन का तर्क परिस्थितकी श्रमिकों, महिलाओं एवं स्वदेशी आंदोलनों को आपस में जोड़ता हैं, तो एक विनाशकारी एकल–मुद्दे पर आधारित "पहचान की राजनीति" उत्पन्न होती हैं, जिसके अन्तर्गत एक समूह के अधिकारों को दूसरे के विरोध में खडा कर दिया जाता हैं। यह प्रतिबांधित समाजशास्त्रीय कल्पना "मानवता" बनाम "प्रकृति" की पश्चिमी द्वैतवाद के नरकेन्द्रवाद की अभिव्यक्ति है, जो वास्तव में पारम्परिक "सामान्य ज्ञान" का प्रत्येक नई पीढी के समाजीकरण का पुनर्अभिनय है। दुर्भाग्य से, वैश्वीकरण के पहिये अभी भी अस्स्तू की "ग्रेट चेन ऑफ बीइंग" पदानुक्रम की चिकनाई से चल रहे हैं। यह उस प्राचीन असंबद्ध तर्क पर आधारित है जो देवताओं, राजाओं एवं पुरूषों को सामाजिक जीवन के शीर्ष पर स्थापित करता है जिनके अधीन महिलाओं, मूल निवासियों एवं प्रकृति हैं। पुरातन अरिस्टोटेलियन मंत्र ने इतिहास की दिशा को इस तरह से संरचित किया है कि सदियों से, महिलाऐं एवं जीते हुये दास मात्र 'वस्तु' बनकर रह जायेगें। धर्म एवं कानून से लेकर अर्थशास्त्र और विज्ञान तक की यूरोकेंद्रित संस्थाओं को "मर्दवादी–पात्रता" संबंधी सेवा देने के लिये तैयार किया गया था।

>>

यह उदारवादियों एवं समाजवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही पूर्व निर्देशित स्थितियों को प्रस्तुत करता है जो समान स्तर पर विद्यमान हैं। विज्ञान की पारिस्थिकी नारीवादी इतिहासकार कैरोलीन मर्चेंट के अनुसार ज्ञानोदय अथवा प्रबुद्धता ने शरीर और प्रकृति को ऐसी मशीनों के रूप में संकल्पित किया जिनके भागों को गणितीय सूत्रों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। यह जीवन अलगाव संस्कृति पूंजीवाद की कार्य प्रणाली के लिये अपरिहार्य हैं एवं इसे आईएसए की आरसी 24 के कुछ पारिस्थितिकी आधुनिकता वादियों द्वारा समाजशास्त्र में बनायें रखा गया हैं, जिनके मानना है कि तकनीकी नवाचार पर्यावरण को बचा सकते हैं। हालाँकि, हमारा स्वचलित भविष्य आसानी से न तो न्याय या सततता में गैर–कार्यान्वित हो पाएगा। इसलिये भी क्योंकि वक्रीय आर्थिकी अथवा नारीवादी अर्थशास्यिों द्वारा देखभाल श्रम का पुनमूल्यांकन जैसे संकेतो का पूंजी के तर्क द्वारा पुनरवशोषण हो जाता है। पारिस्थितिकी संकट के समय में, यह आवश्यक है कि लोग पारिस्थितिकी केंद्रित ढाँचे में सोच पाने में सक्षम हों। जब यह विचार समाजशास्त्र के शिक्षकों के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करता है, तो आमूल परिवर्तनवादी छात्र अक्सर राजनीतिक पारिस्थितिकी, यहाँ तक की मानव भुगोल से आगे नहीं बढ पाते है। परन्तु पेशेवर आधुनिकतावादी, जैविक देखभाल श्रम पर आधारित महिलाओं के अनुभवों का विश्लेषण तथा स्थानीय ज्ञान मीमांसाओं के पारिस्थितिकी केंद्रिता से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

''मानवता'' बनाम ''प्रकृति'' के संवाद ने वामपंथी और विशेष रूप से उत्तर आधुनिक नारीवादियों को राजनैतिक अभिनेताओं के रूप में इस हाशिये पर पड़ी प्रजनन श्रम–शक्ति को गंभीरता से लेने से रोका है। वामपंथियों का आरोप है कि परिस्थितिकी नारीवादी, महिलाओं की राजनीतिक अंतदृष्टि को जन्मजात ''स्त्री–सार'' के रूप में दर्शाते है – जो उनके अनुसार निरा–बकवास है। पारिस्थितिकी नारीवादी धारणाओं का स्त्रोत न तो जैविक सन्निहितता है, न ही आर्थिक संरचना और न ही सांस्कृतिक रूढिगत रीति–रिवाज, हालाँकि, ये सभी चीजे मानव क्रिया को प्रभावित करती हैं। इसके बजाय पारिस्थितिकी नारीवादी ज्ञानमीमांसा श्रम पर आधारित हैः जिसके अन्तर्गत जीवित भौतिक संसार के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से समझ एवं कौशल का उत्पादन एवं पुर्नउत्पादन होता हैं। जो लोग जड़वत औद्योगिक नियमों से बाहर, स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं जैसे– देखभाल करने वाले, किसान एवं संग्रहकर्त्ता, वे सभी अपनी संवेदी क्षमताओं के साथ संपर्क में रहते हैं और एक व्यक्ति दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इसके बारे में अधिक सटीक अनुनादी/गुंजयमान मॉडल बनाने में सक्षम हैं।

> पुनर्योजी श्रम

इस परिथितिकी केंद्रित श्रम वर्ग की समय सीमा अंतर पीढ़ीगत हैं, अतःस्वाभाविक रूप से अधिक सतर्कपूर्ण है। इसका माप अंतरंग है, जो प्रकृति के रूप में मानव शरीरों अथवा प्रकृति, में पदार्थ ऊर्जा स्थानातरण के लिये कामगारों की जवाबदेही को अधिकतम बनाता है। इसके अंतर्गत निर्णय, परीक्षण एवं त्रुटि पर आधारित विशेषज्ञता पर आधारित है, जो पारिस्थितिकी तंत्र अथवा शारीरिक स्वास्थ्य का जन्म से मृत्यु तक के मूल्यांकन का प्रयोग करता है। प्रजातियों अथवा आयु समूहों की विविध आवश्यकताओं में सामंजस्य एवं संतुलन बनाये रखा जाता है। जहाँ घरेलू एवं आजीविका आधारित अर्थव्यस्थाऐं सहक्रियात्मक समस्या समाधान का अभ्यास करती हैं, उस स्थिति में बहु–मापदंडो के आधार पर निर्णय लेना सामान्य ज्ञान की बात है। जिस स्थिति में मानसिक एवं शारीरिक कौशल के बीच कोई विभाजन नही होता है, उस स्थिति में जिम्मेदारी में पारदर्शिता होती है, साथ ही श्रम उत्पाद को पूंजीवाद के तहत श्रमिक से अलग नहीं किया जाता है वरन दूसरों के साथ साझा करने का आनंद प्राप्त होता है। यहाँ उत्पादन का समरेखीय तर्क पुर्नउत्पादन के वृत्त पूर्ण तर्क हेतु मार्ग प्रेषित करता है। वास्तव में, इस तरह से सामाजिक प्रावधान एक साथ जातीय/देशज मौखिक विज्ञान एवं प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही है।

पारिस्थितिकी नारीवाद एक समन्वयवादी राजनीति के लिए तर्क प्रदान करता है, जो आजीविका, कुशल रोजगार एक जुटता, सांस्कृतिक स्वायत्तता, सेक्स–लिंग जागरूकता, सीखने, सशक्तिकरण और आध्यात्मिक नवीनीकरण को बढ़ावा देता है। इसका एक वर्तमान उदाहरण इक्वाडोर के विकास द्वारा खंडित पहाड़ी क्षेत्र नबोन की माताओं एवं दादी के मध्य देखा जा सकता है। दूरदर्शिता और रचनात्मकता का प्रयोग कर, इन स्वशासित महिलाओं ने अपने पुराने पानी के जलग्रहणों और धाराओं को बहाल करने के लिए रोपण द्वारा कटाव नियंत्रण, जल संचयन, मिट्टी की उर्वरता एवं खाद्य सम्प्रभुता हासिल की है। इस प्रयास के द्वारा उन्होंनें वैश्विक जलवायु संकट के लिए भी अपना योगदान भी दिया है। इसी बात का समर्थन करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय किसान संघ "वाया कैंपसीना" इस बात पर बल देकर कहता है कि –"हमारे द्वारा किए गए लघु–स्तर के प्रावधान, पृथ्वी को ठंडा करने में सहयोगी हैं।"

प्रजनन कार्य पश्चिमी व्यवहारिक तर्क के कारण उत्पन्न हुई यंत्रवत् हिंसा को रोकने एवं उसका सामना करने वाले संबंधपूरक – "जानने के तरीको" का निर्माण करता है। जब तक आमूलपरिवर्तनबदी राजनीति को देखभाल श्रम द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, वह आसानी से उस ज्ञान में पुनः फंस जाएगी जो पृथ्वी एंव इसके लोगों को विकास अर्थव्यवस्था के लिए मात्र एक अन्तहीन संसाधन के रूप में देखते हैं। जबकि आधुनिक उद्योगों का सम–रैखिक तर्क प्रकृति के चयापचय को आसानी से बिगाड़ते हुए आगे बढ़ने पर आधारित है जिसक परिणाम में विकार एक अनिश्चितताएं पीछे छूट जाती हैं। इसके विपरीत अधि–उद्योग जो जीवित प्रक्रियाओं का पोषण करते हैं मानव रचनात्मकता का एक वैकल्पिक रूप अभिव्यक्त करने वाले मौन–ज्ञानमीमांसा विकसित करते हैं। इस तरह का श्रम, जो अपनी घरेलू एवं भौगोलिक परीधि, दोनों से पूंजी द्वारा स्वतंत्र रूप से विनियोजित होता है, वास्तव में पूंजीवाद के उत्पादन के तरींको की पूर्व शर्त है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जाए कि श्रमिकों का यह अनूठा वर्ग "पूंजीवाद के अन्दर" मौजूद है, जहाँ इसकी गतिविधियाँ अधिशेष मूल्य को कम करती है। वहीं दूसरी ओर प्रजनन प्रावधान, स्वयं के लिए पर्याप्त होते हुए भी "पूंजीवाद के बाहर" विद्यमान है। मेरे द्वारा "मेटा" शब्द का प्रयोग एक मौलिक ढाँचे को बताने के संदर्भ में किया है जो सहायक गतिविधियों को जगह पर बनाए रखता है।

पारिस्थितिकी–स्वावलम्बी अर्थव्यवस्थाऐं न तो व्यक्तियों का शोषण कर लागतों को मूर्त रूप में समाविष्ट करती हैं और न ही वे अपशिष्ट कों "प्रदूषण" के रूप इंगित करती है। यह पुर्नउत्पादक/पुनर्योजी श्रम कौशल एक धारणीय वैश्विक भविष्य के लिए अपरिहार्य है और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यह दुनिया भर के श्रमिकों द्वारा पहले से ही प्रचलन में है। यह पहचान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में ऐतिहासिक कर्ता के रूप में अधि–औद्योगिक वर्ग को बड़ी सामरिक शक्ति प्रदान करती है। शास्त्रीय समाजवाद की शोषक "उत्पादन के संबंधों" के साथ की अति–व्यस्तता, गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा दमनकारी "पुर्नउत्पादन के संबंधों" के ऊपर चिंतन को पार्श्व भाग में धकेल दिया है।

इसके साथ ही मार्क्स के लेखन में भी ऐसे गद्यांश है जो शायद काफी अच्छे ढंग से "अधि–औद्योगिक श्रम–वर्ग" को वर्णित कर सकते थे, यदि उनका मानवीय केंद्र कम पितृसत्रात्मक एवं यूरोपीय–केंद्रित होता। ■

सभी पत्राचार एरियल सालेह को <ariel.salleh@sydney.edu.au> पर प्रेषित करें।

> ब्राजील 2018 :
मध्यम वर्ग का दक्षिणपंथ की ओर झुकाव

लेना लावीनास, फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रिओ दि जनेरियो और
गुइलहर्मे लेइते गोंकाल्वेस, रिओ दि जनेरियो स्टेट यूनिवर्सिटी, ब्राजील

फरवरी 2018 से रियो डी जनेरियो की सड़कों पर भारी सैन्य और पुलिस की उपस्थिति जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन गई है।
फोटो: इबीसी–सम्प्रेसा ब्राजील दे कम्यूनिकाकाओ। एगेंसिया ब्राजील। क्रियेटिव कामन्स।

1980 का दशक लैटिन अमेरिकी देशों में उन सैन्य तानाशाहियों का अन्त लेकर आया, जिन्होंने कई दशकों तक सामाजिक बदलाव के प्रयासों का दम घोंटा था। लेकिन लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने से जहाँ एक तरफ नागरिक अधिकारों के औपचारिक रास्ते खुले, आर्थिक विपत्तियों और धनी वर्ग के साथ समझौते भी सामने आए।

ब्राज़ील में अंतिम से दूसरे सैन्य शासक एर्नेस्तो गिसेल द्वारा की गई बदलाव की धीमी, निरंतर और सुरक्षित शुरुआत विरोधाभासों से भरी थी। एमनेस्टी कानून जो, सशस्त्र सेनाओं और राजनैतिक तथा आर्थिक नेताओं के बीच हुआ एक सौदा था, ने प्रताड़ना के शिकार तथा गायब हुए लोगों के परिवारों को अकेला छोड़ दिया। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ग्वाटेमाला, पेरू और उरुग्वे जैसे देशों में इसी तरह सौदे हुए, जिससे प्रताड़ना करने वालों, और कुछ मामलों में पूर्व राष्ट्र–प्रमुखों को जेल जाना पड़ा। ब्राजील में ट्रुथ कमीशन (2011-2014) ने नीतियों में स्मृतियों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन इसकी अनुशंसाएं बेकार ही रहीं।

अपनी सीमाओं के बावजूद ब्राज़ील में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना ने राजनीति में लोगों की अधिक भागीदारी के लिए जगह बनाई। मध्यम वर्ग ने नागरिक समाज के पुनर्गठन, रंगभेद विरोधी और महिला अधिकार नीतियों के लिए संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1987 की संविधान सभा के दौरान और तानाशाही के अंत के बाद हुए चुनावों में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक थी। 1989 में मध्यम वर्ग ने वर्कर्स पार्टी (पी.टी.) के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुईस इनासियो लूला डी सिल्वा का समर्थन किया, जबकि विजेता उम्मीदवार फर्नान्डो कोल्लोर डी मेलो ने सैन्य शासन के समर्थन वाले धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व जारी रखा। जब कोलोर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, वर्ष 1992 में बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ब्राज़ील के पहले नव उदारवादी राष्ट्रपति पर महाभियोग के समर्थन में जुटा।

1990 के दशक में, मध्यम वर्ग ने लूला का समर्थन करना जारी रखा, जो वर्ष 1994 और 1998 में फर्नान्डो हेनिरिक कार्दोसो से हार गए थे। 1994 में लूला के वोटो का अधिकांश हिस्सा 2 से 10 तक न्यूनतम मजदूरी पाने वाले लोगों और सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों से आया। कार्दोसो को सर्वाधिक समर्थन आमदनी के पैमाने के दोनों सुदूर सिरों पर मौजूद लोगों ने दिया। 1998 में कार्दोसो को सभी आमदनी वाले वोटरों का बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने सबसे कम पढ़े–लिखे लोगों के बीच अच्छा समर्थन हासिल किया। दूसरी तरफ, लूला ने अधिक शिक्षित वर्ग में मजबूत समर्थन हासिल किया।

कार्दोसो के दौर में मौद्रिक स्थिरता, सम्पूर्ण निजीकरण और वित्तीय मितव्ययता वाली नीतियां बनीं और इसने ब्राज़ील को मंदी के दौर में पहुंचा दिया। अर्थव्यवस्था के गहन पुनर्गठन ने मध्यम वर्ग को पारंपरिक काम–धंधो के घटने, आयात–प्रतिस्थापन व्यवस्था के उभार (जिसके कारण तकनीकी और अफसरशाही का बोलबाला बढ़ा), वेतन में कटौती और रोजगार के अच्छे अवसरों में कमी जैसे दवाब झेलने पड़े। सामाजिक स्थिति में गिरावट के कारण वर्ष 2002 के चुनावों में मध्यम वर्ग ने लूला को समर्थन दिया और उनके वोटों से लूला ब्राजील के पहले वर्कर राष्ट्रपति बने। वर्ष 2006 आते–आते लूला के प्रति मध्यम वर्ग का समर्थन कम होने लगा। यह अधोगामी रुझान वर्ष 2010 और 2014 में तीव्र हुआ जब वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार दिल्मा रूसेफ थे (जिन्होंने दोनों चुनावों में जीत हासिल की)। धीरे–धीरे लेकिन निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के मतदाता दक्षिणपंथ की स्थानांतरित हो रहे हैं।

>>

> लूला/दिल्मा युग में बाजारोन्मुख विस्तार

लूला ने वर्ष 2003 में 'प्लानो रियल' द्वारा हासिल की गई मौद्रिक स्थिरता के बावजूद आर्थिक मंदी, सिकुड़ती वृद्धि के बीच राष्ट्रपति का पद संभाला। मुद्रा स्फीति पर देश की बहुप्रतीक्षित जीत गरीबी और असमानता घटाने तथा मध्यम वर्ग के सामाजिक उर्ध्वगामी गतिशीलता को प्रोत्साहित करने में विफल रही।

लूला के पहले कार्यकाल (2003-06) के आर्थिक सुधार, उनके दूसरे कार्यकाल (2007-2010) में अधिक मजबूत हुए। प्रारंभ में, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने निर्यात को बढ़ावा दिया और विकास को गति दी। इन वर्षों को औपचारिक रोजगार में उल्लेखनीय विस्तार और औसत आय में वृद्धि द्वारा चिन्हित किया गया। न्यूनतम वेतन में महंगाई से 70 प्रतिशत से ऊपर तक की वास्तविक वृद्धि हुई। इसके समानांतर, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों में भी 1.4 करोड़ परिवारों को मामूली लेकिन निरंतर लाभ देने में सफलता मिली। ऋण देने के लिए शुरू नई योजनाओं तक पहुंच ने वित्तीय समावेशन की एक असाधारण प्रक्रिया को संभव बनाया। विश्व प्रसिद्ध 'बोलसा फैमिलिया' कार्यक्रम की सफलता समाज के सबसे निचले तबकों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में ऊपर उठाकर उन्हें उपभोक्ता बाज़ार से जोड़ने से निकली थी।

इसी दौर में निजीकरण की प्रक्रियाएं चल रही थी। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण, और उसी काल में राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन की कमी के चलते निजी स्वास्थ्य योजनाओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ी संख्या में विद्यार्थी सरकारी से हटकर निजी शिक्षण संस्थाओं में चले गए : वर्ष 2015 तक 75 प्रतिशत विद्यार्थी निजी संस्थाओं में पढ़ रहे थे। शिक्षा के लिए ऋण के आंकडों में बेहताशा बढ़ोतरी हुई : 51 प्रतिशत ऋण का भुगतान अटक गया (जिनकी कुल राशि लगभग 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी) और इनमें से आधे के पास भुगतान वापिस शुरू करने का कोई जरिया नहीं था।

रिकॉर्ड स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं के वास्तविक प्रोत्साहन आयात के अधिमूल्यन ने अंततः औद्योगिक गतिविधियों की वापसी को रोक दिया। वर्कर्स पार्टी की विरासत में से एक प्राथमिक क्षेत्रों की नवीकृत केन्द्रीयता थी जो कच्चे माल की वैश्विक मांग बढ़ने से नहीं बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन की कृषि–आधारित व्यवसायों के साथ घनिष्ठ गठबंधन के द्वारा प्रेरित थी।

दिल्मा के शासन के पहले वर्ष (2011) से ही आर्थिक विकास की गति मंद पड़ने लगी। सड़के "नए मध्यम वर्गों" – एक सम्बोध जो अल्प–आय क्षेत्रें को मध्यम वर्ग की तरह ही उपभोग करने की अनुमति देकर, सामाजिक गतिशीलता में आने वाले अवरोधों के अंत का सुझाव देता है, के असंतोष से गूंजने लगी। फिर 2013 के जून में एक स्वप्रेरित जन आन्दोलन शुरू हुआ जिसने बेहतर सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास की मांग की।

इस प्रक्रिया को बेहतर रूप में समझने के लिए यह याद रखना होगा कि जब 2006 और 2013 के दौरान आय में वृद्धि हुई और निर्मित वस्तुओं के दाम गिर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, डेकेयर, और वृद्धजनों की देखभाल पर होने वाले खर्चों ने औसत मुद्रास्फीति और वेतन को पीछे छोड़ दिया था। आसानी से उपलब्ध होने वाले लेकिन महंगे कर्जों से उपभोक्ताओं के सपने साकार होने लगे, अधिक से अधिक लोग इसके कर्ज के दुःस्वपन के शिकार हुए और इसने लोगों की घरेलू आमदनी के अधिकतर हिस्से को निगल लिया। आज ब्राज़ील में लगभग 6.3 करोड़ वयस्क वित्तीय संकट में हैं।

> मध्यम वर्ग और सुदूर दक्षिणपंथ

कर्जे में डूबा मध्यम वर्ग पुनः लोकतांत्रिकरण के बाद बाजारोन्मुखी विस्तार के विभिन्न चरणों में निहित विरोधाभासों से मायूस हुआ। उछाल वाले दिनों के दौर में अराजनीतिकरण के साथ–साथ इसने इस वर्ग को राजनीतिक प्लेटफार्मों के समक्ष विरोधाभासी, अस्थिर स्थिति में रखा और उन्हें अति दक्षिणपंथ के चंगुल में फंसने को मजबूर कर दिया।

ऐसे विमर्श का पहला तत्व सैन्य तानाशाही की वापसी है जिसकी ब्राज़ील के इतिहास का बेहतरीन दौर के रूप में प्रशंसा की गई। इस स्थिति को उक्त दौर में हुई राज्य–प्रायोजित हिंसा के प्रति चुप्पी की नीति से प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए पुनःलोकतंत्रीकरण के दौरान उच्च वर्ग के साथ हुए समझौते जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, अति दक्षिणपंथ ने राष्ट्रवाद, अंधराष्ट्रवाद और जाति–नस्लीय भेदभावपूर्ण संदर्भों में सामाजिक तनाव को पुनः ढाला है। यह मध्यम वर्ग की असुरक्षा की भावना की पहचान कर इसके लिए उन लोगों को बदनाम करता है, जिनको वह समाज के इन हालात के जिम्मेदार समझता है। इनमें वामपंथी, महिलाएं, समलैंगिक, अश्वेत, मूल आदिवासी सहित वे सब सम्मिलित हैं, जो पूर्व में पहुँच से दूर रही सामाजिक–राजनैतिक हैसियत को हासिल करने में सफल रहे हैं। "अन्य" के उत्पीड़न से यह उन लोगों की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जिन्हें बाज़ार ने सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अति दक्षिणपंथ लूला और दिल्मा के शासन से मध्यम वर्ग के मोहभंग को भी शह देता है : (पीटीज्म) एंट–पेटिस्मो विरोधी राजनैतिक और आर्थिक भड़ास को व्यक्तिगत घृणा और हिंसा के रूप में प्रदर्शित करते हैं।

दक्षिणपंथ का घृणास्पद भाषण गरीबों और कामकाजी लोगों के खिलाफ हिंसा के स्वाभाविकरण को राज्य की नीति का हिस्सा बना देते है और फिर यह बेरहम संख्या में तब्दील हो जाते है। फरवरी 2018 से, जब रिओ डे जनेइरो में सेना को बुलाया गया, पुलिस या सेना ने प्रत्येक 6 घंटों में एक व्यक्ति को मारा है। उनके शिकार झुग्गियों में रहने वाले अश्वेत नौजवान हैं। बुरी तरह विफल साबित हो चुकने के बावजूद भी हिंसा को रोकने के लिए हिंसा की रणनीति मध्य क्षेत्रों के लिए एक मानक कार्यवाही बन गई है जो शहरी असुरक्षा को राज्य सत्ता के अभाव के रूप में देखते हैं जिसका समाज के लिए किसी भी कीमत पर समाधान होना चाहिए।

हाल में हुए चुनावों में विजेता दक्षिणपंथी नेता, पूर्व सेना अधिकारी जेर बोल्सोनारो, ने उच्च–वेतन और मध्यम वर्ग के हाई स्कूल या कॉलेज डिग्रीधारी वोटरों का खूब समर्थन हासिल किया। दूसरी तरफ, वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार फर्नान्डो हद्दाद को सबसे गरीब तथा सबसे अनपढ़ लोगों का समर्थन मिला। इससे यह स्पष्ट है कि राजनीति की बिसात पर स्थितियां कितनी बदल गई हैं। लेकिन अब ब्राजील के राजनैतिक परिदृश्य में दो नए तथ्य उभरे हैं, जो एक–दूसरे से काफी बारीकी से जुड़े हैं। पहला तथ्य है कि बोल्सोनारो ने सभी सामाजिक हलकों में अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरा यह कि ब्राज़ील में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण रहे वर्गों में लोकतान्त्रिक शासन के प्रति की उदासीनता और तिरस्कार की भावना बढ़ रही है। ■

सभी पत्राचार लेना लविनास को
<lenalavinas@gmail.coml> पर और
गुइलेहर्मे लेइते गोंकाल्वेस को
<llguilherme.leite@uerj.brl> प्रेषित करें।

> लोकलुभावनवाद

पहचान और बाजार

अयसे बुग्रा, बोगाजिकी विश्वविद्यालय, तुर्की द्वारा

तुर्की में हाल के मुद्रा संकट ने दर्शाया कि केन्द्रीय बैंक की स्वायत्तता को बचाने के लिए कानून का उल्लंघन कैसे अर्थव्यवस्था को गंभीर हानि पहुंचा सकता है।
फोटोः अइसे बुग्रा

1990 के दशक में, लोकलुभावनवाद एक नये प्रकार की गैर–उदारवादी विचारधारा को नामित करने के लिये व्यापक रूप से प्रयोग किया गया शब्द है जो देशों की एक विस्तृत श्रृंखला के कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को वर्णित करता है। विशिष्ट प्रतिनिधित्व के लिये एक नैतिक दावा – जहां पूरे विपक्ष की वैद्यता को अस्वीकार किया जा सकता है – लोकलुभावनवाद की मुख्य विशेषता के रूप में दिखायी देता है और इस अशांत अवलोकन को आधार बनाता है कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी सरकार लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि खतरे का सवाल पहली बार सत्ता में आये लोकलुभावन दल की बहस और राजनीतिक प्रवृति से साफ तौर पर दिखाई नहीं देता, लोकलुभावनवादी राजनीति की ये विशेषतायें प्रतिनिधि लोकतंत्र के मानदंडों और संस्थाओं से क्रमिक विचलन की गतिशील प्रक्रिया में अक्सर आकार ले लेती हैं। इसलिये यह सुझाव दिया जा सकता है कि लोकलुभावनवाद की प्रकृति को, दी गयी विशेषताओं के एक सेट वाली विचारधारा के बजाए एक प्रक्रिया के रूप में बेहतर समझा जा सकता है।

> तुर्की में दक्षिण पंथ लोकलुभावनवाद की प्रक्रिया

2002 में जब तुर्की में ए.के.पी. (जस्टिस एंड डवलपमेंट पार्टी) सत्ता में आयी, इसके नेताओं ने अपने इस्लामिक अतीत की चिंताओं का खारिज करने के एक प्रयास में अपनी वैचारिक स्थिति का वर्णन करने के लिये "रूढ़िवादी लोकतंत्र" शब्द का प्रयोग किया। दल के संस्थापक सदस्यों ने वास्तव में *इस्लामिक नेशनल आउटलुक आंदोलन* के अंदर अपना राजनीतिक गठन किया था, और अधिकांश आर.पी. (वेलफेयर पार्टी) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुये थे जो 1997 में अपनी धर्मनिरपेक्ष विरोधी प्रवृति के कारण बंद हो गयी थी। फिर भी ए.के.पी. नेताओं का यह दावा कि पार्टी ने अपनी इस्लामिक स्थिति पीछे छोड़ दी है, देश और विदेश में कई लोगों को विश्वसनीय लगा। बाजारोन्मुख आर्थिक रणनीति के लिये एक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति भी उन लोगों के लिये आश्वस्त करने वाली थी जो ए.के.पी. को एक सामान्य दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार थे।

आज, ए.के.पी. और इसके नेता एर्डोगन लोकतंत्र के लिये लोकलुभावन खतरे पर बहसों में एक प्रमुख उदाहरण के रूप में दिखते हैं। सोच में यह परिवर्तन छिपे हुये इस्लामिक एजेंडा के दिखायी देने से कम और ध्रुवीकृत समाज में पहले से ही उपस्थित प्रवृति के सामने आने से संबंधित है। यह प्रवृत्ति शुरूआत में देश के सांस्कृतिक संसार से अलग और बहुमत के द्वारा चुनी गयी सरकार की विरोधी सत्तावादी धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतों वाले विपक्ष द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, के खिलाफ रक्षात्मक तर्क के रूप में बनायी गयी थी।

1990 के दशक में आर.पी. की तरह एकेपी ने धर्मनिरपेक्ष रिपब्लिकन शासन के तहत देश की मुस्लिम बहुल जनसंख्या की वंचित स्थिति पर जोर देने के लिये मान्यता की राजनीति की भाषा का आधार लिया। यह वास्तव में लोकलुभावन विजेताओं के द्वारा पीड़ितों जैसा व्यवहार पेश करने और बहुसंख्यकों का दुर्व्यवहार किये जाने वाले अल्पसंख्यकों की तरह दिखाने का मामला था, जैसा कि जेन वर्नर मुलर ने अपनी पुस्तक *व्हाट इज पोपुलिज्म?* में रखा। हालांकि, उस दौर के प्रचलित वातावरण में, जहां पहचान की राजनीति वाम और

>>

फोटो : अइसे बुग्रा

दक्षिणपंथी राजनीति के बीच में विभाजन को व्यापक रूप में समाहित करती थी, कुछ लोगों ने ए.के.पी. की चर्चाओं के इस तत्व की धर्मनिरपेक्षतावादी स्थिति की विवादास्पद सार्वभौतिकता के खिलाफ सांस्कृतिक मतभेदों के पहचान के लिये एक लोकतांत्रिक आह्वान के रूप में व्याख्या की। इसके अलावा, पहचान की राजनीति के लिये ए.के.पी. का दृष्टिकोण, कम से कम चर्चाओं के स्तर पर उनके अब तक अस्वीकृत सांस्कृतिक मतभेदों को पहचानने और सम्मान देने के वादों के साथ, नस्लीय अल्पसंख्यकों तक भी बढ़ गया। एक बार के लिये, इसने पार्टी के लिये वाम उदार बुद्धिजीवियों और कुछ कुर्दिश नागरिकों सहित जनसंख्या के विभिन्न हिस्सों के समर्थन का आनंद लेने में मदद की।

एक.के.पी. की पहली सरकार के गठन के एक दशक के बाद ही समूह मतभेदों के प्रति पार्टी के दृष्टिकोण में निहित समस्याओं के बारे में बताना संभव हो गया। जबकि सांस्कृतिक मतभेदों की पहचान को न्याय के एक केन्द्रीय आयाम के रूप में प्रस्तुत किया गया, न्यायोचित प्रतिनिधित्व के प्रश्न को सभी समूहों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ऊपर निर्वाचित पार्टी या उसके नेता के वैद्य एकाधिकार के लिये अनुक्रमित किया गया था।

> दक्षिणपंथ द्वारा पहचान की राजनीति का उपयोग

तुर्की में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रकाश में, शेरीबर्मन द्वारा उठाया गया प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है: "पहचान की राजनीति वाम से अधिक दक्षिणपंथ को क्यों लाभान्वित करती है?" जैसा कि एरिक होब्सबॉम ने पहले से ही 1996 में एक प्रकाशित लेख द *न्यू लेफ्ट रिव्यू* में चेतावनी दी थी, राष्ट्रवाद पहचान की राजनीति का एकमात्र रूप है जो अधिकांश नागरिकों के लिये एक समान अपील पर आधारित है और "दक्षिणपंथी, विशेषतः सत्ता में दक्षिणपंथी, ने हमेशा इस पर एकाधिकार होने का दावा किया है।" ए.के.पी. के मामले में, पहचान की राजनीति की भाषा का सफल उपयोग अंततः राष्ट्रवाद के एक ऐसे स्वरूप के रूप में सामने आया है जहां विपक्षी दलों को राष्ट्रीय हितों के लिये खतरें के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उदाहरण 2015 के आम चुनावों के पहले के चुनावी अभियानों के भाषणों में देखा जा सकता है।

सांस्कृतिक मतभेदों की स्वीकृति से एक राष्ट्रवादी भाषा तक चर्चात्मक परिवर्तन के साथ 2007, 2010 और 2017 में हुये तीन जनमत संग्रहों के बाद महत्वपूर्ण संस्थागत परिवत्रन सफलतापूर्वक शुरू किये गये। वास्तव में, तुर्की का मामला दिखाता है कि कैसे लोकलुभावनवाद का हमारा समय एक जनमत संग्रहों का समय भी है। वर्तमान में लोकलुभावनवाद की बढ़त और राजनीतिक निर्णय करने के रूप में जनमत संग्रहों की महत्ता के वैश्विक स्तर पर अवलोकन को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से व्यापक लोकप्रिय असंतोष के प्रतिबिंब के रूप में विवेचित किया जा सकता है। इस प्रकार, वे दोनों उदारवादी परिधियों में जांचों और संतुलनों की एक प्रणाली के द्वारा विवश हुये बिना लोकप्रिय संप्रभुता के एक स्वरूप के बारे में समान चिंताओं को पोषित करते हैं। तुर्की में, जनमत संग्रहों ने कार्यपालिका पर नौकरशाही और कानूनी बाधाओं के क्रमिक उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और अंततः राष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना में जहां निर्वाचित राष्ट्रपति के पास अत्यधिक निर्णय करने की शक्तियां होती है।

दिलचस्प बात यह है, देश का वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था में सम्मिलन, निर्वाचित शासक के द्वारा पूर्ण निर्णय करने की शक्ति के प्रयोग को सीमित करने में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। तुर्की में हाल ही के मुद्रा सकट में दिखा कि कैसे कानून के शासन का उल्लंघन और केन्द्रीय बैंकों की स्वायत्ता का अनादर निवेशक के विश्वास का क्षरण करता है और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि अब यह साफ हो रहा है कि संकट को देश के खिलाफ साजिश करने वाली ताकतों के प्रति बारंबार संदर्भों के माध्यम से संभाला नहीं जा सकता है, सत्तावादी लोकलुभावनवादी नेताओं को यह स्वीकार करना पड़ सकता है कि उनका शासन बाजार अर्थव्यवस्था के सुचारू कामकाज से टकराव में आ सकता है। हम राजनीति और आर्थिक नीतियों के दायरे में किस तरह के बदलावों की आशा कर सकते हैं, यह अभी भी अनिश्चित है। ■

सभी पत्राचार अयसे ब्रग्रा को
<bugray@boun.edu.tr> पर प्रेषित करें।

> लेटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद

समाज कल्याण से ऊपर निजी–स्वार्थ

रामिरो कार्लोस हम्बर्टो कजियनो ब्लांको, साओ पॉउलो विश्वविद्यालय, ब्राजील और
नतालिया टेरेसा बेरटी, यूनिवर्सिटी देल रोजारियो, कोलंबिया द्वारा

अर्जेन्टीना में विरोध। फोटोः रमीरो कार्लोस हर्म्बटो कैगियानो ब्लॉकों।

2000 के दशक के कमोडिटी बूम ने अर्जेंटीना और ब्राजील की सरकारों को सामाजिक एकीकरण के साथ पुनः औद्योगिकीकरण की नीतियों को अपनाने में सक्षम बनाया। इन सरकारों ने रणनीतिक कंपनियों को फिर से राष्ट्रीयकृत किया, आंशिक रूप से श्रम बाजार को (पुनः) विनियमित किया, एक न्यूनतम आय को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत किया, और अन्य उपायों के साथ आवास ऋणों का समर्थन किया, जिन्होंने मध्यम वर्गों के विकास और जनसंख्या के बड़े हिस्से के लिए गरीबी पर काबू पाने की अनुमति दी। हालांकि, आर्थिक पुनरुद्धार और महत्वपूर्ण निवेश प्रवाह के आकर्षण ने इन अर्थव्यवस्थाओं के अत्यधिक केंद्रित चरित्र को बनाए रखा। 2008 के संकट ने मध्यम वर्गों द्वारा हासिल विशेषाधिकारों की नाजुकता को स्पष्ट किया। उसी वर्ष अर्जन्टीना में सेसरोलेरोस और ब्राजील में पेनेलिरोस (बर्तन पीटने वाले प्रदर्शनकारी) के सत्तावादी और अपवर्जी दावों का उभार देखा जिसने क्रिस्टीना फ़र्नांडेज़ डी किर्चनर और दिल्मा रूसेफ़ को समर्थन के नुकसान में और उसके बाद दक्षिणपंथी लोकलुभावन सरकारों के उभार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मार्च 2008 में अर्जेंटीना में, अनाज के निर्यात से जुड़े समूहों ने एक नए कर साधन के सामने विरोध और बाधाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिसका उद्देश्य एक उच्च प्रतिस्पर्धी जो तकनीकी रूप से पिछड़ गये विभिन्न उद्योगों के मध्य असंतुलन का प्रबंधन करना था। कृषि क्षेत्रों में हड़तालों की अवधि और व्यापक स्वीकृति ने कुछ शहरी केंद्रों को भोजन की कमी का संकेत दिया।

यह ब्यूनस आयर्स में ऊपरी और मध्यम वर्गों के क्षेत्रों द्वारा "स्व–संगठित" प्रदर्शनों की एक श्रृंखला की शुरुआत थी, जो अन्य शहरों में बर्तन और धूपदान की आवाज़ तक विस्तारित हुई थी। 2012 में ये विशालकाय हो गये, परन्तु फिर इन्होंने धीरे–धीरे शक्ति खो दी। ये प्रदर्शन, जिन्हें # 13S # 8N # 18A # 8A # 13N और # 18F[1] के रूप में जाना जाता है, ने विविध शिकायतें भ्रष्टाचार और स्वतंत्रता की कमी, सार्वभौमिक बाल भत्ता, इत्यादि एकत्रित की। ये सभी राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आक्रामक नारों और पोस्टरों में व्यक्त हुई।

ब्राजील में मई और जून 2013 में, मुफ्त सामूहिक परिवहन के पक्ष में विरोध प्रदर्शनों ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया और विश्व कप के खिलाफ और सार्वजनिक सेवाओं की अनिश्चितता के खिलाफ मध्यम वर्गीय विरोध बन गया। 2015 और 2016 में, ये विरोध अपने चरित्र को बदलते हुए और राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ और वर्कर्स पार्टी एवं 2002 के बाद से प्रोत्साहित सामाजिक नीतियों दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आक्रामक रूख अपनाते हुए लगभग सभी प्रमुख ब्राजीलियन शहरों में पहुंच गये। इन अभिव्यक्तियों ने रूसेफ के महाभियोग, की मांग तानाशाही के पुनर्जनन में फासीवादी स्थिति और वाम के प्रति सार्वजनिक द्वेष। कई समूहों ने सीधे "तत्काल सैन्य हस्तक्षेप" की मांग रखी।

मध्यम और उच्च वर्ग घटते हुए सामाजिक अंतर जिसे दोनों सरकारें चक्रीय विरोधी नीतियों और श्रम बाजार के

>>

विनियमन के माध्यम से हासिल करने की कोशिश कर रही थीं, के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों ने श्रमिकों के सशक्तीकरण को खारिज कर दिया, और वेतनभोगी वर्गों ने अपंजीकृत नौकरानियों को रखने के विशेषाधिकार को खोने से इंकार कर दिया। इसी समय, उन्होंने व्यक्तियों और राज्य के भ्रष्टाचार के साथ सामाजिक नीति को जोड़ा। उन्होंने सामाजिक असमानताओं को सामान्य करने और गरीबी को वैधता या कौशल की कमी से बहने वाली व्यक्तिगत असफलता के रूप में "वैधता के सिद्धांत" पर आकर्षित किया। यह "समृद्धि के धर्मशास्त्र" के साथ चलता है, जिसके माध्यम से पेंटेकोस्टल चर्चों का कहना है कि इस प्रयास को आर्थिक रूप से भगवान के साथ–साथ उद्यमशीलता विमर्श द्वारा भी मुआवजा दिया जाता है।

यह असंतोष जो मनिचैस्म और चयनात्मकता से चिह्नित, भ्रष्टाचार की निरंतर निंदा के रूप में प्रारम्भ हुआ – अर्जन्टीना में किचर्नर और ब्राजील में पेतीस्ता (वकर्स पार्टी) – जो नेताओं के चरित्र के विचलन के लक्षण के रूप में, कई प्रकार के कट्टरपंथी विचारधाराओं का उद्भव स्थल बन गया। इसी समय, दोनों समाजों में इसके संरचनात्मक चरित्र पर सवाल उठाए बिना, उन लोगों पर जो वास्तव में भ्रष्टाचार में शामिल थे, पर एक आंशिक दृष्टिकोण लिया गया।

कट्टरवाद इस धारणा से परिभाषित किया जाता है कि एक प्रकट सत्य है जो बहस की किसी भी संभावना को अमान्य करता है। एंटिचविस्मो की आड़ में अर्जेंटीना और ब्राजील में कम्युनिस्ट विरोधी कट्टरवाद का पुनर्जन्म हुआ। अब खतरा "वेनेजुएलाकरण" और "बोलिवेरियनवाद" है, जिसे "पश्चिमी पूंजीवाद" और "पारंपरिक परिवार" की नींव को तोड़ने के किसी भी प्रयास के रूप में समझा जाता है। कम्युनिस्ट–विरोधी कट्टरपंथी सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करने का विरोध करते हैं, जो ब्राजील में गरीबों, नारीवादियों, समलैंगिकों और अश्वेतों और अर्जेंटीना में खलनायकों (झोंपड़ियों में रहने वाले) से घृणा में अनुवादित होती है, जिन सभी पर अक्षम, अज्ञानी या भ्रष्टाचारी होने का आरोप है।

इसने ऑस्ट्रियाई स्कूल से विरासत में मिली अतिउदार विचारधारा के लोकप्रिय होने के द्वार खोल दिए हैं, जैसा कि ब्राजील के सामाजिक शोधकर्ता कारापाना बताते हैं, दो स्तंभों द्वारा समर्थन मिलता है: "न्यूनतम राज्य", और पैटा सुंट सर्वंडा जिसके अनुसार सभी अधिकारों को वहां तक सीमित कर दिया जाए जो सभी पार्टियों द्वारा "मुक्त" रूप से स्वीकार्य हो। वहाँ से, एक सरल सुई जेनिरिस द्विभक्तीकरण की स्थापना होती है जो वाम–राज्य–दबाब बनाम दक्षिणपंथ–बाजार–स्वतंत्रता में अनुवादित होती है। पहला अनुक्रम खतरे के रूप में "समानता" का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा स्वतंत्रता की अवधारणा को "राज्य की अनुपस्थिति" के रूप में पुनः प्रकट करता है।

दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद के निर्माण में दूसरा क्षण इसके सभी संस्करणों में अतिउदारवाद और कट्टरपंथी ईसाई धर्म के बीच सुविधा का विवाह है। राज्य पर हमला एक सामान्य बात है, क्योंकि यह "स्वतंत्रता के दायरे को सीमित करता है"। यह सार्वजनिक हस्तक्षेप के माध्यम से, निजी शिक्षा में भी पितृसत्तात्मक अधिकार को भी कम करता है। अतिउदारवाद और नव–पेंटेकोस्टल गिरिजाघरों का बचाव करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के मध्य गठबंधन अर्जन्टीना और ब्राजील में सामाजिक नीतियों और अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप, "लैंगिक विचारधारा" की निंदा और विद्यालयों में "शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के मतारोपण" के आरोप के मिश्रण में अनुवादित हुआ।

ब्राजील की समाजशास्त्री कैमिला रोचा के अनुसार, घृणा के व्यक्तिपरक शासन की स्थापना में सफलता, जो विश्लेषण और लोकतांत्रिक संवाद की किसी भी संभावना को रोकती है, नए तकनीकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग, प्रभुत्ववादी मीडिया को दी जाने वाली बढ़ती स्पेस और एनजीओस एवं राजनैतिक दलों जैसे पारंपरिक राजनैतिक संगठनों की घुसपैठ, के द्वारा समझा जा सकता है। इस प्रकार, दोनों देशों में लोकतंत्र की वापसी (1983 में अर्जेंटीना, 1986 में ब्राज़ील) के द्वारा पराजित संघर्षों के खिलाफ आम सहमति बन गई थी : मानवाधिकारों की लड़ाई और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष और यह सर्वसम्मति इन समाजों को स्वैच्छिकता, झूठे पद, भ्रामक सरलीकरण, और अंतहीन "नकली समाचार" की उच्च खुराक के साथ बस गई। ■

1. क्रमशः 13 सितम्बर एवं 8 नवम्बर 2012; 18 अप्रेल, 8 अगस्त एवं 13 नवम्बर, 2013 और 8 फरवरी, 2014.

सभी पत्राचार
रामिरो कार्लोस हम्बर्टो कजियनो ब्लांको को
<ramirocaggianob@gmail.com> पर
नतालिया टेरेसा बर्टी को
<rnatalia.berti@urosario.edu.co> पर
प्रेषित करें।

> पोलैंड में एक नई प्रतिसंस्कृति के रूप में कट्टरपंथी राष्ट्रवाद

जस्टिना कज्टा, व्रोकला विश्वविद्यालय, पोलैंड द्वारा

राष्ट्रवादी ताकतों द्वारा वारसॉ, पोलैंड में आयोजित स्वतन्त्रता दिवस मार्च, 2011. विकीपीडिया, क्रियेटिव कामन्स।

राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी लोकलुभावनवादी दलों के लिए बढ़ता समर्थन हाल के वर्षों में कई देशों में समाजशास्त्रियों और लोकतांत्रिक नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय रहा है। पोलैंड में 2015 से कट्टरपंथी राष्ट्रवादी संगठन अधिक दिखाई दे रहे हैं जब से दक्षिणपंथी रूढ़िवादी लॉ एण्ड जस्टिस (पीआईएस) पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है। राष्ट्रवादी प्रवचनों में इसी प्रकार की वृद्धि समूचे यूरोप के देशों एवं अन्यत्र भी देखी जा सकती है, जहां लोकवादी कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां प्रवास और सम्प्रभुता जैसे मुद्दों पर संगठित कर वोट आकर्षित करती हैं।

वर्तमान समय में पोलैंड में कट्टरपंथी राष्ट्रवाद किसके लिए खड़ा है? "ग्रेट पोलैंड" के लिए लड़ने का अर्थ क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैंने पोलैंड में राष्ट्रवादी संगठनों के सदस्यों के साथ शोध किया। संगठन तक उनके जीवन पथ के साथ उनके उद्देश्यों और विश्वदृष्टि को ट्रेस करने के लिए मैंने जीवन संबंधी कथात्मक साक्षात्कार आयोजित किये।

उन तरीकों को देखते हुए जिनसे राष्ट्रवादी स्वयं को और अपनी गतिविधियों का वर्णन करते हैं, हम चार मुख्य विचारणीय श्रेणियां देख सकते हैं। प्रथम, वे स्वयं को पोलिश इतिहास को जानने और इसके सही राजनीतिक संस्करण को प्रोत्साहित करने वाली देशभक्तों की नई पीढ़ी के शिक्षक के रूप में देखते हैं। द्वितीय, वे परम्परा और कैथोलिक मूल्यों पर आधारित पोलिश पहचान के रक्षक/(पुनः) सृजक हैं। तीसरा, राष्ट्रवादी व्यवस्था विरोधी कार्यकर्ता हैं जो व्यापक रूप से इयू, राजनैतिक प्रतिष्ठान, 1989 के बाद की राजनीति और उदार मीडिया के रूप में समझी जाने वाली "व्यवस्था" का विरोध करते हैं। चौथा, वे स्वयं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से संलग्न नागरिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो पोलिश समाज में बहुमत की तुलना में संभावित खतरों के बारे में जागरूक हैं और परवाह करते हैं।

सांगठनिक वेबसाइटों पर प्रकाशित उनके आख्यानों और सामग्रियों के विश्लेषण के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि पोलैंड में समकालीन राष्टवादी आंदोलन एक प्रतिवादी उत्तर आधुनिक सामाजिक आंदोलन है जो उदारवाद का प्रतिरोध करता है और परम्परा की तरफ झुकता है। इसे एक विशेष प्रकार की प्रतिसंस्कृतिः उदारवाद–विरोधी (उदार–वामपंथ विमर्श और राजनीति की अनुभूत प्रभुत्व के आधार पर), शासन–विरोधी, इयू विरोधी, विजातीयता विरोधी के रूप में देखा जा

>>

सकता है। 1960 के दशक की प्रतिसंस्कृति जहां प्रगतिशील नारों पर आधारित थी, अब जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं वह अतीत की तरफ (असंभव) परिवर्तन है जिसकी अब तक हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कल्पना करना कठिन है। इस प्रतिसंस्कृति को यह तथ्य और अधिक अजीब बनाता है, कि सरकार (पीआईएस) इसका भाग प्रतीत होती है। पारम्परिक व्यवस्था, जिसके पास वह लौटना चाहती है, की अवधि की कड़ाई से परिभाषित करने की असफलता एक अन्य समस्या है। अतीत एक विशिष्ट संदर्भ बिन्दु की बजाय एक तरह के अमूर्त अवधारणा के रूप में कार्य करता है। समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन भी व्यवस्था–विरोधी आंदोलन हैं जो राजनीतिक वर्ग को और 1989 के बाद के वास्तविक, गहन रूपांतरण के अभाव (जिसमें वि–समुदायीकरण का अभाव और राजनीतिक कुलीन का राष्ट्रीय कुलीन वर्ग में आसान संक्रमण सम्मिलित है) को चुनौती देता है। आंदोलन के प्रतिभागी अर्थशास्त्र के बजाय संस्कृति, पहचान और राजनीति से जुड़े होते हैं। वे (1) यूरोपीय सभ्यता और पोलिशता की नींव का निर्माण करने वाले मूल्यों (राष्ट्र, धर्म, पारम्परिक परिवार, इतिहास) के लिए खतरे की भावना; (2) यह विश्वास कि राजनीतिक परिदृश्य पाखण्ड से भरा है; और (3) यह विश्वास के पालिश राष्ट्र की सम्प्रभुता सीमित है, को साझा करते हैं।

यथार्थ को स्पष्ट द्विभाजन के संदर्भ में देखा जाता है : सबसे सामान्य स्तर पर, दुनिया "अच्छे" और "दुष्ट" में विभाजित है (तालिका 1 देखें)। "अच्छे" के पक्ष में संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है : यूरोपीय सभ्यता, धर्म (ईसाई धर्म), राष्ट्र और परिवार। मूल्यों को परम्परा, समुदाय एवं नैतिक व्यवस्था के संदर्भ में वर्णित किया गया है। उन्हें मूल, प्राकृतिक, शाश्वत और इसलिए वास्तविक माना गया है। इसके अतिरिक्त, हम दो श्रेणियों के अविभाज्य जोड़ों को देख सकते हैं : (1) पोलिश राष्ट्र एवं कैथेलिक विश्वास और (2) यूरोपीय सभ्यता एंव ईसाई धर्म जो पोलिश राष्ट्रवाद में धर्म की केन्द्रीयता को दर्शाते हैं। "दुष्ट" के पक्ष में उदारवाद हावी है जो पारम्परिक विश्वदृष्टि के विरोधाभास के रूप में देखा जाता है और जो (अन्य के साथ) यूरोपीय संघ के साथ पहचाना जाता है। भौतिकवाद, सापेक्षवाद और समतावाद के साथ उदारवाद पूर्व व्यवस्था को नष्ट करता है और समुदाय के विघटन को प्रेरित करता है। "अच्छी" श्रेणियों के विपरीत "दुष्ट" को गढ़ा जाता है और बाहरी शक्तियों/समूहों द्वारा "मजबूत" किया जाता है। ऐसे यथार्थ में राजनीतिक वर्ग, यूरोपीय संघ, समलैंगिक एवं शरणार्थी मुख्य शत्रु बन जाते हैं। वे उन विशेषताओं और घटनाओं को मूर्त रूप देंगे जिन्हें हानिकारक माना जाता है क्योंकि वे एक सजातीय, सामंजस्यपूर्ण और सम्प्रभु राष्ट्र की दृष्टि को जोखिम में डालते हैं।

कट्टरपंथी राष्ट्रवाद दो मुख्य भावनाओं पर आधारित है : अनिश्चितता और गर्व। राष्ट्रीय, यूरोपीय और वैश्विक संदर्भों में चल रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, अनिश्चितता एक आम और साझी भावना है और अपने आप में एक राष्ट्रवादी बनने के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं है। यद्यपि, कट्टरपंथी राष्ट्रवादी विमर्श जो दुनिया की द्विअर्थी दृष्टि से जुड़ा है, रोजमर्रा की समस्याओं, जिसमें एक अच्छी नौकरी,

सारणी 1: राष्ट्रवादी आंदोलनों के भाषणों में यथार्थ के द्वंद्वात्मक दृष्टि

अच्छाई	*दुष्टता*
परम्परा, समुदाय एवं व्यवस्था	उदारवाद, अहंता एंव अघःपतन
यूरोपीयन सभ्यता (वास्तविक, अनन्त, जड़ परम्पराएं)	*उदार लोकतंत्र* (शासन के रूप में इयू, अधिनायकवाद, शत्रुता, विचित्रता, झूठ, खतरा)
अनन्त ईसाई मूल्य (कैथोलिक विश्वास, नैतिकता का स्रोत, सहजता)	*मानवाधिकार की प्रबोधन विचारधारा एवं सापेक्षवाद* (कृत्रिमता, वस्तुनिष्ठ सच का अभाव)
राष्ट्रीय समुदाय (जैविक पूर्णता, पदानुक्रम, स्वतन्त्रता, संप्रभुता, व्यवस्था)	*विश्ववादी अराजकता एवं समतावाद* (भौतिकवाद, मिथ्याज्ञान/आविष्कृत समतावाद, समुदाय और व्यवस्था का विघटन)
पारंपरिक परिवार (स्वास्थ्य, समुदाय)	*सम्बन्धों का उदार/वामपंथी मॉडल* (राजनेता, मीडिया, नारीवादी, समलैंगिक लॉबी, रूग्णता, पतन, हानिकारिता)

स्रोतः आल–पोलिश यूथ, नेशनल री बर्थ ऑफ पोलैंड एवं 2011-15 में नेशनल रेडिकल केम्प के 30 प्रतिनिधियों के साथ जीवनी सम्बन्धी कथात्मक साक्षात्कारों का विश्लेषण एवं उनकी आधिकारिक संगठनात्मक वेबसाइटों पर प्रकाशित सामग्री।

>>

2015 में वारसॉ, पोलैंड में राष्ट्रवादी ताकतों द्वारा आयोजित स्वतन्त्रता दिवस मार्च।
पी. ड्रेबिक/फ्लिकर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

आवास और जीवन स्तर को बनाये रखना सम्मिलित है, के उत्तर के रूप में प्रकट हो सकता है। खतरनाक शरणार्थियों द्वारा अपनी संस्कृति को थोपने और सामाजिक आवास और नौकरियों पर कब्जा करने; यौन अल्पसंख्यकों द्वारा बच्चों को प्रताडित करना; अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा पोलिश कामगारों का शोषण; और पोलिश परम्पराओं और मूल्यों पर जानबूझ कर हमला करने वाले उदारवादियों के बारे में कहानियों का पोलिश समाज के कुछ भागों द्वारा स्वागत किया जाता है। ऐसे विमर्श सरल उत्तर और ठोस संदर्भ बिन्दु प्रस्तुत करते हैं जो अनिश्चितता के बोझ से निपटने के लिए उसे कल्पित शत्रुओं के प्रति वितृष्णा में परिवर्तित करते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय गौरव के बारे में भी है : एक भावना जो दुनिया में पोलैंड की अर्द्ध–परिधीय स्थिति के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में प्रकट होती है। इसी तरह, लॉ एंड जस्टिस मतदाताओं पर मैकीज ग्डुला के शोध ने दर्शाया, कट्टरपंथी राष्ट्रवाद पोलैंड एवं "राइजिंग फ्रॉम द नीस" के प्रतीकात्मक अर्थ को खोजने का एक तरीका है। दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने और एक बेहतर ऐतिहासिक रूप से चेतन एवं स्थिर–राष्ट्रवाद के निर्माण करने की सशक्त आवश्यकता है।

क्या पोलिश समाज पर राष्ट्रवादी प्रतिसंस्कृति की लहर हावी रहेगी? एक तरफ, यह कहा जा सकता है कि कट्टरपंथी राष्ट्रवाद जल्द ही अपना समर्थन नहीं खोने वाला है और इसका अनुमान लगाना काफी कठिन है कि किस प्रकार का अन्य विमर्श इसे प्रतिस्थापित कर सकता है और आसानी से समकालीन दुनिया की जटिलता की व्याख्या कर सकता है। इससे अधिक, राष्ट्रवादी संगठनों ने पोलिश सरकार के साथ स्वतंत्रता दिवस मार्च के दौरान 11 नवम्बर 2018 को मार्च किया जो दिखाता है कि राजनीतिक अवसर संरचना उनके विकास के लिए अनुकूल है। दूसरी तरफ, कम अनुकूल राजनीतिक संदर्भ के बावजूद, विपक्षी, उदार और वामपंथी विश्वदृष्टि के प्रतिनिधि पोलिश समाज में अभी भी ध्यान देने योग्य और सक्रिय हैं। उनकी निरन्तर प्रासंगिकता के हालिया संकेतों में से एक स्थानीय चुनावों के परिणाम है : यद्यपि पीआईए को सामान्य तौर पर क्षेत्रीय सरकारों में सर्वाधिक सीटें मिली, पोलैंड के बड़े शहरों के निवासियों ने अधिक उदार उम्मीदवारों को चुना। अगले कुछ वर्षों में हम कट्टरवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा सार्वजनिक विमार्श को आगे बढ़ाने की बजाय सांस्कृति विमर्श के मध्य तनाव और संघर्ष के बढ़ने की अपेक्षा कर सकते हैं। ■

सभी पत्राचार जस्टिना कज्टा को
<juskajta@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> मैरी जहोदा से प्रेरणा लेना

जोहान बाकर, जोहान्स केपलर विश्वविद्यालय लिंज, ऑस्ट्रिया, **जूलिया हॉफमैन,** चेम्बर ऑफ लेबर वियना, ऑस्ट्रिया एवं **जॉर्ज हुबमैन**, जहोदा बऊर इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रिया द्वारा

1937 में मेरी जहोदा। क्रेडिट : एजीएसओ (ऑस्ट्रिया में समाजशास्त्र के इतिहास के लिए लेखागार)।

2017 में, वर्तमान लेख के लेखक उस वक्त तक लगभग अज्ञात डाक्टरेट थीसिस (प्रसिद्ध आस्ट्रियाई समाज वैज्ञानिक मैरी जहोदा की) के संपादन, वित्तपोषण एवं प्रस्तुतिकरण में व्यस्त थे। मैरी ने अपना शोध 1931 के अंत में कार्ल एवं शालेर्ट बुहलर के निर्देशन में पूर्ण किया। 1932 में वियना विश्वविद्यालय ने इस शोध को मंजूरी दी। शोध ग्रंथ तथाकथित वर्सोर्गुगशूसरिन वियना (जो गरीब एवं बीमार व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का वृद्धाश्रम था) के निवासियों के साथ 52 गुणात्मक साक्षात्कारों पर आधारित था। यह कामकाजी वर्ग के जीवन संबंधी सूचना का उपयोग करने वाला पहला अनुभवजन्य अध्ययन था। साक्षात्कार एवं शोध ग्रंथ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध एवं बीसवी शताब्दी के प्रथम दशकों में श्रमिक वर्ग की दमनकारी जीवन स्तर की प्रभावी छवि पेश करता है।

इसके साथ ही, जहोदा बेहतर रूप से विख्यात प्रसिद्ध अध्ययन मारिएन्थलः द सोश्योग्राफी ऑफ एन एनएम्पलोइड कम्यूनिटी में संलग्न थी जिसे उन्होंने पॉल लजारसफेल्ड एवं हेन्स जेसल के साथ मिलकर लिखा था। उन्होंने 1932 की गर्मियों के दौरान इस रिपोर्ट के मुख्य भाग को लिखा।

1937 में आस्ट्रो–फासीवादी साम्राज्य ने कुछ दिनों के नोटिस पर उन्हें ऑस्ट्रिया छोड़ने पर मजबूर किया। उनके बलात निकास के पहले उन्हें बन्दी बना लिया था। आस्ट्रो फासीवादी शासन ने 1934 से सामाजिक प्रजातांत्रिक आन्दोलन में उनकी संलग्नता को प्रतिबंधित कर दिया था। केवल अंतर्राष्ट्रीय दखल से ही वो वहां से मुक्त हो पायी।

जहोदा सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन गयी, जहां वे कई व्यवहारिक शोध प्रोजक्ट में शामिल रही। इसमें एक अध्ययन, उच्च बेरोजगारी वाले वेल्श खनन क्षेत्र की निर्वाह उत्पादन योजना पर था। 1945 में, संयुक्त राज्य अमरीका में उन्होंने अमेरिकन यहूदी कमेटी में एक स्थान प्राप्त किया, जहां उन्होंने कई आनुभाविक अध्ययन पूर्ण किये। 1947 के अन्त में, वे कोलम्बिया विश्वविद्यालय की ब्यूरो ऑफ एपलाइड सोशल रिसर्च में गयी एवं राबर्ट मर्टन के साथ फलकारी कार्य प्रारम्भ किया। 1949 में, वो सह आचार्य बन गयी एवं 1953 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में सामाजिक मनोविज्ञान की पूर्ण प्रोफेसर बन गयी। 1958 में, वो निजी कारणों से ग्रेट ब्रिटेन लौट गयी जहां वे ब्रूनल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गयी; 1965 में उन्होंने ससेक्स विश्वविद्यालय में पूर्ण प्रोफेसर का संस्थापक पद स्वीकार किया। जहोदा की मृत्यु 2001 में यूनाइटेड किंगडम में हुई। उनके गृहदेश ऑस्ट्रिया में उनकी असाधारण उपलब्धियों को काफी देर से, 1980 के उत्तरार्द्ध में सम्मानित किया गया। वे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त ऑस्ट्रिया लौटना चाहती थी परन्तु उन्हें कोई कार्य प्रस्ताव नहीं मिले।

मैरी जहोदा 250 से अधिक प्रकाशनों की लेखिका हैं, जो काफी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं : रोजगार एवं बेरोजगारी, विशेष रूप से यहूदी विरोधी; अनुपालन एवं सत्तावादी; जन स्वास्थ्य, शोध तकनीक एवं पद्धतिशास्त्र से संबंधित अभिवृत्ति और अभिवृत्तियों में परिवर्तन एवं मनो–विश्लेषण प्रमुख शोध पत्रिकाओं में उनकी समीक्षाओं की बड़ी संख्या विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट रूचि को दर्शाती है।

> मैरी जहोदा से हम क्या सीख सकते हैं?

समाज वैज्ञानिक एवं राजनीतिक रूप से संलग्न नागरिकों के रूप में, हम उनके वैज्ञानिक कार्य एवं जीवन वृत्तान्त से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, लेखक के रूप में, हम अपनी भिन्न पृष्ठभूमि का उल्लेख करना चाहेंगे। हम में से एक विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पूर्णकालिक प्रोफेसर है, दूसरा थिंक टैंक के साथ संलग्न है एवं तीसरा ऑस्ट्रियन चेम्बर ऑफ लेबर में पदाधिकारी है।

>>

हम अलग–अलग उम्र एवं जेंडर के हैं। हम अपनी पृष्ठभूमि के कुछ भाग साझा करते हैं। हम तीनों ने एक ही विश्वविद्यालय में समाजविज्ञान (समाजशास्त्र एवं समाज–अर्थशास्त्र) का अध्ययन किया है। हम सभी सामाजिक समस्याओं को हल करने एवं सामाजिक असमानताओं का कम करने में मदद करना चाहते हैं।

जहोदा के वैज्ञानिक कार्य एवं बायोग्राफी से पहला निष्कर्ष जो हम निकाल सकते है वो यह कि हमें अपने काम को लोगों के वास्तविक जीवन की समस्याओं पर केन्द्रित करना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि लोगों की सामाजिक समस्याओं से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा जाये। जहोदा की जीवनी कई अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार की संलग्नता शोध को प्रोत्साहित करती है जैसा जहोदा ने अपने पद्धतिशास्त्रीय कार्य में जोर दिया एवं सामाजिक घटनाओं की बेहतर समझ के लिए अनुमति देती है और संभवत यह समाधान ढूंढने का भी नेतृत्व कर सकती है। जहोदा ने इस बात पर जोर दिया कि अमूर्त में विकसित वैज्ञानिक प्रश्न सदैव सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करने एवं हल करने के लिये उपयोगी नहीं होते हैं। यह दलील न तो नई है और न ही जहोदा के लिए विशिष्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसका उत्तर देना आसान नहीं है। दूसरा, हमने जहोदा से सीखा कि सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक असमानताओं के विश्लेषण के लिये कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में रूचि एवं विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के सहकर्मियों के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है। अन्तः विषयी प्रतिस्पर्धा बेकार है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक सीमाओं में विभाजित करना संभव नहीं है। मैरी जहोदा के कार्य में कोई वैज्ञानिक सीमायें नहीं हैं, विशेष रूप से समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के मध्य उनके अंत विषयी फोकस के साथ। उनका अ–अवव्याख्यावाद सामाजिक मनोविज्ञान की संकल्पना सामाजिक यथार्थ का पता लगाने में फलकारी है। यह सामाजिक संरचना एवं व्यक्तित्व के मध्य संबंध स्थापित करती है (सामाजिक संरचना समाजशास्त्र से एवं व्यक्तित्व मनोविज्ञान से)। अ–अवव्याख्यावादी सामाजिक मनोविज्ञान का एक कार्य यह विश्लेषण करना है कि सामाजिक संस्था कौन से अनुभव प्रदान करती है, किस प्रकार उनकी व्याख्या लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है एवं इसके विपरीत रोजगार के पांच अप्रकट प्रकार्यों की जहोदा की संकल्पना आज भी इस संबंध का बेहतरीन उदाहरण है। यह संकल्पना मानती है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में रोजगार विशेष प्रकार के अनुभवों को प्रदान करता है जो मानव की मूल (आधारभूत) आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रोजगार (1) दिवस को व्यवस्थित करता है (2) लोगों को सक्रिय करता है (3) अपने निजी परिवार के परे लोगों के सामाजिक क्षितिज को बढ़ाता है (4) उच्च सामूहिक प्रयोजनों में योगदान देता है (5) सामाजिक पहचान एवं प्रस्थिति प्रदान करता है।

यह पांच अप्रकट प्रकार्य एवं मूल मानव आवश्यकताओं से इनके संबंध आज भी सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिये आवश्यक और उपयोगी है, विशेषतः पश्चिम देशों में। हमें अपने आप से बार–बार यह पूछना चाहिये कि किस हद तक एवं लोगों के किन समूहों के लिये कुछ सामाजिक विकास इन बुनियादी मानव आवश्यकताओं का उल्लंघन है। जहोदा के पद्धतिय सिद्धान्तों के अनुसार, इस प्रकार का विश्लेषण लोगों के रोजमर्रा के जीवन अनुभवों एवं उनकी मानव आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। इसको याद रखने से हमारा विश्लेषण अधिक जीवंत होगा एवं हमारे निष्कर्ष अधिक ठोस होंगे। (ग्लोबल डायलाग 8.2 में थिंक टैंक के बारे में चर्चा देखिये) हमारे परिणामों को वृहद दर्शक मिलेगें एवं जन चर्चा को प्रोत्साहित करेंगे (सब लोग इससे सहमत नहीं होंगे)।

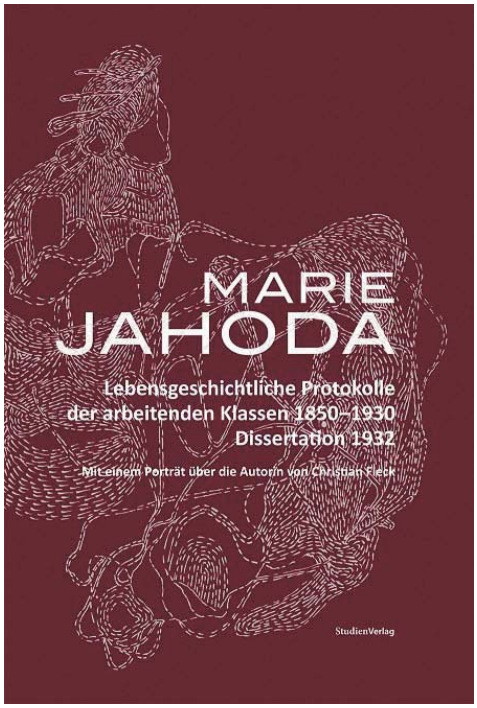

स्टूडियन वर्लाग द्वारा हाल ही 2017 में प्रकाशित मेरी जहोदा की 1932 के शोध प्रबंध की पुस्तक का आवरण : मेरी जहोदा द्वारा श्रमिक वर्गों की जीवन ऐतिहासिक रिपोर्ट, 1850-1930, जोहान बाकर, वालट्रुड कन्नोनियर–फिनस्टर, एवं मीनराड जिग्लर द्वारा संपादित।

अंततः हमारे विश्लेषण को मानवता के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। हमारी राय में, समाज विज्ञानों ने वर्तमान में, मुख्य रूप से इस प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित किया है कि समाज, मानवता के विकास को क्यों अवरोधित करता है। यद्यपि ये विश्लेषण, विभिन्न एवं गंभीर सामाजिक समस्याओं को जिनका हमारे वैश्विक समाज सामना करते है को देखते हुए अत्यावश्यक है लेकिन वे अक्सर नकारात्मक या निराशावादी निदान की तरफ ले जाते है। यह नकारात्मक दृष्टि समाज वैज्ञानिक के रूप में हमारी पहचान का एक हिस्सा बन गयी है। जहोदा का अनुसरण करते हुए एक तरफ हमें वास्तविक जीवन की समस्याओं को हमारे वैज्ञानिक शोध के साथ ज्यादा नजदीकी से जोड़ना चाहिये एवं दूसरी और अधिक सकारात्मक प्रवृति को विकसित करना चाहिये। यह हमारी वैज्ञानिक एवं राजनीतिक विमर्श में अकादमिक विशेषज्ञता की भूमिका को ताकतवर बनाने में मदद करेगा। यह ऐसे वक्त में होगा जब नव–उदारवादी चिंतन के प्रभाव में बढ़ोतरी हो रही हो। हमारे विश्लेषण को आंशिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। हमारी मानवता के विकास के लिये किन सामाजिक परिस्थितियों की पूर्ति होनी चाहिये? ■

सभी पत्राचार जोहान बेकर को <johann.bacher@jku.at> पर जूलिया हॉफमैन को <Julia.HOFMANN@akwien.at> पर एवं जॉर्ज हबमैन को <georg.hubmann@jbi.or.at> पर प्रेषित करें।

> पुर्तगाल में श्रम संबंध एवं सामाजिक संवाद

एलिसियो एस्टांक, कोइंब्रा विश्वविद्यालय, पुर्तगाल एवं आईएसए की श्रम आन्दोलनों पर शोध समिति (आरसी 44) एवं सामाजिक वर्ग एवं सामाजिक आंदोलन (आरसी 47) के सदस्य एवं
एंटोलियो केसीमीरो फरेरा, कोइंब्रा विश्वविद्यालय, पुर्तगाल

25 अप्रेल 1974 की कारनेशन क्रांति को चित्रित करते लिस्बन की सड़कों पर भित्ति चित्र।
फोटो : किम्बल यंग, क्रिएटिव कामन्स।

पुर्तगाल एक अर्द्ध सीमान्त देश है, जिसने 1974 में प्रजातांत्रिक परिवत्रन का अनुभव किया। यह दौर एक लम्बी अधिनायकत्व के दौर (1926 से शुरू) के उपरान्त आया। अधिनायकत्व "एस्टाडो नोवो" (नया राज्य) 1933 के संविधान द्वारा स्थापित किया गया। इसने फासीवादी निगमवाद की नींव रखी जिसने व्यापार संघ के ऊपर राज्य नियंत्रण को वैध किया एवं श्रमिकों के हिंसक दमन को बढ़ाया।

48 वर्षों के अधिनायकवाद के दौरान श्रमिक वर्ग का प्रतिरोध विरल और छुटपुट था। सिर्फ 1960 के दशक के अन्त में, कुछ कोर्पोरेट संघों में संगठित प्रतिरोध दिखाई पड़ा। यह नगरीकरण, तटीय प्रदेशों पर जनसंख्या केन्द्रीकरण, कुछ जन सेवाओं के विकास साथ ही अर्थव्यवस्था के तृतीयक सेक्टर के विकास का परिणाम था, जिसने श्रमिकों के मध्य नवीन सह गतिकी को जगह दी (यद्यपि अभी भी गुप्त रूप से)। इस संदर्भ में ट्रेड यूनियन कॉनफीडेशन जिसका प्रभुत्व आज भी है (इंटरसिंडिकल नेसिओनेल, जिसे आज सीजीटीपी जनरल कान्फीडरेशन ऑफ द पोस्ब्यूगीस वर्कस कहा जाता है) 1970 में उभरा। हालांकि, इस अवधि के दौरान (1960 के दशक के उत्तरार्द्ध से 25 अप्रेल 1974 के आंदोलन तक), अर्थव्यवस्था के सापेक्षिक खुलने एवं श्रम सेक्टर के विकास के बावजूद, पुर्तगाल मुख्यतः एक ग्रामीण देश ही रहा। उद्दीपक उद्योग राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था द्वारा तैयार सस्ते श्रम पर आधारित था जो कि दमनकारी एवं सुरक्षित साम्राज्य में थी जहां श्रमिकों, संघों एवं समाज पर निगरानी रखी जाती थी।

कारनेशन आन्दोलन (25 अप्रेल 1974) ने ही वर्तमान श्रम संबंधों एवं श्रम अधिकारों की व्यवस्था के उद्भव के लिये परिस्थितियों का निर्माण किया। इसके बाद से ही, पुर्तगाली समाज में कोई सामाजिक संवाद एवं श्रम कानून पर बोल सकता था। इसके अलावा, उस दौर के सामाजिक एवं लोकप्रिय आंदोलनों (1947-45) के ताकतवर क्रांतिकारी जोश के कारण पुर्तगाल एक ऐसा विरल पश्चिमी देश बना जिसने समाजवाद के प्रोजेक्ट को खुले रूप में गले लगाया, जैसा कि 1976 के संविधान में मान्यता प्राप्त है। हालांकि उस संघर्षकारी एवं क्रांतिकारी दौर ने देश पर (अच्छे एवं बुरे के लिये) गहरी छाप छोड़ी। इसने विरोधी सामाजिक प्रारूपों के मध्य संरचनात्मक दरार को प्रस्तुत किया। इसे राजनीतिक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यवस्था विरोधी विचारधाराओं पीसीपी (कम्यूनिस्ट पार्टी) एंव सूदूर वाम एवं सामाजिक लोकतांत्रिक या उदारवादी विचारधाराओं–पीएस (समाजवादी पार्टी) एवं पीएसडी

>>

(सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी) के मध्य विभाजन के रूप में अनुवादित किया गया। यह संघर्ष श्रमिक संघ क्षेत्र में, एक तरफ सीजीटीपी (कम्यूनिस्ट प्रभावी "वर्ग आधारित" श्रम संघ) एवं दूसरी तरफ जनरल यूनियन ऑफ वर्कर्स (यूजीटी–सुधार एवं संवाद से संचालित व्यापार संघ) जिसकी स्थापना 1978 में हुयी थी के मध्य था।

नये संविधान के तहत स्थापित श्रम कानून ने विशेष रूप से प्रारम्भिक चरण में क्रांतिकारी दौर के तीव्र वर्ग संघर्ष के प्रभाव को प्रतिबिंबित किया। संविधान ने वृहद सामाजिक स्तर पर त्रिपक्षीय संरचना की व्यवस्था की : यह 1984 में स्थापित सामाजिक संवाद की स्थायी समिति (सीपीसीएस) थी जिसको बाद में 1991 में इकॉनोमिक एंड सोशल काऊंसिल (सीईएस) ने बदल दिया। व्यवहारिक रूप से सामाजिक संवाद एवं श्रम संबंधों के प्रारूप, विभिन्न राजनीतिक संयोगों एवं सामाजिक साझेदारों के मध्य शक्ति संबंधों की गतिशीलता के साथ आर्थिक एवं सामाजिक संकेतकों के उद्भव के अनुसार झूलते रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में, संकटकालीन दौर और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावों ने विनियमन, लचीलाकरण और श्रम के विभाजन के रूझानों का अनुसरण करते हुए सामाजिक नीतियों को बाधित करने वाले कई वैधानिक परिवर्तनों को ट्रिगर किया है।

2008 के हाल के आर्थिक–वित्तीय विपदा का पुर्तगाल पर प्रभाव पड़ा विशेषतः खैरात कार्यक्रम (2011-14) के दौरान। उस दौर में, पुर्तगाल में "अपवाद की स्थिति" उभरी। ट्रोइका यूरोपीय आयोग, यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक, एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मित्तव्यत्तता उपायों का लागू करना एवं पूर्व दक्षिणपंथी सरकार (पूर्व प्रधानमंत्री पासोस कोल्हो के नेतृत्व में पीएसडी/सीडीएस) के द्वारा उसका उत्साहपूर्वक लागू किये जाने से सामाजिक असमानताएं एवं अपवर्जन तीव्र हुए। ऐसा सामाजिक तनाव के संदर्भ में हुआ जिसमें हड़ताल एवं प्रतिरोध के चक्र समाहित है, जो सामाजिक एवं श्रम आन्दोलनों द्वारा पोषित होते हैं।

इस मित्तव्यत्ता फ्रेमवर्क में सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक और न्यायिक संस्थावाद सम्मिलित था, जिसका उद्देश्य बजट घाटे की पूर्ति एवं सामाजिक संवाद के विनाश के द्वारा बाजार को शांत एवं स्थायित्व प्रदान करना था। मित्तव्यत्तता उपाय एवं नवउदारवादी "सुधार" एजेंडा श्रम लागत को कम करने एवं पदच्युति के लिए मुआवजा लचीले कार्य समय एवं सामूहिक सौदेबाजी सीमित करने के अभियानों के साथ अभिसारित होता है। विशेष रूप से, कामगार वर्ग को मिलने वाले लाभों में कटौती करने के लिए प्रतीकात्मक विधायी परिवर्तनों की एक श्रृंखला प्रारम्भ की गई। कार्य परिषदों और कंपनी यूनियनों दोनों की भूमिकाओं को विशेषाधिकार देते हुए संविधान में पूर्व दृष्ट श्रम संघ संरचनाओं की भूमिका को भी सीमित किया गया।

साथ ही, श्रम संबंधों के विनियमन के विशेषाधिकार प्राप्त स्वरूप–सामूहिक सौदेबाजी–को श्रम अनुबंध एवं सामूहिक संधियों के कारण तीव्र अवरोधों का सामना करना पड़ा। ये सौदेबाजी समय पर निर्भर रहते हुये संधि के साथ या बिना वस्तुनिष्ठता के साथ नियोक्ताओं की तरफदारी करते हैं। मित्तव्यत्तता की अवधि के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति श्रमिकों और नियोक्ताओं के मध्य शक्ति विषमताओं में वृद्धि के माध्यम से इस प्रकार के सामाजिक संवाद की नाकाबंदी में परिलक्षित होती है। दूसरी तरफ, वृहद सामाजिक स्तर पर, आर्थिक एवं सामाजिक काउंसिल (सीईएस) ने ट्रोइका के साथ किये गये वादों के दबाब के तहत श्रम संबंध फ्रेमवर्क को पीछे खदेडने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह तथाकथित "संरचनात्मक सुधारों" की अधिक व्यापक प्रक्रिया में हल्के किये मद श्रम कानून की राजनैतिक और न्यायिक पहचान को खोये बिना ऐसे निर्णयों का विरोध नहीं कर सकते थे।

बाजार की कट्टरता की विशेषता वाले मित्तव्यत्तता वृतान्त ने श्रम अधिकारों एवं सामाजिक न्याय की रक्षा करने वाले सामाजिक लोकाचार को प्रतिबिंबित करने वाले किसी भी विधायी एजेंडा को अवरूद्ध करते हुए यथार्थ के वैकल्पिक निदान को अवैधानिक बताया है। सामाजिक संवाद एवं नागरिकता की संस्थाओं एवं संगठनों ने स्वयं को नई मित्तव्यत्तता के वैधकरण में सहयोजित एवं उनके बदलाव के तंत्र के रूप में देखा।

लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया (1974 के अनुसार) के बाद चार कालों की पहचान की जा सकती है : 1970 से 1980 के वर्षों के मध्य वृहद सामाजिक संवाद का विस्तार एवं शून्यीकरण 1990 के दशक में सामाजिक संवाद की वापसी, वैश्वीकरण एवं यूरोपियन एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित; सामाजिक संवाद में संकट के क्षण जो मित्तव्यत्तता उपायों के लागू होने और उसके उपरांत विधायी कठोर सुधारों के साथ संलग्नता से चिह्नित; ओर अंत में वर्तमान क्षण जिसमें समाजवादी पार्टी सरकार, कम्यूनिस्ट पार्टी एवं लेफ्ट ब्लॉक के मध्य संसदीय समझौतों के उपरान्त वार्ता धुरी संसद की तरफ झुकती है। इसके साथ ही वार्ता तंत्र दोनों सामूहिक सौदेबाजी एवं त्रिपक्षीय प्रणाली के महत्व में भी धीरे–धीरे कमी आने लगी।

सारांश में सबसे हालिया ट्रोइका–पश्चात के काल ने सामाजिक संवाद की वापसी के लिए नई शर्ते पेश कर एक नये राजनीतिक समाधान के लिए जगह खोली हे। इस कारण से यह देश यूरोपियन संदर्भ में आज प्रतिचक्र उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है जो विभिन्न वामपंथी राजनीतिक दलों के मध्य गठजोड़ की आश्चर्यजनक व्यवहार्यता को प्रस्तुत करता है। इस नवीन राजनीतिक श्रम विन्यास में, यह सिर्फ एक राजनीतिक पक्षधर अधिवक्ता या सामाजिक विद्रोह आन्दोलन नहीं है अपितु विभिन्न प्रकार के व्यापार संघ कार्यवाही है जिसने गठबंधनों एवं वार्ता प्रक्रियाओं के पक्ष में माहौल बनाने वाले वातावरण के लिये योगदान दिया है। इस हल से उठाये गये संशय एवं जटिलता के बावजूद, पुर्तगाली अनुभव दर्शाता है कि सामाजिक संवाद के भविष्य में राजनैतिक और श्रम क्षेत्रों को सम्मिलित करने वाले सामाजिक कर्ताओं के मध्य नवीन विन्यास को शामिल हैं। यह प्रदर्शित करता है कि हेरफेर के बावजूद आर्थिक–वित्तीय बहाली को प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में जहां संघर्ष एवं वार्ता को अलग नहीं किया जा सकता, सामाजिक नीतियों की बहाली एवं गठबंधन राजनीति के पुनरूद्धार से जोड़ा जा सकता है। ■

सभी पत्राचार एलिसियो एस्टैनक को <elisio.estanque@gmail.com> पर एवं एंटोलियो केसीमीरो फरेरा को <acasimiroferreira@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> वैश्विक संवाद की बंगाली टीम का परिचय

रोकेया अख्तर

आसिफ बिन अली

मो. युनुस अली

अब्दुलाह–हिल–मुहामिन चौधरी

इशरत जहां आईमून

काजी फादिया इकबाल

हबीबुल हक खोंडकर

हसन महमूद

मुस्ताफिजुर रहमान

खैरून नाहर

जुवैल राना

तौफिका सुल्ताना

हेलाल उद्दीन

GLOBAL DIALOGUE

>>

रोकिया अख्तर बांग्लादेश में विकास प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय सलाहकार और पेशवर हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र जेंडर एक्शन प्लान, किशोरों के लिए पोषण एवं खाद्य सुरक्षा के लिये जलवायु परिवर्तन लचीलता हैं। वे ढ़ाका विश्वविद्यालय, बांग्लादेश में पीएचडी की विद्यार्थी हैं। उनका डोक्टोरल शोध ढ़ाका में भाषा, संस्कृति एवं स्कूली शिक्षा पर है। उन्होंने ढ़ाका विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर्स एवं आनर्स किया है।

आसिफ बिन अली इस्टर्न विश्वविद्यालय, ढ़ाका में समाजशास्त्र का अध्यापन करते हैं एवं 'डेली ऑब्जरवर' जो कि बांग्लादेश स्थित अंग्रेजी दैनिक अखबार है, में सहायक संपादक के रूप में कार्य करते हैं। वो 2017 से केन्द्रीय क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च फैलो के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने साऊथ एशियन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत से समाजशास्त्र में स्नात्तकोत्तर किय हैं उनके शोध क्षेत्रों में राष्ट्रवाद, आतंकवाद, पहचान निर्माण, धर्म का समाजशास्त्र एवं प्राकृतिक विपदा का इतिहास सम्मिलित हैं।

मो. यूनस अली ढ़ाका विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में स्नातक के विद्यार्थी हैं। उनके शोध क्षेत्र, जेंडर एवं विकास, जन स्वास्थ्य एवं बाल समाजीकरण है।

अब्दुलाह-हिल-मुहामिन-चौधरी एक गुणात्मक बाजार शोधकर्ता हैं, जो वर्तमान में क्वाटम कन्ज्यूमर सोल्यूशंस में सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ढ़ाका विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर किया है। उनकी शोध रूचि, बांग्लादेश के सामाजिक विचारधारा के संबंध में धार्मिक आख्यानों के बदलते पैटर्न में है।

इशरत जहां आईमून ढ़ाका विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में व्याख्याता हैं। उन्होंने ढ़ाका विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर किया है। उनकी शोध रूचि जेंडर संबंध एवं खाद्य सुरक्षा शासन में है।

काजी फादिया इकबाल ने समाजशास्त्र में स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर की उपाधि पूर्ण कर ली है एवं अभी वे एमफिल डिग्री के लिए अध्ययनरत हैं। वर्तमान में वे एडवोकेसी की निदेशक के रूप में एवं साऊथ एशिया इन्सट्टियूट ऑफ सोश्ल ट्रान्सफारमेशन के नेटवर्किंग विभाग (SAISI) में कार्यरत हैं।

हबीबुल हक खोंडकर पीएचडी (पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय) अबु धाबी, यूएई के जायेद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं एवं सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र पर अन्तर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ की शोध समिति (आरसी 9) के सह–अध्यक्ष हैं। उनके शोध क्षेत्रों में वैश्वीकरण के सिद्धान्त, प्रवासीकरण, राज्य, सिविल सोसाइटी, प्रजातंत्र, राजनीति में मिलिट्री एवं अकाल सम्मिलित हैं। उन्होंने ब्रयान टरनर के साथ ग्लोबलाइजेशन ईस्ट/वेस्ट (सेज, 2010) का सहलेखन किया और गोदान थेरबान के साथ एशिया एवं यूरोप इन ग्लोबलाइजेशनः कान्टीनेन्टस, रीजन्स एवं नेशन्स (ब्रिल 2006) एवं जेन नेवरसेन के साथ 21 सेन्चुरी गलोबलाइजेशनः परस्पेक्टिव फ्रांम द गल्फ (दुबई एवं अबु धाबीः जायद विश्वविद्यालय प्रेस, 2010) का सह–सम्पादन किया है।

हसन महमूद कतर की नार्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में आवासीय सहायक आचार्य हैं। उन्होंने केलीफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एन्जिल्स से समाजशास्त्र में पीएचडी, टोकिया के सोफिया विशविद्यालय से ग्लोबल स्ट्डीज में स्नात्तकोत्तर एवं ढ़ाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश से समाजशास्त्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया है। वे बॉल स्टेट विश्वविद्यालय, यूएसए में समाजशास्त्र विषय में अतिथि अध्यापक रहे हैं। उनके अध्यापन एवं शोध क्षेत्र हैं, सामाजिक सिद्धान्त, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासीकरण एवं विकास, पहचान राजनीति एवं ग्लोबल इथनोग्राफी हैं। करेंट समाजशास्त्र, प्रवास एवं विकास, कन्टेमपरेरी जस्टिमस रिव्यू एवं जर्नल ऑफ सोश्योइकोनॉमिक रिसर्च एंड डवलपमेंट में उनके शोध प्रकाशित हुए हैं।

मुस्ताफिजुर रहमान ढ़ाका विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर के छात्र हैं। उन्हें 2018 में स्नातक में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये स्वर्ण पदक मिल चुका है। उनके शोध क्षेत्र हैं, चिकित्सा समाजशास्त्र एवं जन स्वास्थ्य।

खैरून नाहर सीएस केयर लिमिटेड में स्पीच एवं भाषा थैरेपिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भाषाविज्ञान में बीए (आनर्स) एवं एमए किया है। उन्होंने ढ़ाका विश्वविद्यालय से स्पीच एवं भाषा थैरेपी में समाजविज्ञान में मास्टर्स किया है।

जुवैल राना, इरेस्मुस स्कोलर है, जो ईएसईएसपी स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ, फ्रांस से अपनी स्नातक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके शोध क्षेत्र है, बालकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रदूषण, विषाक्त पदार्थों, एन्डोक्रइन खलल एवं अन्य संबंधित कारकों का प्रभाव। उन्होंने शोध पत्रिकाओं में पर्यावरण स्वास्थ्य, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, हृदय संबंधित समस्याओं, धूम्रपान, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक एवं स्वास्थ्य असमानता, पर शोध पत्र एवं पुस्तक अध्याय प्रकाशित किये हैं। यह प्रकाशन विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में हुये हैं। वे साऊथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस के कार्यकारी संपादक एवं एसएआईएसटी ढ़ाका के सह–संस्थापक हैं।

तौफिका सुल्ताना सस्काचेवान विश्वविद्यालय, कनाडा में समाजशास्त्र में पीएचडी की विद्यार्थी हैं। उनके शोध क्षेत्र हैं, बढ़ती उम्र एवं मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं रूग्णता का समाजशास्त्र, जनसांख्यकी, सामाजिक असमानता, विपदा प्रबंधन एवं कमजोर वर्ग का अध्ययन। कनाडा में पीएचडी शुरू से पहले उन्होंने इस्टर्न विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्यापन किया है। उन्होंने बीआरएसी बांग्लादेश में रिसर्च इवेलुएशन डिविजन (आरईडी) में भी कार्य किया है। वे साऊथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस की सह संपादक एवं एसएआईएसटी ढ़ाका की सह–संपादक हैं।

मो. हेलाल उद्दीन इस्टर्न विश्वविद्यालय, बांग्लादेश में समाजशास्त्र के व्याख्याता हैं। उन्होंने ढ़ाका विश्वविद्यालय से स्नातक एवं मास्टर्स पूर्ण की है। वो साऊथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस के लिये संपादकीय सहायक एवं एसएआईएसटी के सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं नवाचार प्रभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके शोध क्षेत्र हैं, पर्यावरणीय समाजशास्त्र, स्वास्थ्य का समाजशास्त्र एवं उत्तर–आधुनिकतावाद।